कल्पमेधा

हमें उस जीवन की परवाह नहीं करनी चाहिए, जिसकी हमने अपने लिए कल्पना की है, ताकि उसको स्वीकार कर सकें, जो हमारी प्रतीक्षा कर रहा है।

– जोसेफ कैम्पबेल

न्याय का विवेक

इसमें कोई दोराय नहीं कि किसी भी तरह के अन्याय के बाद न्याय के लिए न्यायपालिका ही उम्मीद का ठौर होती है। अदालतों में बैठे न्यायाधीश यह सुनिश्चित करते हैं कि पीड़ित पक्ष के साथ इंसाफ हो। मगर कई बार ऐसे मामले भी चर्चा और चिंता का कारण बने हैं, जिनमें महिलाओं के खिलाफ अपराधों से जुड़े मुकदमों में किसी जज की टिप्पणी या उनके फैसले को न्याय की अवधारणा पर पूर्वाग्रह हावी होने के तौर पर देखा गया। इस क्रम में कानूनी प्रावधानों की व्याख्या करते हुए जो कहा गया, उसमें संवेदनशीलता का अभाव नजर आया। शायद यही वजह है कि पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट को जजों के दृष्टिकोण में जरूरी संवेदनशीलता विकसित करने के लिए अलग से प्रयास करने पर जोर देना पड़ा। शीर्ष अदालत की पीठ ने स्पष्ट रूप से कहा कि न्यायपालिका के सदस्यों के दृष्टिकोण के साथ ही अदालती प्रक्रियाओं में अंतर्निहित संवेदनशीलता और विवेक विकसित करने के लिए कदम उठाने की जरूरत है।

हालांकि समय-समय पर शीर्ष अदालत की ओर से न्यायाधीशों के दृष्टिकोण पर रूढ़िवादी सोच हावी होने से उपजे सवालों से निपटने के लिए कदम उठाए गए हैं। वर्ष 2023 में एक पुस्तिका भी इस उद्देश्य से तैयार की गई थी कि न्यायाधीश पितृसत्तात्मक भाषा को पहचान कर उससे बच सकें। मगर इस सबका कोई ठोस असर सामने नहीं आ सका है। इसी के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने अब राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी को यौन हिंसा और अन्य अपराधों के संदर्भ में न्यायाधीशों तथा न्यायिक प्रक्रिया के भीतर संवेदनशीलता एवं करुणा विकसित करने के उद्देश्य से दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने को कहा है। जाहिर है, शीर्ष अदालत का निर्देश यह सुनिश्चित करने के मकसद से है कि जज महिलाओं के विरुद्ध अपराधों और खासतौर पर यौन हिंसा के मामलों में पूरी संवेदनशीलता के साथ सुनवाई करें, उनके फैसलों पर सामाजिक भेदभाव या पूर्वाग्रहों पर बनी धारणाओं की छाया नहीं दिखे। निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट की इस पहल में एक ऐसी समस्या की पहचान कर उसे रेखांकित किया गया है, जिसकी आमतौर पर अनदेखी की जाती है, लेकिन कई फैसलों पर उसका असर देखा जाता है।

दरअसल, महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा से जुड़े मामलों में कई बार सामाजिक धारणाओं पर पितृसत्तात्मक सोच से संचालित मानसिकता हावी होती है। जबकि अदालतों में न्यायाधीशों से यह उम्मीद की जाती है कि वे इस तरह के पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर कानून की व्याख्या करते हुए समाज में प्रचलित आम मानसिकता, उसके आधार पर बनने वाली धारणाएं और उसमें महिलाओं की वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखेंगे। साथ ही वे मामले में फैसला देते हुए निरपेक्ष रह कर जरूरी संवेदनशीलता और करुणा का सहारा लेंगे। विडंबना यह है कि देश में निचली अदालतों में महिलाओं के खिलाफ होने वाले जघन्य अपराधों और बलात्कार के मामलों में भी कुछ जज सामाजिक हकीकतों की अनदेखी करते हुए कानून के प्रावधानों की व्याख्या इस तरह करते हैं कि उससे आरोप हल्के हो जाते हैं और पीड़ित महिला के न्याय पाने की राह ज्यादा मुश्किल हो जाती है। इसलिए जरूरत है कि न्यायाधीशों के दृष्टिकोण में संवेदना और करुणा विकसित करने के लिए लैंगिक संवेदनशीलता पर केंद्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने के साथ-साथ न्यायपालिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने पर जोर दिया जाए।

बुनियादी चिंता

देश के आठ प्रमुख बुनियादी क्षेत्रों की उत्पादन वृद्धि दर पिछले माह जनवरी में गिरकर चार फीसद पर आ गई, जो समूची अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत नहीं है। इन क्षेत्रों का देश के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक और सकल घरेलू उत्पाद में महत्त्वपूर्ण योगदान है, इसलिए इनकी उत्पादन गति धीमी होने से देश की आर्थिक वृद्धि प्रभावित होती है। इन क्षेत्रों से जुड़े उद्योगों को देश की अर्थव्यवस्था का स्तंभ माना जाता है, जो बुनियादी ढांचे के विकास, रोजगार सृजन और समग्र औद्योगिक वृद्धि को गति देते हैं। पिछले दिनों सरकार की ओर से जारी आंकड़ों ने यह स्पष्ट कर दिया था इस वर्ष की शुरुआत थोक और खुदरा महंगाई में बढ़ोतरी के साथ हुई है। अब बुनियादी क्षेत्रों की वृद्धि दर में गिरावट यह दर्शाती है कि देश की अर्थव्यवस्था को कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि वस्तुओं के उत्पादन में कमी से मांग और आपूर्ति के बीच पैदा होने वाले अंतर की वजह से महंगाई के और बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

गौरतलब है कि देश के आठ प्रमुख बुनियादी क्षेत्र- कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में लगभग चालीस फीसद की हिस्सेदारी रखते हैं। ऐसे में इन क्षेत्रों की वृद्धि दर में गिरावट का समग्र अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ सकता है, इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। सरकार की ओर से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी 2025 में बुनियादी क्षेत्रों की वृद्धि दर 5.1 फीसद और दिसंबर में 4.7 फीसद थी। मगर, इस साल जनवरी में कच्चा तेल एवं प्राकृतिक गैस तथा कोयला एवं सीमेंट क्षेत्र के उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि, उर्वरक, इस्पात और बिजली उत्पादन में थोड़ी वृद्धि ने स्थिति को और कमजोर होने से रोका है। यह विचित्र बात है कि एक ओर निर्यात के जरिए अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के दावे किए जाते हैं, तो दूसरी तरफ बुनियादी क्षेत्रों में उत्पादन की गति धीमी पड़ती जा रही है। सरकार को चाहिए कि इन क्षेत्रों में चुनौतियों से निपटने के लिए कारगर कदम उठाए जाएं।

बुजुर्गों की उपेक्षा और सुरक्षा का सवाल

आज के दौर में बेहतर शिक्षा और अच्छे रोजगार के लिए युवा विदेश या बड़े शहरों में जाकर बस रहे हैं। इस कारण कई बार बुजुर्ग माता-पिता की सुध लेने वाला कोई नहीं होता है। यह पारिवारिक मूल्यों के क्षरण के साथ-साथ कानूनी तौर पर सुरक्षा से जुड़ा मसला भी है।

जगदीप सिंह

भारतीय समाज में परिवार की संरचना और मूल्यों का आधार माता-पिता की देखभाल एवं सम्मान रहा है। मगर आधुनिक समय में वैश्वीकरण, बेहतर शिक्षा और अच्छे रोजगार के लिए युवा विदेश या बड़े शहरों में जाकर बस रहे हैं। यह प्रवास अक्सर परिवारों में आर्थिक उन्नति तो लाता है, लेकिन कई मामलों में बुजुर्ग माता-पिता अकेले पड़ जाते हैं। देखभाल और भावनात्मक समर्थन का अभाव तथा अकेलेपन से बुजुर्गों की मानसिक एवं शारीरिक स्थिति दयनीय हो जाती है। हाल ही में बजट सत्र के दौरान राज्यसभा में इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया गया और विदेश जाने वाले युवाओं के लिए माता-पिता की देखभाल सुनिश्चित करने वाले सख्त नियमों की मांग की गई। सुझाव दिया गया कि विदेश जाने से पहले युवाओं से एक हलफनामा लिया जाए, जिसमें वे अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा माता-पिता की देखभाल के लिए देने का वादा करें। साथ ही हर छह महीने में माता-पिता से 'संतुष्टि प्रमाण पत्र' प्राप्त करना अनिवार्य हो, जिसमें बुजुर्ग पुष्टि करें कि उनकी देखभाल सही तरीके से हो रही है, उनके बच्चे नियमित संपर्क में हैं और आवश्यक सहायता मिल रही है। यदि ऐसा प्रमाण पत्र नहीं मिलता या शिकायत आती है, तो ऐसे युवाओं का पासपोर्ट रद्द किया जाए और उन्हें भारत वापस बुलाया जाए। इसके अलावा यह सलाह भी दी गई कि कम से कम सप्ताह में एक बार फोन पर माता-पिता का हालचाल पूछना भी बाध्यकारी होना चाहिए।

संसद में दिए गए ये सुझाव इसलिए महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले वर्ष पांच सौ से अधिक ऐसे मामले सामने आए, जहां विदेश में बसे बच्चों की ओर से उपेक्षा के कारण माता-पिता की हालत बहुत खराब हो गई या उनकी मृत्यु हो गई और बच्चे अंतिम संस्कार के लिए भी नहीं लौटे। यह मुद्दा केवल भावनात्मक नहीं है, बल्कि सामाजिक और कानूनी दृष्टि से भी गंभीर है। भारत में पहले से ही 'माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम- 2007' लागू है, जो युवाओं को माता-पिता की आर्थिक और भावनात्मक देखभाल के लिए जिम्मेदार बनाता है। इस कानून के तहत बुजुर्ग न्यायाधिकरण में शिकायत कर सकते हैं और अपने बच्चों से मासिक भरण-पोषण की सहूलियत प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें संपत्ति हस्तांतरण रद्द करने की शक्ति भी शामिल है। मगर अफसोसनाक है कि सख्त कानूनी प्रावधानों के बावजूद बुजर्गों की देखभाल और सुरक्षा पूरी तरह सुनिश्चित नहीं हो पा रही है, जिस कारण बड़ी संख्या में बुजुर्ग वृद्धाश्रम में शरण लेने को मजबूर हो रहे हैं, जबकि कई माता-पिता के बच्चे भारतीय शहरों में ही रह रहे हैं।

दूसरा, यह कानून विदेश में बसे युवाओं (एनआरआइ) पर प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो पाता, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय क्षेत्राधिकार, प्रवर्तन की कमी और संपर्क की दूरी जैसी समस्याएं आड़े आती हैं। कई एनआरआइ युवा भारत में संपत्ति या बैंक खाते रखते हैं, लेकिन माता-पिता की देखभाल की जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेते हैं। संसद में पेश किया गया प्रस्ताव इसी कमी को दूर करने के प्रयास से जुड़ा है, जहां विदेश मंत्रालय और पासपोर्ट प्राधिकरण के माध्यम से यात्रा तथा नागरिकता से जुड़ी शर्तें लगाने का सुझाव दिया गया है। यदि इस पर गंभीरता से विचार कर इसे व्यवस्था का हिस्सा बनाए जाए, तो विदेश जाने वाले युवाओं के लिए पासपोर्ट आवेदन

या वीजा प्रक्रिया में माता-पिता की सहमति या हलफनामा अनिवार्य हो सकता है, जो उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम होगा। इस तरह के कानून की आवश्यकता इसलिए भी महसूस की जा रही है, क्योंकि भारत में बुजुर्ग आबादी तेजी से बढ़ रही है। वर्ष 2021 के एक अनुमानित आंकड़े के अनुसार, देश में साठ वर्ष से अधिक उम्र के लोग कुल आबादी का लगभग दस फीसद हैं, और यह संख्या वर्ष 2030 तक और बढ़ने का अनुमान है। युवाओं के विदेश और शहरों में पलायन के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में बुजुर्ग अकेले रह जाते हैं, जहां स्वास्थ्य सेवाएं, सामाजिक सुरक्षा और भावनात्मक समर्थन की कमी होती है।

> कई बार माता-पिता अपने बच्चों को विदेश भेजने के लिए अपनी जमीन-जायदाद तक बेच देते हैं, अपनी सारी बचत उसमें लगा देते हैं और कहीं कमी रह जाए तो बैंकों से कर्ज लिया जाता है। मगर कई दफा उन्हें बदले में अकेलापन और उपेक्षा ही मिलती है। यह न केवल व्यक्तिगत स्तर पर दुखद है, बल्कि समाज में पारिवारिक मूल्यों के क्षरण को भी दर्शाता है। भारतीय संस्कृति में 'मातृ-पितृ भक्ति' को सर्वोच्च माना जाता है, लेकिन आर्थिक महत्त्वाकांक्षा और पश्चिमी जीवनशैली के प्रभाव से ये मूल्य कमजोर पड़ रहे हैं।

कई मामलों में माता-पिता अपने बच्चों को विदेश भेजने के लिए अपनी जमीन-जायदाद तक बेच देते हैं, अपनी सारी बचत उसमें लगा देते हैं और कहीं कमी रह जाए तो बैंकों से कर्ज लिया जाता है। मगर कई दफा उन्हें बदले में अकेलापन और उपेक्षा ही मिलती है। यह न केवल व्यक्तिगत स्तर पर दुखद है, बल्कि समाज में पारिवारिक मूल्यों के क्षरण को भी दर्शाता है। भारतीय संस्कृति में 'मातृ-पितृ भक्ति' को सर्वोच्च माना जाता है, लेकिन आर्थिक महत्त्वाकांक्षा और पश्चिमी जीवनशैली के प्रभाव से ये मूल्य कमजोर पड़ रहे हैं। संसद में दिया गया सुझाव इसी सांस्कृतिक संकट पर ध्यान आकर्षित करता है और याद दिलाता है कि युवाओं की सफलता के पीछे माता-पिता का त्याग भी होता है, इसलिए उनकी सेवा अनिवार्य होनी चाहिए।

हालांकि, इस प्रस्ताव पर बहस भी छिड़ी हुई है। कुछ लोग इसे सकारात्मक मानते हैं, क्योंकि यह बुजुर्गों के अधिकारों की रक्षा से जुड़ा है और बच्चों में जिम्मेदारी की भावना जगाने वाला है। सोशल मीडिया पर कई लोग इसका यह कहकर समर्थन कर रहे हैं कि इस तरह का कानून जरूरी है, ताकि माता-पिता का भविष्य सुरक्षित रहे। दूसरी ओर, कुछ आलोचक इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अतिक्रमण मानते हैं। वे कहते हैं कि पासपोर्ट रद्द करना या प्रमाण पत्र की बाध्यता जैसे कदम बहुत कठोर हैं, जो प्रवास की स्वतंत्रता को प्रभावित करेंगे। अंतरराष्ट्रीय कानूनों में पासपोर्ट रद्द करने के लिए केवल गंभीर अपराध या राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार होते हैं, न कि पारिवारिक मामलों पर। एनआरआइ समुदाय का एक हिस्सा भी इसे भेदभावपूर्ण मानता है, उनका तर्क है कि भारत में रहने वाले युवा जो माता-पिता की उपेक्षा करते हैं, उनके खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई नहीं होती है।

इसके बावजूद इस प्रस्ताव की व्यावहारिकता पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। यदि सरकार इस तरह के प्रावधान लागू करती है, तो विदेश मंत्रालय को एनआरआइ से जुड़े डेटाबेस को मजबूत करना होगा, भारतीय दूतावासों के माध्यम से प्रमाण पत्र सत्यापन की व्यवस्था करनी होगी और शिकायतों के लिए एक तंत्र बनाना होगा। यह प्रक्रिया जटिल हो सकती है, लेकिन डिजिटल प्रणाली और आधार जैसी सुविधाओं से इसे संभव बनाया जा सकता है। मिसाल के तौर पर माता-पिता एक आनलाइन पोर्टल पर प्रमाण पत्र दर्ज कर सकते हैं या दूतावास में जमा कर सकते हैं। यदि प्रमाण पत्र नहीं मिलता है, तो पासपोर्ट नवीनीकरण रुक सकता है या यात्रा प्रतिबंध लग सकता है। यह कदम युवाओं को अपने माता-पिता से नियमित संपर्क बनाए रखने के लिए प्रेरित करेगा और उनकी सुरक्षा का एहसास दिलाता रहेगा।

इस मुद्दे पर संसद में उठाया गया सवाल केवल कानूनी नहीं, बल्कि नैतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी अहम है। यदि ऐसा कानून बनता है, तो यह सुनिश्चित करेगा कि विदेश में सफलता पाने वाले युवा अपने माता-पिता को कभी न भूलें। बुजुर्गों का सम्मान और सुरक्षा राष्ट्र की प्रगति का आधार है, और उनकी उपेक्षा सामाजिक मूल्यों के लिए घातक साबित हो सकती है। इसलिए इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए, ताकि बुजुर्ग माता-पिता का भविष्य सुरक्षित हो और परिवार की एकता बनी रहे। यह कदम न केवल बुजुर्गों की रक्षा करेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को जिम्मेदारी का पाठ भी पढ़ाएगा।

दृढ़ता का दायरा

प्रेरणा अवस्थी

मनुष्य का जीवन किसी सीधी सड़क की यात्रा नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे महासागर की यात्रा है, जिसमें मौसम प्रति पल अपना रंग बदलता रहता है। हवा का रुख कभी यात्रा की दिशा के अनुकूल होता है, तो कभी प्रतिकूल। विशाल जलराशि कभी शांत होती है, तो कभी उग्र। ऐसी दशाओं में नाव का चलना केवल भाग्य या परिस्थितियों पर ही निर्भर नहीं होता, बल्कि वह निर्भर करता है नाविक की सजगता, साहस और खासकर उस पतवार पर, जिसे वह लगातार थामे रहता है। जीवनरूपी महासागर की इस यात्रा में जो तत्त्व पतवार की भूमिका अदा करता है, वह है दृढ़ निश्चय। यह ऐसी शक्ति है, जो मनुष्य को विपरीत परिस्थितियों में भी सही दिशा से भटकने नहीं देती। इसलिए यह कहना कोई अत्युक्ति नहीं कि दृढ़ निश्चय ही जीवन की पतवार है।

आज का समय जितना द्रुत है, उतना ही अधिक विचलनशील भी। तकनीक के उन्नयन ने निस्संदेह हमें सुविधाओं का अमूल्य कोष प्रदान किया है, लेकिन साथ ही हमें अधीरता भी एक पार्श्वप्रभाव के रूप में प्राप्त हुई है। विकल्पों की बाढ़ ने हमें विविध अवसर दिए हैं, लेकिन निर्णय की स्थिरता को बहुत बुरी तरह प्रभावित किया है। आज स्थिति यह है कि हम शीघ्रातिशीघ्र परिणाम चाहते हैं, तत्काल स्थापित होना चाहते हैं और बिना संघर्ष के ही सफलता की कल्पना करने लगते हैं। यही कारण है कि मार्ग में उपस्थित छोटे-छोटे अवरोध भी हमें बड़े संकट जैसे प्रतीत होने लगते हैं। कोई कार्य अपनी सिद्धि में थोड़ा समय ले ले, तो हमारा मन हमसे कहता है कि 'इसे छोड़ो'। कार्य में असफलता प्राप्त होने पर मन उसे अपनी क्षमताओं की परिधि से परे समझ लेता है। आलोचना की स्थिति में मन हताशा और नकारात्मकता से भरने लगता है।

ऐसे प्रतिकूल समय में दृढ़ निश्चय ही वह आंतरिक बल है, जो मन को टूटने से बचाता है और विचारों को बिखरकर व्यर्थ नहीं होने देता। दृढ़ निश्चय को कई बार हठ, जिद या कठोरता के साथ जोड़ दिया जाता है। मगर वास्तविक दृढ़ निश्चय का आधार कभी कठोर नहीं होता, बल्कि यह विवेक की कोमलता से निर्मित होता है। दृढ़ निश्चय सदैव सही लक्ष्य चुनकर, सही दिशा पकड़कर, प्रत्येक बाधा को पार करते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इसकी पतवार में एक अनोखा लचीलापन होता है। परिस्थितियां बदलने पर यह अपनी गति का तरीका भी परिवर्तित कर लेती है, लेकिन प्रत्येक दशा में लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता बनी रहती है। यह व्यक्तित्व को स्थिरता प्रदान करता है। अंतर्मन में विद्यमान भय, आलस्य, निराशा और शंका व्यक्ति की संभावनाओं को समाप्त कर देते हैं। दृढ़ निश्चय ही वह गुण है जो इन शत्रु भावों के प्रति एक अमोघ अस्त्र का कार्य करके इनका शमन करता है और मन को लक्ष्य के साथ बांधे रखता है।

सफलता का मार्ग बाहर से जितना आकर्षक दिखाई पड़ता है, भीतर से उतना ही कठिन और संघर्षपूर्ण होता है। हम अक्सर किसी व्यक्ति की मंजिल को देखते हैं, उस मंजिल तक पहुंचने में उसके द्वारा की गई यात्रा को नहीं। अनेक बार टूटकर भी अपने संकल्प को बचाए रखने के उत्साह को शायद हम नहीं देख पाते। दृढ़ निश्चय का संबंध परिश्रम के साथ धैर्य से भी है। निरंतरता ही मेहनत के मूल्य को निर्मित करती है। यह सीख हमें प्रकृति से सतत रूप से मिलती रहती है। बीज मिट्टी में पड़कर तत्काल वृक्ष नहीं बन जाता। बहता पानी एक ही दिन में नदी के रूप में अपनी पहचान नहीं प्राप्त कर लेता। पर्वतों की विशालता भी सदियों में ही अस्तित्व में आती है। ठीक इसी तरह मनुष्य के भीतर भी बड़े परिवर्तन एक क्षण में नहीं घटित होते।

दृढ़ निश्चय व्यक्ति को लंबी यात्रा के लिए तैयार करता है। वह उसे सदैव प्रेरित करता है कि मार्ग अवश्य कठिन एवं दुरूह होगा, लेकिन यात्रा को विराम मत देना। छोटे-छोटे संकल्प मन को दृढ़ता प्रदान करते हैं। संकल्पों की ऊर्जा से सिंचित मन ही धीरे-धीरे बड़े संघर्षों के लिए तैयार होता है। दृढ़ निश्चय का आधार है- स्वयं के प्रति ईमानदारी। जो व्यक्ति अपने आप से बार-बार वादा करके तोड़ता है, वह अति शीघ्र भीतर से कमजोर हो जाता है, लेकिन स्वयं के साथ प्रतिबद्ध व्यक्ति आत्मविश्वास के उच्चतम स्तर को प्राप्त कर लेता है।

दृढ़ निश्चय व्यक्ति को परिस्थितियों का दास नहीं बनने देता। यह व्यक्ति को प्रतिकूल परिस्थिति में भी प्रयत्न की निरंतरता को बनाए रखने की शक्ति देता है। नतीजतन, व्यक्ति मानसिक रूप से सशक्त हो जाता है। दृढ़ निश्चय से पूर्ण व्यक्ति गिरकर भी उठता है, रुककर भी फिर चल पड़ता है और हारकर भी जीतने का प्रयास करता है। जीवन में कई बार हम कुछ समय के लिए पीछे चले जाते हैं, लेकिन अगर हमारा संकल्प जीवित है, तो हम फिर से आगे बढ़ जाते हैं। एक महत्त्वपूर्ण बात यह कि दृढ़ निश्चय की पतवार बिना दिशा के नहीं चलती। इसलिए लक्ष्य का चयन भी नितांत महत्त्वपूर्ण है। लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो आत्मा की गहराई से जुड़ा हो। जब लक्ष्य हमारे भीतर से निकलता है, तब दृढ़ निश्चय स्वतः मजबूत होता है। मगर जब लक्ष्य केवल बाह्य प्रदर्शन के लिए होता है, तब वह कठिनाई का वार होते ही टूट जाता है।

इसलिए जीवन में सर्वप्रथम यह स्पष्ट होना जरूरी है कि हमें दरअसल चाहिए क्या। उसके बाद उसी लक्ष्य के लिए अपने भीतर दृढ़ निश्चय को उत्पन्न करना चाहिए। आज तेजी से परिवर्तित होती दुनिया, अनियंत्रित प्रतिस्पर्धा और जटिल चुनौतियों के बीच हमें अपने भीतर दृढ़ निश्चय को केवल एक गुण के रूप में ही नहीं, बल्कि जीवन की आधारशिला के रूप में विकसित करना होगा। जो व्यक्ति दृढ़ निश्चय की पतवार थामकर जीवनयात्रा को जारी रखता है, परिस्थितियां उसे लेशमात्र भी क्षति नहीं पहुंचा सकतीं। वे केवल और केवल उसके व्यक्तित्व को निखारने का कार्य करती हैं।

दुनिया मेरे आगे

> दृढ़ निश्चय को कई बार हठ, जिद या कठोरता के साथ जोड़ दिया जाता है। मगर वास्तविक दृढ़ निश्चय का आधार कभी कठोर नहीं होता, बल्कि यह विवेक की कोमलता से निर्मित होता है। दृढ़ निश्चय सदैव सही लक्ष्य चुनकर, सही दिशा पकड़कर, प्रत्येक बाधा को पार करते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।

कसौटी पर साझेदारी

भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। यह समझौता निर्यात, निवेश और तकनीकी सहयोग के नए अवसर प्रदान कर सकता है। हालांकि, इस समझौते के साथ कई चुनौतियां भी जुड़ी हैं। अमेरिकी बाजार में अधिक पहुंच के बदले में भारत पर शुल्क में कटौती, बौद्धिक संपदा नियमों और कृषि मानकों को लेकर दबाव है। इससे घरेलू उद्योगों, खासकर लघु और मध्यम उद्यमों पर प्रतिस्पर्धात्मक दबाव पड़ेगा। किसानों और डेटा सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर संतुलित नीति बनाना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। फिर भी यह समझौता भारत के निर्यात, निवेश और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देकर वैश्विक मंच पर उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकता है। आपूर्ति शृंखला में भारत की भूमिका बढ़ने से रोजगार और विनिर्माण क्षेत्र को दीर्घकालिक लाभ मिल सकता है। मगर शुल्क कटौती और बाजार खोलने का दबाव घरेलू उद्योगों और किसानों के लिए असमान प्रतिस्पर्धा पैदा कर सकता है। इसलिए जरूरी है कि भारत किसी भी समझौते में अपने दीर्घकालिक आर्थिक हितों, आत्मनिर्भरता और सामाजिक संतुलन को प्राथमिकता दे।

– आशुतोष पांडेय, जम्मू

नया अध्याय

बांग्लादेश में बीएनपी की जीत के बाद भारत का रुख क्या होगा? यह सवाल इन दिनों हर जगह पूछा जा रहा है। शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग के लगभग डेढ़ दशक के शासन के बाद, बांग्लादेश नैशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की तारिक रहमान के नेतृत्व में वापसी ने द्विपक्षीय संबंधों की एक नई शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रहमान को फोन कर बीएनपी की निर्णायक जीत पर बधाई दी। यह त्वरित संपर्क भारत की 'पड़ोसी प्रथम' नीति के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस नए अध्याय में कई लंबित मुद्दे शामिल हैं। बीएनपी के घोषणापत्र में तीस्ता जल बंटवारे समेत सीमा पार से होने वाली गोलीबारी और व्यापार असंतुलन जैसे मुद्दों को उठाने का वादा किया गया है। भारत के लिए यह भी जरूरी है कि वह बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नई सरकार के साथ रचनात्मक बातचीत करे, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अब एक नए मोड़ पर हैं।

– सुमित सेठ, चंडीगढ़

सबकी जिम्मेदारी

हाल ही में केंद्र सरकार ने शहरों के विकास के लिए हरी झंडी दिखा दी है। यह शहरों को बेहतर बनाने का प्रयास है। मगर केंद्र सरकार का प्रयास तभी सफल हो सकता है, जब सभी राज्य मिल कर काम करेंगे। इससे पहले भी केंद्र सरकार ने शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए प्रयास किया था, लेकिन कुछ खास कामयाबी नहीं मिली। सवाल यह है कि शहरों की सूरत संवारना क्या केंद्र सरकार का ही काम है? क्या राज्य सरकारों की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी का जो सपना देखा है, वह क्या सचमुच पूरा हो सकेगा? जहां भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हो और जहां जनहित के हर काम में भी विघ्न डाला जाता हो, वहां विकास कैसे संभव होगा? अगर आजादी के बाद हर पार्टी के नेता और हर सरकारी कर्मचारी जनहित के लिए निस्वार्थ काम कर रहे होते, तो आज देश में स्मार्ट सिटी बनाने का दिखावा नहीं करना पड़ता, बल्कि आज भारत विश्व का आधुनिक देश होता।

– राजेश कुमार चौहान, जलंधर

इंसानियत की खातिर

एक ओर हम 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प कर रहे हैं, तो दूसरी ओर सामाजिक स्तर पर अब भी भेदभाव होता है। सदियों पुरानी जातीय जकड़न से भारतीय समाज आज भी मुक्त नहीं हो पा रहा है। सामाजिक सद्भाव को ठेस पहुंचाने की यह प्रवृत्ति अच्छी नहीं है। भेदभाव से समाज में दरार पैदा होती है। व्यक्ति का मनोबल कमजोर होता है। हमारी एकता पर भी इसका असर पड़ता है। भारत जाति व्यवस्था से कब मुक्त होगा? आखिर क्या वजह है कि कुछ जातियां स्वयं को श्रेष्ठ मानती हैं? यह प्रवृत्ति एक तरह से दूसरों को कम आंकने जैसा है। जाति के आधार पर खुद को सबसे अच्छा मानने की धारणा इस कदर रच-बस गई है कि यह भारतीय समाज को खोखला कर रही है। यह तस्वीर बदलनी चाहिए।

– मिथिलेश कुमार, भागलपुर

बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए मौजूद हैं कई विकल्प

जनसत्ता कारोबाजार

पहली बार माता-पिता बनने का एक अलग ही सुख होता है। पहली संतान के लिए हर अभिभावक यह चाहता है कि वह अपने बच्चे के लिए कुछ ऐसा करे कि उसका जीवन आर्थिक रूप से हमेशा के लिए सुरक्षित बन जाए। बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए वो हर काम करने के लिए तैयार रहते हैं। फिर चाहे बच्चे की पढ़ाई हो या उनका रहन-सहन, या भविष्य। लेकिन बच्चे का भविष्य कैसे सुरक्षित बनेगा, इसके लिए यहां पर निवेश के कुछ ऐसे उपाय बताए जा रहे हैं।

म्यूचुअल फंड में निवेश

आज के आधुनिक युग में म्यूचुअल फंड निवेश का एक सबसे अच्छा और सस्ता साधन माना जाता है। यह निवेशकों को उनके कई तरह के जोखिम एवं निवेश के आधार पर कई अच्छे विकल्पों की पेशकश करता है। इनमें से इक्विटी म्यूचुअल फंड, बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड और डेट फंड मुख्य हैं। इक्विटी पर आधारित फंड जोखिम भरे होते हैं, क्योंकि वे शेयरों में निवेश करते हैं। बैलेंस्ड फंड का जोखिम सामान्य होता है, क्यों कि वे आंशिक रूप से ऋण में निवेश करते हैं। डेट फंड में जोखिम ना के बराबर होता है। इसके अलावा भी म्यूचुअल फंड के कई विकल्प हैं , जिनमें गोल्ड ईटीएफ से लेकर हाइब्रिड फंड तक है। म्यूनचुअल फंड में निवेश का सबसे सुरक्षित तरीका एसआइपी है।

जायदाद में निवेश

भारत में जमीन झ जायदाद ही एक ऐसी चीज है, जिसकी कीमत सिर्फ बढ़ती है। तो अगर आप जमीन खरीद कर अपने बच्चे के नाम करना चाहते हैं तो यह उसके लिए सबसे अच्छा निवेश होगा। हालांकि बड़े शहरों में अब जमीन खरीदना संभव नहीं है, लेकिन आप फ्लैट खरीद सकते हैं या फिर छोटे शहरों में जमीन भी खरीद सकते हैं। छोटे शहरों में जमीन खरीदना थोड़ा आसान होता है और यहां पर बिक्री भी काफी अच्छी हो सकती है।

बच्चों की बात

बांड और एफडी

बच्चों के भविष्य सुरक्षित बनाने के लिए बांड और एफडी भी शानदार विकल्प हैं । दोनों में लाभ सुनिश्चित है। अन्य निवेश की तुलना में बांड व एफडी में पैसा लगाने पर एक निश्चित ब्याज मिलता है और इसमें निवेश के डूबने का जोखिम नहीं रहता है। इनमे एक नियत अवधि के लिए निवेश करना होता है , बीच में पैसा निकलना ठीक नही रहता है।

सोने के बिना भारत का व्यापार अधूरा माना जाता है। सोना लोग हमेशा खरीदते और बेचते हैं। भारत एक ऐसा देश माना जाता है जहां पर सोना सबसे अधिक खरीदा और बेचा जाता है। सोने की कीमत घटती- बढ़ती रहती है। इसकी कीमत कभी भी एक जैसी नहीं होती है, लेकिन अब तक के रिकार्ड के अनुसार पिछले कई साल में सोने की कीमत काफी बढ़ चुकी है। इसलिए आप सोने में निवेश करने की बात सोच सकते हैं। चांदी में निवेश भी नया विकल्प बन कर उभरा है। सोने चांदी में निवेश के लिए गोल्ड ईटीएफ और सिल्वर ईटीएफ विकल्प हैं।

पोस्ट आफिस योजना में भी दम

पोस्ट आफिस में इस समय कई ऐसी योजनाएं हैं जो कि बचत योजनाओं के रूप में जानी जाती है। इन योजनाओं में सुकन्याह समृद्धि योजना सिर्फ बच्चियों के लिए है, जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा अलग-अलग बैंकों में बच्चों के लिए कई बचत खाते खोले जाते हैं, जहां पर अपने बच्चे के नाम से बचत खाता खोल सकते हैं।

बीमा योजना भी जरूरी

हर किसी को एक बीमा योजना खरीदनी चाहिए। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि यह आपके ना होने पर आप पर आश्रित व्यक्तियों के जीवन को आसान बनाने का कार्य करती हैं। यह आपके बच्चों की पढ़ाई से लेकर उनके शादी तक में काम आते हैं। टर्म बीमा असल बीमा है। इसलिए आप टर्म बीमा में निवेश कर सकते हैं, टर्म बीमा में कम प्रीमियम में बड़ी राशि प्राप्त होती है।

डिजिटल वसीयत बनाएं, बड़े काम की चीज है

जनसत्ता कारोबाजार

एक समय था जब केवल चल-अचल संपत्तियों की ही कानूनी वसीयत बनाई जाती थी। आज समय बदल चुका है। अब लोगों की डिजिटल संपत्तियां भी बहुत हैं। शेयर, पुस्तक लेखन, सोशल मीडिया अकाउंट, डिजिटल वालेट और क्रिप्टो आदि आज की नई डिजिटल संपत्तियां हैं। इनकी सुरक्षा आज अनिवार्य है। अपने डिजिटल खातों में नामिनी बनाएं, नामिनी तक पासवर्ड की पहुंच सुनिश्चित करें। यह इसलिए जरूरी है कि कहीं आपकी मेहनत शून्यता में न खो जाए। इसलिए एक कानूनी वसीयत ही पूरी संपत्ति बचाने के लिए काफी नहीं है।

आज स्मार्टफोन लोगों के जीवन की 'मास्टर चाबी' है। सब कुछ उसी में समाया है। बैंकिंग एप, परिवार के फोटो, और यहां तक कि कर रिकार्ड भी फोन के एक लाक के पीछे हैं। यदि फोन फेस स्कैन या किसी ऐसे कोड ले लाक है, जिसके बारे में परिवार में किसी को भी जानकारी नही है, तो मुसीबत के समय पैसे आपके काम नहीं आएंगे। डिजिटल विरासत को संभालना जरूरी है। स्मार्टफोन का लाक आसान रखें, नामिनी तक उसकी पहुंच दें, सब कुछ लिख कर एक डायरी में रखें। हो सके तो पासकोड के लिए एक आपात फोल्डर बनाएं और इसे सहेज कर रखें। आप 'डिजिटल पासवर्ड मैनेजर' का भी उपयोग कर सकते हैं। ये टूल आपको एक आपातकालीन संपर्क नामित करने की सुविधा देते हैं, जो उपयोगकर्ता के लंबे समय तक निष्क्रिय रहने पर एक्सेस प्राप्त कर सकता है।

अब हम केवल पारंपरिक बैंक खातों तक सीमित नहीं हैं। हमारे पास यूपीआइ से जुड़े वालेट, प्रीमियम क्रेडिट कार्डों पर मिलने वाले भारी रिवार्ड पाइंट और भोजन, यात्रा या कैब बुकिंग एप में जमा नकद बैलेंस भी होते हैं। ये संपत्तियां 'भूत' की तरह हैं, क्योंकि इनके फिजिकल स्टेटमेंट्स शायद ही कभी डाक से आते हैं। हर सक्रिय डिजिटल वालेट और फिनटेक एप का रिकार्ड रखें। सबसे महत्त्वपूर्ण बात, सेटिंग की जांच करें ओ देखें कि इन एप में नामिनी का विवरण अपडेट किया गया है या नहीं। नामिनी सेटिंग सुनिश्चित करता है कि पैसा बिना किसी कानूनी लड़ाई के सही व्यक्ति तक पहुंचे। ईमेल और क्लाउड को भी सुरक्षित करें। गूगल पर, 'निष्क्रिय अकाउंट मैनेजर' सेट करें। यह सिस्टम को बताता है कि किसी विश्वसनीय व्यक्ति को आपके डेटा का एक्सेस कब देना है। एप्पल के पास 'लिगेसी कान्टैक्ट' नामक एक समान टूल है। मुसीबत के समय में ये दोनों ही जीवनरक्षक साबित होते हैं। कागज के शेयर प्रमाणपत्र रखने के दिन अब खत्म हो गए हैं। आज सब कुछ डीमैट अकाउंट में हैं। शेयर कारोबार पूरी तरह से कागजविहान है। इसलिए सुनिश्चित करें कि सभी डीमैट खातों में एक 'बेनेफिशियल नामिनी' हो।

काम काज

भारत में अब कई निवेशक क्रिप्टो, डिजिटल मुद्रा और विकेंद्रित वित्त (डी- फि) में हाथ आजमा रहे हैं। विरासत के मामले में यह सबसे खतरनाक क्षेत्र है। बैंक में आप मैनेजर से बात कर सकते हैं। क्रिप्टो में कोई मैनेजर नहीं होता। यदि आप किसी वालेट की 'प्राइवेट की' या 'सीड फ्रेज' खो देते हैं, तो समझो पैसा गया। कोई भी अदालत या तकनीकी विशेषज्ञ उसे वापस नहीं ला सकता। वह डिजिटल दुनिया में हमेशा के लिए खो जाता है।

संवाद

मेरठ में रविवार को मेट्रो से मेरठ साउथ स्टेशन जाते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांग बच्चों से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने मेरठ में 12,930 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया।

घरेलू खुदरा बाजार 2035 तक दोगुना होगा

घरेलू खुदरा बाजार वर्ष 2035 तक बढ़कर 210-215 लाख करोड़ रुपए हो जाने का अनुमान है, जो 2025 में अनुमानित 90-95 लाख करोड़ रुपए का दोगुने से भी अधिक होगा। 16 फरवरी सोमवार को जारी एक रपट में यह अनुमान जताया गया। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी) और रिटेलर्स एसोसिएशन आफ इंडिया (आरएआइ) ने संयुक्त रूप से यह रपट 'रिटेल लीडरशिप समिट 2026' में जारी की। रपट कहती है कि प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बेहतर प्रदर्शन और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर होने से भारत खुदरा बाजार में वृद्धि का प्रमुख चालक रहेगा। रपट के मुताबिक, खुदरा क्षेत्र के अगले चरण की वृद्धि में वे कंपनियां आगे रहेंगी जो स्पष्ट रणनीतिक ध्यान, अनुशासित क्रियान्वयन और कृत्रिम मेधा (एआइ) पर आधारित बदलाव को अपनाएंगी। रपट कहती है कि उपभोक्ता जुड़ाव, परिचालन माडल और प्रतिभा प्रबंधन में संरचनात्मक परिवर्तन अपनाने वाले खुदरा विक्रेता 200 लाख करोड़ रुपए के बाजार की यात्रा में असमानुपातिक मूल्य अर्जित कर सकेंगे।

म्यूचुअल फंड कोई भी हो, निवेश के लिए सबसे सुरक्षित तरीका है

फंड्स का फंडा

जनसत्ता कारोबाजार

मोटे तौर पर म्यूचुअल फंड के चार प्रकार होते हैं। म्यूचुअल फंडों को उनकी अंतर्निहित परिसंपत्तियों के आधार पर इक्विटी फंड (शेयर), डेट फंड (बांड), हाइब्रिड फंड (शेयर और बांड का मिश्रण) और मनी मार्केट फंड (अल्पकालिक ऋण) में वर्गीकृत किया जाता है।

जानकारों का मानना है कि म्यूचुअल फंड के प्रकार कोई भी हो, इसमें निवेश के लिए एसआइपी सबसे सुरक्षित तरीका है। लेकिन एसआइपी में निवेश का 7-5-3-1 नियम एक सशक्त तरीका है। यह नियम इक्विटी निवेश के लाभदायक सफर का मार्ग प्रशस्त करता है। 7-5-3-1 नियम इक्विटी म्यूचुअल फंड में व्यवस्थित निवेश योजनाओं (एसआइपी) के लाभों को अधिकतम करने की एक व्यापक रणनीति है। यह नियम निवेश की अवधि, विविधीकरण, मानसिक दृढ़ता और एसआइपी राशि में क्रमिक वृद्धि के महत्त्व पर बल देता है ।

7-5-3-1 नियम निवेशकों को एसआइपी की अवधि, विविधीकरण, मानसिक दृढ़ता और चरणबद्ध योगदान पर सलाह देता है, ताकि जोखिम का सफलतापूर्वक प्रबंधन करते हुए दीर्घकालिक लाभ को अधिकतम किया जा सके। सात वर्ष या उससे अधिक की एसआइपी अवधि अस्थिरता को कम करती है जबकि दीर्घकालिक चक्रवृद्धि को मजबूत करती है।

पांच इक्विटी समूहों में विविधीकरण से जोखिम-समायोजित होकर रिटर्न में वृद्धि होती है। निवेशकों को तीन चरणों (निराशा, चिड़चिड़ापन और घबराहट) का अनुभव होता है, और इसमें शामिल रहना महत्त्वपूर्ण है। स्टेप-अप एसआइपी,फिक्स्ड एसआइपी की तुलना में समग्र संपत्ति में काफी वृद्धि करते हैं।

पहला मूलभूत सिद्धांत है निवेश की अवधि सात वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। शेयर बाजार में गिरावट के दौरान हुए नुकसान को कम करते हुए, सात वर्षों की अवधि में शेयरों का प्रदर्शन आमतौर पर अच्छा रहता है। कम से कम सात वर्षों के लिए इक्विटी एसआइपी में निवेश करने से चक्रवृद्धि ब्याज का पूरा लाभ मिलता है। सिप के सात सामान्य प्रकार हैं: रेगुलर एसआइपी, टाप-अप एसआइपी , फ्लेक्सिबल एसआइपी, ट्रिगर एसआइपी, पर्फेचुअल एसआइपी, मल्टी एसआइपी और बीमा सहित एसआइपी । ये विकल्प निवेशकों को एक संरचित निवेश दृष्टिकोण चुनने की सुविधा देते हैं जो उनके वित्तीय लक्ष्यों और आय स्थिरता के अनुरूप हो।

विविधीकरण ही सफलता दिलाता है

इक्विटी निवेशकों के लिए, निवेश पोर्टफोलियो में स्थिरता और वृद्धि प्राप्त करने के लिए विविधीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। '5 फिंगर फ्रेमवर्क' जोखिम और प्रतिफल को प्रभावी ढंग से संतुलित करने के लिए निवेश को पांच प्रमुख परिसंपत्ति वर्गों में फैलाने का सुझाव देता है। इन परिसंपत्ति वर्गों में उच्च-गुणवत्ता वाले शेयर, वैल्यू शेयर, जीएआरपी (उचित मूल्य पर वृद्धि) शेयर, मिडकैप या स्माल-कैप शेयर और वैश्विक शेयर शामिल हैं। उच्च गुणवत्ता वाले शेयर (लार्ज कैप शेयर) एक मजबूत निवेश पोर्टफोलियो की नींव बनाते हैं।

वैल्यू शेयर वर्तमान में बाजार में कम मूल्य पर उपलब्ध हैं। इन शेयरों में निवेश करना दीर्घकालिक रूप से लाभदायक हो सकता है, क्योंकि इनके मूल्य में वृद्धि होने की संभावना रहती है , जिससे निवेशक इन्हें उच्च कीमतों पर बेच सकते हैं।

जीएआरपी शेयर (उचित मूल्य पर वृद्धि) उभरते या तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में आशाजनक कंपनियों के निवेश हैं। ये शेयर वृद्धि और मूल्य निवेश दोनों के तत्वों को समाहित करते हैं। भारत में ड्रोन और दूरसंचार जैसे क्षेत्र जीएआरपी शेयर के उदाहरण हैं, जिनमें भविष्य में महत्त्वपूर्ण वृद्धि की संभावना है। मिडकैप और स्माल-कैप शेयर उन कंपनियों को दर्शाते हैं, जिनमें विकास की अपार संभावनाएं होती हैं। हालांकि इनमें लार्ज-कैप शेयर की तुलना में जोखिम अधिक होता है, लेकिन ये असाधारण रूप से अधिक लाभ दे सकते हैं। वैश्विक शेयरों में निवेश करने से पोर्टफोलियो को भौगोलिक विविधता मिलती है, जिससे यह स्थानीय आर्थिक मंदी से सुरक्षित रहता है।

बाजार के वे शब्द, जिनमें छिपी हैं ट्रेडिंग की गुत्थियां

जनसत्ता कारोबाजार

एक समय था जब शेयर बाजार में केवल बड़े लोग ही पैसा लगाते थे या फिर विदेशी संस्थागत निवेशक ही पैसा लगाते थे। जानकारी बढ़ने के साथ आम लोग भी शेयर बाजार में निवेश करने लगे हैं। कभी घरेलू संस्थागत निवेशक और विदेशी संस्थागत निवेशक के दम पर भारत के शेयर बाजार नाचते थे। इन्हें 'बुल' निवेशक कहते हैं। लेकिन आज आम निवेशक बाजार के बड़े खिलाडी हैं । इन्हें 'पिग' निवेशक भी कहते हैं। ये 'पिग' निवेशक ही हैं, जो भारतीय शेयर बाजार को मजबूत बनाए रखते हैं।

अगर आम निवेशकों को भी शेयर बाजार में प्रयोग होने वाले तकनीकी शब्द के मायने समझ में आ जाए तो वे और सतर्क रह कर निवेश कर सकते हैं। इस आलेख में जानते हैं ऐसे ही शेयर बाजार से जुड़े तकनीकी शब्दों के बारे में, जिनसे ट्रेडिंग की गुत्थियां सुलझ सकती हैं।

शेयर सूत्र

बुल मार्केट

बुल मार्केट मतलब शेयर ट्रेडर व निवेशक इस बात का अनुमान लगाते हैं कि शेयर की कीमत बढेगी तथा इससे भविष्य में उन्हें अच्छा मुनाफा होगा।नई नीतियां यानई निवेश परियोजनाएं इस बाजार को प्रभावित कर सकती हैं।

बेयर मार्केट

जब निवेशक को यकीन हो जाता है कि उसके शेयर की कीमत घटने वाली है तो इसे बेयर मार्केट कहते हैं। ऐसी स्थिति में निवेशक अपने पैसों को निकाल कर किसी अन्य शेयर में लगाने के बारे में सोचता है। अगर बाजार में शेयर की कीमत हर रोज गिरने लगे तो समझे कि वह एक बेयर मार्केट है।

मार्जिन मनी

इस शब्द का इस्तेमाल मार्जिन ट्रेडिंग के दौरान होता है। डीमैट खाते में राशि कम होने पर राशि को बढ़ाएं कहने के बजाय मार्जिन मनी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। यदि आपके खाते में पैसे कम हैं और आप और शेयर खरीदना चाहते हैं तो यह शब्द का सुनना आम होगा।

बंपर लिस्टिंग

निवेशकों को हर शेयर पर हुई इतनी कमाई - आगे क्या करें? जब आइपीओ आता है और घोषित मूल्य से काफी अधिक मूल्य पर शेयर एक्सचेंज में सूचीबद्ध होती है तब इसे बंपर लिस्टिंग कहते हैं।

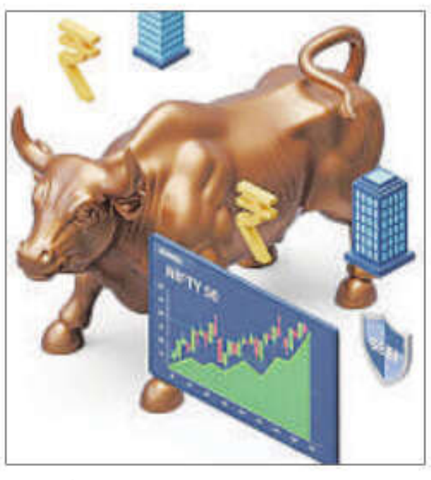

बीटा

बीटा बाजार में सुरक्षा की अस्थिरता को मापता है और एक शेयर की तुलना अन्य शेयरों से करता है। पूर्ण रूप से देखा जाए तो बाजार का बीटा हमेशा एक रहता है और अगर किसी विशेष शेयर का बीटा एक से अधिक है तो बाजार की तुलना में सुरक्षा अधिक आक्रामक होती है और अन्य स्थिति में इसके विपरीत।

डिविडेंड

कंपनी हर साल या छह महीनों में इस राशि को लाभ के तौर पर शेयरधारकों को देती है। इससे कंपनी की शेयर की कीमतों में तेजी आती है। कई कंपनियां डिविडेंड नीति का पालन नहीं करती और बोनस शेयर जारी कर सकती हैं।

स्प्रैड

जब एक निवेशक अपने शेयर को एक तय दाम पर बेचना चाहता है या जब एक निवेशक किसी तय दाम पर शेयर को खरीदना चाहता है तो उसे स्प्रैड करते हैं। आम तौर पर स्प्रैड शब्द का इस्तेमाल फ्यूचर या आप्शन मार्केट में होता है।

समर्थन मूल्य

हर शेयर का एक मूल्य तय किया जाता है जिसे सपोर्ट मूल्य कहते हैं। माना जाता है कि उस शेयर की कीमत तय सपोर्ट मूल्य से नीचे नहीं गिरेगी। हालांकि शेयर बाजार में हर रोज कई सपोर्ट मूल्य मिटते और बनते हैं। अगर कोई शेयर अपना सपोर्ट मूल्य तोड़ता है तो समझे कि वह समय शेयर को बेचने के लिए बिल्कुल सही है। तकनीकी विश्लेषण में यह शब्द सही बैठता है। पर जब बात शेयर के मौलिक विश्लेषण की आती है, तो सपोर्ट मूल्य कोई काम का नहीं।

भारत-ब्राजील : विन विन डील

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को वहां की सुप्रीम कोर्ट द्वारा गैरकानूनी करार दिए जाने और उसके बाद ट्रंप द्वारा 10 प्रतिशत की बजाय 15 प्रतिशत ग्लोबल टैरिफ लगाए जाने से पैदा हुई व्यापार अनिश्चितता के बीच भारत और ब्राजील ने ट्रेड डील पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा में गर्मजोशी में हुई बातचीत के बाद दोनों देशों में क्रिटीकल मिनरल्स और रेचर अर्थ एलिमैंट्स, व्यापार निवेश, रक्षा, ऊर्जा प्रौद्योगिकी तथा बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग बढ़ाने संबंधी समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। ब्राजील के राष्ट्रपति ए.आई. समिट में भाग लेने भारत आए हुए थे। इन समझौतों से एक दिन पहले भारत-अमेरिका के नेतृत्व वाले समूह पैक्स सिलिका में भी शामिल हुआ। जो सेमीकंडक्टर और रेयर अर्थ की सप्लाई को सुनिश्चित करने का लक्ष्य पूरा करेगा। भारत अमेरिका से ट्रेड वार्ता के परिणामों की परवाह न करते हुए अपने लिए मार्ग प्रशस्त कर रहा है। केन्द्र सरकार लगातार भारत के लिए नए बाजार तलाश करने में सफल रही है ताकि अमेरिकी टैरिफ के दुष्प्रभावों का सामना किया जा सके। भारत और ब्राजील में क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमैंट्स समझौता रणनीतिक गेम चेंजर के तौर पर देखा जा सकता है। दुनिया तेजी से इलैक्ट्रिक व्हीकल, ग्रीन एनर्जी और आर्टिफिशियल इंटैलीजैंस की ओर बढ़ रही है। इन सभी सैक्ट्र्स की रीढ़ है लीथियम और रेयर अर्थ। लीथियम और दुर्लभ खनिजों की सप्लाई पर चीन का दबदबा है। यह सझौता सिर्फ व्यापारिक डील नहीं बल्कि सप्लाई चेन की नई भू-राजनीतिक का संकेत है। समुंदर पार से आने वाले संसाधन भारत की औद्योगिकी और तकनीकी प्रगति को नई गति दे सकते हैं। भारत चीन के वर्चस्व को खत्म करने के लिए आगे बढ़ रहा है। यह दोनों देशों के लिए विन विन डील की तरह है। भारत ब्राजील डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सैंटर स्थापित करने के लिए पहले ही काम कर रहा है। दोनों देशों ने 2030 तक अपने द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब डालर के पूर्व लक्ष्य से बढ़ाकर 30 अरब डॉलर करने पर सहमति जताई है। भारतीय कम्पनियां ब्राजील में निवेश के अवसर तलाश सकती हैं। वहीं ब्राजील भारत के बड़े बाजार और तकनीकी सहयोग से लाभ उठाना चाहता है। दोनों कच्चे माल के निर्यातक बनने के बजाय वेल्यू एडीशन और मैन्युफैक्चरिंग में साझेदारी पर जोर दे रहे हैं। लूला डी सिल्वा 260 व्यावसायियों के साथ भारत पहुंचे हैं। इससे साफ है कि यह दौरा कूटनीतिक ही नहीं बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी अहम है।

> **दोनों देश पुराने इतिहास के आधार पर स्वयं में कई आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक ढांचे से जुड़े हुए हैं। लेटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र में ब्राजील भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदारी में से एक है। भारतीय उद्यमियों ने ब्राजील के आईटी औषधि, विज्ञान, ऊर्जा, कृषि, खनन और इंजीनियरिंग क्षेत्र में निवेश किया हुआ है। ब्राजील के उद्यमियों ने भी भारत के ऑटोमोबाइल, ऊर्जा और जैव रसायन में निवेश किया हुआ है। भारत और ब्राजील में रक्षा सहयोग के लिए वर्ष 2003 में हस्ताक्षर किए गये थे। उसके बाद से ही दोनों देशों के रक्षा संबंधों का विस्तार होता गया।**

भारत और ब्राजील ब्रिक्स समूह के संस्थापक देश हैं। इस समूह में रूस, चीन और साउथ अफ्रीका भी शामिल हैं। वर्ष 2024 में इस समूह का विस्तार हुआ और इसमें मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई शामिल हुए। ब्रिक्स को चीन के दबदबे वाला समूह माना जाता है। चीन, रूस और ईरान खुलकर पश्चिम विरोधी बातें करते हैं। दूसरी तरफ सऊदी अरब, यूएई और मिस्र पश्चिम और चीन के बीच संतुलन बनाकर रखते हैं। सभी ब्रिक्स देशों में भारत एकमात्र ऐसा देश है जो पश्चिम से रणनीतिक साझेदारी मजबूत कर रहा है और चीन से तनावपूर्ण संबंधों के चलते भी संतुलन बनाए हुए हैं। महत्वपूर्ण मुद्दों पर भारत और ब्राजील के विचार समान हैं। दोनों ही विकासशील देश एक जीवंत लोकतंत्र होने के नाते बहुध्रुवीय विश्व का समर्थन करते हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति अमेरिका की मनमानी का कड़ा विरोध करते आए हैं। सबसे पहले ब्रिक्स मुद्रा का सुझाव भी उन्होंने ही दिया था। ब्रिक्स द्वारा अपनी मुद्रा चलाये जाने के प्रस्ताव मात्र से ही ट्रंप परेशान हो उठे थे। उन्हें लगता था कि अगर ऐसी कोई नई मुद्रा आ गई तो डॉलर का महत्व कम हो सकता है। हालांकि ब्रिक्स मुद्रा का प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ पाया। दोनों देश ऐसी विश्व व्यवस्था चाहते हैं कि एक या दो महाशक्तियों के नियंत्रण में न हो, बल्कि उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को समान महत्व मिले। भारत की ही तरह ब्राजील भी अंतर्राष्ट्रीय मामलों में किसी एक गुट के साथ बंधने की बजाए राष्ट्रपति हितों को प्राथमिकता देता है। दोनों देश ब्रिक्स के अलावा जी-20, जी-4 जैसे मंचों पर मिलकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए आवाज बुलंद करते रहे हैं।

दोनों देश पुराने इतिहास के आधार पर स्वयं में कई आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक ढांचे से जुड़े हुए हैं। लेटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र में ब्राजील भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदारी में से एक है। भारतीय उद्यमियों ने ब्राजील के आईटी औषधि, विज्ञान, ऊर्जा, कृषि, खनन और इंजीनियरिंग क्षेत्र में निवेश किया हुआ है। ब्राजील के उद्यमियों ने भी भारत के ऑटोमोबाइल, ऊर्जा और जैव रसायन में निवेश किया हुआ है। भारत और ब्राजील में रक्षा सहयोग के लिए वर्ष 2003 में हस्ताक्षर किए गये थे। उसके बाद से ही दोनों देशों के रक्षा संबंधों का विस्तार होता गया। ब्राजील में भारत की संस्कृति, धर्म, कला और दर्शन को लेकर काफी रुचि है। पूरे ब्राजील में योग सिखाने वाले कई संगठन हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और लूला डी सिल्वा के बीच व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे हैं। दोनों की मैत्री बहुपक्षवाद और शांति के समर्थक हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति द्वारा पहलगाम में आतंकी हमले की निंदा करना अपने आप में महत्वपूर्ण है। पिछले वर्ष जब प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील गए थे तो उन्हें ब्राजील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया था। दोनों देश अब नेचुरल पार्टनर हैं। इसी वर्ष वह ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत को सौंपेगा। आने वाले वर्षों में दोनों संबंधों को नई ऊंचाई देंगे। दोनों देश ग्लोबल साऊथ को मबजूत बनाएंगे ताकि दुनिया की दो महाशक्तियों के बीच किसी नए शीत युद्ध जैसी स्थिति न पैदा हो।

चिंघाड़ को जो नीति का नाम बताए...

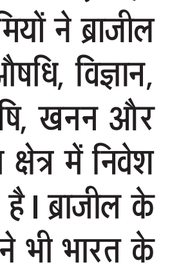

गीता पाढा

"जब जंगल का हाथी दंभ में मतवाला हो जाए,
टैरिफ-टैरिफ इस रोग का ढोल निराला हो जाए,
अपनी ही चिंघाड़ को जो नीति का नाम बताए,
विश्व-बाजार की चौपाल में खुद तमाशा बन जाए...।।"

दमादम मस्त कलंदर, शायर सिद्दीकी और अयूब खां

डा. चन्द्र त्रिखा
chandertrikha@gmail.com

वैसे इकबाल, फैज़, मंटो के मुल्क में भी कई शायर अंधेरे में ही रहे। ऐसा ही यह शायर था सागर सिद्दीकी। विश्वभर में लगभग 300 से अधिक गायकों ने उसका लिखा एक गीत गाया। उसके गायकों में नूरजहां भी थी, रूना लैला भी। वह जन्मा था वर्तमान हरियाणा के शहर अम्बाला छावनी में। उसी शहर में एक मौहल्ला है 'लालकुर्ती'। उसी मौहल्ले में पहली बार, 'दमादम मस्त कलंदर' का विश्व-प्रसिद्ध गीत लिखने वाले शायर सिद्दीकी ने 14 अगस्त 1928 में जन्म लिया था। उसकी मातृभाषा पंजाबी थी मगर 16 वर्ष की उम्र में ही उर्दू के शायर बन गए। उसी मौहल्ले में कुछ वर्ष मंटो ने भी गुजारे थे। उनसे इस शायर को भी मिलवाया गया, तब मंटो ने कहा था, 'अरे कोई और ढंग का काम करो, बाप का सहारा बनो। यह कलम वलम तो सिर्फ दिमाग खराब करती है।'

मगर सागर सिद्दीकी नहीं रुका। उसकी शायरी के तीखे तेवरों को देखते हुए उसे लुधियाना, जालंधर, अमृतसर और सहारनपुर के मुशायरों में बुलाया जाने लगा।

1947 में देश विभाजन के वक्त उनकी उम्र 19 साल थी। वे हिन्दुस्तान छोड़कर पाकिस्तान चला गया और लाहौर में सड़कों पर ज़िन्दगी गुज़ारने लगा। उनकी हालत इतनी ख़स्ता थी कि वे दो-दो रुपए में अपनी गज़लें लोगों को बेच दिया करता था। वे लोग आगे उन गज़लों को अपने नाम से छपवा लिया करते थे।

उन दिनों ही मुम्बई से पाकिस्तान गए फिल्म जगत के कुछ लोगों ने मिलकर फिल्म 'लाल मिर्जा' का निर्माण किया। फिल्म के निर्देशन का भार संगीतकार मास्टर आशिक हुसैन ने अपने ऊपर ले लिया। वे सागर सिद्दीकी को जानते थे। उन्होंने सागर सिद्दीकी से फिल्म के लिए गाना लिखने की फरमाइश की और सागर सिद्दीकी ने 20 साल की उम्र में 'दमादम मस्त कलन्दर' लिखकर मास्टर आशिक़ हुसैन को दे दिया। वैसे इस गीत के मूल रूप की पंक्तियां अमीर खुसरो व बुल्ले शाह के नाम पर भी दर्ज हैं, मगर उसे प्रभावी रूप में व परिवर्द्धित रूप में सागर ने स्वयं भी गाया और एक फिल्म के लिए भी दिया। गीत के बदले उन्हें बीस रुपए दिए गए थे। फिर आशिक़ हुसैन ने इस गीत की धुन बनाई और गायिका नूरजहां से यह गीत गवाया। इसी गीत को गाने के बाद नूरजहां बेहद लोकप्रिय गायिका बन गईं और यहीं से उनका फिल्मों के लिए गायन के क्षेत्र में प्रवेश हुआ। बाद में धीरे-धीरे यह गीत इतना लोकप्रिय हुआ कि सारी दुनिया में छा गया। दुनिया भर के तीन सौ से अधिक गायकों ने यह गीत गाया है लेकिन गीत का रचयिता और संगीतकार दोनों ग़रीब ही रहे। सागर सिद्दीकी भिखारियों के साथ ही सड़क पर रहने लगा। उसे भांग, चरस और गांजे जैसे नशों की आदत पड़ गई थी और वह भीख मांग कर गुज़ारा करते थे और सड़क पर ही रहा करता था। घोर सर्दियों की रात में वे कूड़ा जला कर अपनी ठण्ड भगाया करता था। 19 जुलाई 1974 को सुबह-सवेरे लाहौर में एक दुकान के सामने सड़क पर उसका शव पाया गया था।

उधर मास्टर आशिक़ हुसैन नई इक्कीसवीं सदी में भी ज़िन्दा थे। संगीतकार के रूप में उनकी कोई पूछ नहीं थी। अपने निधन से एक दिन पहले तक वे सड़क पर पकौड़े बनाकर बेचने का ठेला लगाते थे और उसी से अपनी जीविका चलाते थे।

अमृतसर वाले दिनों में सागर ने लकड़ी की कंघी बनाने वाली एक दुकान पर मुलाज़मत कर ली और कंघियां बनाने का फन भी सीख लिया। इस दौरान शेर.गोई का सिलसिला शुरू हो चुका था। शुरू में क़लमी नाम नासिर हिजाज़ी था लेकिन जल्द ही बदलकर सागर सिद्दीक़ी कर लिया। सागर अपने अशआर बेतकल्लुफ दोस्तों को सुनाने लगे। 1944 में अमृतसर में एक ऑल इंडिया मुशायरा मुनअक़िद हुआ जिसमें शिरकत के लिए लाहौर के अनेक शायर भी मदऊ थे। सागर की आवाज़ में बला का सोज़ था, तरन्नुम की रवानी थी जिससे उन्होंने उस मुशायरे में सबका दिल जीत लिया। इस मुशायरे ने उसे रातों-रात शोहरत की बुलन्दी तक पहुंचा दिया। उसके बाद सागर को लाहौर और अमृतसर के मुशायरों में बुलाया जाने लगा। शायरी सागर के लिए 'वजह-ए-शोहरत' के साथ- साथ 'वसीला-ए-रोज़गार' भी बन गई और यूं नौजवान शायर ने कंघियों का काम छोड़ दिया।

विभाजन के बाद सागर अमृतसर से लाहौर चले गए। सागर ने इस्लाह के लिए लतीफ़ अनवर गुरदासपुरी की तरफ रुजूअ किया और उनसे बहुत फ़ैज़ पाया। 1947 से लेकर 1952 तक का ज़माना सागर के लिए सुनहरा दौर साबित हुआ। उसी अरसे में कई रोज़नामों, माहवार अदबी जरीदों और हफ्तावार रिसालों में सागर का कलाम बड़े सम्मान के साथ प्रकाशित होता रहा। फिल्मी दुनिया ने सागर की मक़बूलियत देखी तो कई फिल्म प्रोड्यूसरों ने उनसे गीत लिखने की फरमाइश की और उन्हें माक़ूल मुआवज़ा देने की यक़ीन-दहानी कराई। मगर कभी किसी ने वादा नहीं निभाया।

वर्ष 1952 के बाद सागर की ज़िंदगी खराब सोहबत की बदौलत हर तरह के नशे का शिकार हो गई। वो भंग, शराब, अफ़ग़ून और चरस वग़ैरह इस्तेमाल करने लगे। उसी आलम-ए-मदहोशी में भी मश्क़-ए-सुख़न जारी रहती और सागर गज़ल, नज़्म, क़तआ और फिल्मी गीत हर शैली ए सुख़न में शाहकार तख़लीक़ करता रहा।

उसकी कृतियों में 'ज़हर ए आरज़ू', 'ग़म ए बहार', 'शब ए आगाही', 'तेशा ए दिल', 'लौह ए जुनूं', 'सब्ज़ गुंबद', 'मक़तल ए गुल', 'कुल्लियात ए सागर' शामिल हैं। जनवरी 1975 को वह पक्षाघात का शिकार हो गया। उसकी वजह से उनका दायां हाथ हमेशा के लिए बेकार हो गया। फिर कुछ दिन बाद मुंह से ख़ून आने लगा, जिस्म सूख कर हड्डियों का ढांचा रह गया। सागर सिद्दीक़ी का आख़िरी वक्त दाता दरबार के सामने पायलट होटल के फुटपाथ पर गुज़रा और उसकी मृत्यु 19 जुलाई 1974 की सुबह को उसी फुटपाथ पर हुई। उन्हें म्यानी साहब के क़ब्रिस्तान में दफनाया गया।

एप्स्टीन फाइल का कहर !

विनीत नारायण
www.vineetnarain.net

पिछले हफ्ते तक इंग्लैंड के युवराज रहे प्रिंस एंड्रयूज़ की गिरफ्तारी ने एप्स्टीन फ़ाइल्स में उल्लेखित विश्व की मशहूर हस्तियों और राजनेताओं के दिल की धड़कन बढ़ा दी है। ये एक ऐसा जिन्न है जो फैलता ही जा रहा है। हर रोज़ नए-नए नाम और उनके काले कारनामे उजागर हो रहे हैं। आश्चर्य की बात है कि अमरीका के न्यायिक विभाग ने इन फाइल्स के सामने आने के बाद इनमें शामिल मशहूर हस्तियों से न तो कोई पूछताछ की और न ही उनके ख़िलाफ़ कोई केस दर्ज किए। क्योंकि उस पर अपने ही सत्ताधीशों का दबाव था। ये फ़ाइलें भी 30 जनवरी, 2026 को सामने इसलिए आई हैं, क्योंकि अमरीका के सांसदों ने न्यायिक विभाग पर भारी दबाव बनाया। अभी भी बहुत सारी सूचनाओं को ये विभाग दबाकर बैठा है। अमरीका के जो भी सांसद बारी-बारी से जाकर न्यायिक विभाग में इन फाइलों का निरीक्षण कर रहे हैं वे सदमें में आ जाते हैं। इनमें दुनिया के कुलीन और मशहूर धनाढ्यों और राजनेताओं के नाम शामिल हैं।

आश्चर्य की बात है कि भारत का अधिकतर मीडिया ही नहीं बल्कि अमरीका का भी मुख्य धारा का मीडिया एप्स्टीन फाइल्स को लेकर सामने आ रही दिल दहलाने वाली सूचनाओं को उस तत्परता से प्रकाशित या प्रसारित नहीं कर रहा जैसा किया जाना चाहिए। लगता है कि पैसे और ताक़त के दबाव पर इन सूचनाओं को दबाने का काम जारी है। पर सोशल मीडिया अपनी भूमिका बखूबी निभा रहा है। जिन्हें एप्स्टीन फाइल्स के बारे में अधिक जानकारी नहीं है, वे सोशल मीडिया पर जाकर 'EpsteinFiles' कीवर्ड को खोजेंगे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। ये फाइल्स इतनी भयावह हैं कि अगर इससे जुड़े ताक़तवर लोगों पर क़ानूनी कर्रवाई होना शुरू हो जाए तो अमरीका की राजसत्ता और आर्थिक सत्ता धराशाही हो जाएगी और यही स्थिति अन्य देशों में भी हो सकती है। आज अमरीका के हर बड़े शहर में लाखों नागरिक अपने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के ख़िलाफ़ सड़कों पर भारी प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि इन संदिग्ध फाइल्स में उपलब्ध वीडियो फुटेज में डोनाल्ड ट्रम्प जैसी तमाम बड़ी हस्तियां, छोटी बच्चियों के साथ दिखाई दे रहे हैं हालांकि बच्चियों के यौन शोषण के मामले में उनके विरुद्ध अभी तक कोई प्रमाण सामने नहीं आए हैं। पर लाख टके का सवाल यह है कि जिस नरपिशाच को बच्चियों के साथ पाशविक यौनाचार के मामले में सज़ा मिल चुकी थी उससे ये बड़ी हस्तियां क्यों लगातार मिलती-जुलती रहीं?

आइए जान लें कि जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन कौन था? वो एक अमेरिकी फाइनेंशियर (धन प्रबंधक) और सेक्स क्रिमिनल था। वो न्यूयॉर्क में जन्मा, पढ़ाई में अच्छा था, एक प्राइवेट स्कूल में टीचर रहा, फिर वॉल स्ट्रीट पर 'बियर स्टर्न्स' जैसे बड़े बैंक में काम किया। बाद में उसने अपनी खुद की फर्म बनाई, जहां वो अरबपतियों के पैसे मैनेज करता था। वो बहुत अमीर हो गया और दुनिया के बड़े-बड़े लोगों से उसकी दोस्ती थी, जैसे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू, बिल गेट्स, कई सेलिब्रिटी, वैज्ञानिक और बिजनेसमैन। उसके पास 'लोलिता एक्सप्रेस' नाम का प्राइवेट जेट था। न्यूयॉर्क व फ्लोरिडा में उसके महल जैसे घर और कैरिबियन में एक प्राइवेट द्वीप भी था जहां वो शानदार दावतें देता था, जिनमें दुनियाभर की मशहूर हस्तियां शिरकत करती थीं।

एप्स्टीन पर बच्चियों और नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण और सेक्स ट्रैफिकिंग (बलात्कार/दुष्कर्म का नेटवर्क चलाने) के गंभीर आरोप थे। 2005 में फ्लोरिडा पुलिस ने जांच शुरू की तो एक 14 साल की लड़की ने बताया कि एप्स्टीन ने उसे उसके घर में 'सेक्सुअल मसाज' के बहाने शोषण किया। दर्जनों (कुछ रिपोर्ट्स में 100+ से ज्यादा) नाबालिग लड़कियों ने कहा कि एप्स्टीन उन्हें पैसे देकर 'मसाज' के लिए बुलाता था, फिर सेक्सुअल एक्टिविटी करता था। उसकी पार्टनर घिस्लेन मैक्सवेल पर आरोप था कि वो एप्स्टीन को लड़कियां मुहैया कराती थी। मैक्सवेल को 2021 में दोषी ठहराया गया और उसे 20 साल की सजा हुई और वो अभी जेल में है।

उधर 2008 में एक डील हुई जिसमें एप्स्टीन ने अपना दोष स्वीकार किया और वो गिरफ्तार कर लिया गया। पर वो सिर्फ 13 महीने ही जेल में रहा लेकिन 2019 में एप्स्टीन को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया।

उस पर सेक्स ट्रैफिकिंग केफेडरल आरोप लगे लेकिन फिर जेल में ही उसकी मौत हो गई। बताया गया कि उसने जेल में आत्महत्या कर ली परंतु उसकी मौत संदेहास्पद परिस्थितियों में हुई, क्योंकि उस पर 24 घंटे निगरानी करने के लिए जेल में जो कैमरे लगे थे वो ख़राब हो गए थे, ऐसा बताया गया। इतना ही नहीं उस पर चौकसी से हर वक्त निगाह रखने के लिए तैनात सुरक्षा गार्ड ने भी बताया गया कि सो गए थे। अमरीकी प्रशासन के ये स्पष्टीकरण एप्स्टीन की मौत के कारणों को संदेहास्पद बना देते हैं लेकिन ऑफिशियल रिपोर्ट सुइसाइड की ही है।

2025-2026 में अमेरिका में 'एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट' पास हुआ। जिसके बाद अमरीका के न्यायिक विभाग ने लाखों पेज के डॉक्यूमेंट्स, फोटो, वीडियो रिलीज किए। जिनकी संख्या करीब 35 लाख पेज है। इनमें वो लाखों ईमेल भी हैं जिनका एप्स्टीन और दुनिया के तमाम ताकतवर लोगों के साथ संवाद दर्ज है। कुछ ईमेल तो अनैतिकता की हदें पार करने वाली हैं। इसके अलावा तमाम अबोध बच्चियों के साथ हुए शारीरिक और मानसिक शोषण को दर्शाने वाली तमाम वीडियो और फोटो भी हैं। इससे पता चलता है कि एप्स्टीन अपने हर मेहमान की हर गतिविधि का रिकॉर्ड सम्भाल कर रखता था। ऐसा प्राय: वही लोग करते हैं जो बाद में अपने इन महत्वपूर्ण संपर्कों को ब्लैकमेल करके उनसे बड़े-बड़े लाभ ले सकें।

एप्स्टीन की मौत के बावजूद भी अब ये केस सारी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। गौरतलब है कि एप्स्टीन के सेक्स कांड की पीड़िताओं ने संगठित होकर यह संकल्प लिया है कि अब वे चुप नहीं रहेंगी और हर उस हस्ती का नाम उजागर करेंगी जिसने उनकी कच्ची उम्र की परवाह न करते हुए उनका शारीरिक शोषण किया था। मीर तक़ी मीर का एक शेर है, "इब्तिदा-ए-इश्क़ है रोता है क्या, आगे-आगे देखिए होता है क्या।"

पाकिस्तान का मध्य पूर्व रुख बढ़ा रहा है क्षेत्रीय आतंकवाद का खतरा

सेना दे रही हमास और मुस्लिम ब्रदरहुड का साथ

काबुल, (पंजाब केसरी): पाकिस्तान की सेना हमास और मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे कट्टर इस्लामी समूहों को अपनी गतिविधि जारी रखने के लिए समर्थन दे रही है। इसकी वजह से लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) और जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) जैसे स्थानीय आतंकी संगठनों को समर्थन मिल रहा है और वे गाजा और कश्मीर पर इस्लामिक देशों से सपोर्ट मांग रहे हैं। रविवार को एक रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान का मध्य पूर्व की ओर रुख दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व के पहले से ही अस्थिर क्षेत्रों में गलतफहमी, वैचारिक प्रभाव और प्रॉक्सी संघर्ष के खतरे को बढ़ा देता है। पाकिस्तान लंबे समय से लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसी अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों को समर्थन देता रहा है। भले ही अंतरराष्ट्रीय दबाव में पाकिस्तान ने इन्हें प्रतिबंधित किया, लेकिन ये समूह अब भी सहयोगियों और सामने वाली संरचनाओं के जरिए सक्रिय हैं। पाकिस्तान जब मध्य पूर्व में

> **पाकिस्तान लंबे समय से लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों को समर्थन देता रहा है**

अपनी सुरक्षा उपस्थिति बढ़ाता है और साथ ही इस्लामी आतंकवादी समूहों को खुले समर्थन देता है, तो यह समस्या सिर्फ दक्षिण एशिया तक सीमित नहीं रहती, बल्कि क्षेत्रीय बन जाती है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि पाकिस्तान के राजनीतिक और धार्मिक प्लेटफॉर्म हमास का समर्थन कर रहे हैं। जनवरी 2024 में पाकिस्तान की संसद ने हमास के प्रतिनिधि खालेद कद्दूमी का स्वागत किया और फरवरी 2025 में उन्होंने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान हमास की मेजबानी कर स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों को पश्चिमी देशों, इजराइल और भारत के खिलाफ एकजुट कर रहा है। अमेरिका और यूरोपीय संघ समेत कई देशों ने हमास को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। इसके इतर पाकिस्तान में उन्हें सम्मानित अतिथि के रूप में देखना दो खतरे पैदा करता है। पहला, पाकिस्तान का घरेलू इस्लामी नेटवर्क अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के लिए आकर्षक बन सकता है। दूसरा, दुनिया में पाकिस्तान की छवि आतंक समर्थक राष्ट्र के रूप में और मजबूत होती है। रिपोर्ट में कहा गया, "हमास और मुस्लिम ब्रदरहुड द्वारा पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों को समर्थन देने को लेकर चिंता जताई गई है। पाकिस्तान में इन प्रतिबंधित इस्लामी संगठनों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी यह दर्शाती है कि लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद को व्यवस्थित और सक्रिय समर्थन प्रदान किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश के विश्वविद्यालयों में होगी मंदिर प्रबंधन की पढ़ाई : मोहन यादव

इंदौर, (पंजाब केसरी): मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रविवार को घोषणा की कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देकर अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए राज्य के विश्वविद्यालयों में मंदिर प्रबंधन को विषय के तौर पर पढ़ाया जाएगा। यादव ने इंदौर में संवाददाताओं से कहा, 'हम मंदिर प्रबंधन को एक विषय के तौर पर विश्वविद्यालयों की पढ़ाई से जोड़ रहे हैं। हमने मंदिर प्रबंधन विषय पर अकादमिक पाठ्यक्रम संचालित करने का निर्णय किया है।' उन्होंने बताया कि इन पाठ्यक्रमों में धार्मिक पर्यटन के साथ ही मंदिरों की वित्तीय व प्रशासनिक व्यवस्था, सुरक्षा आदि की पढ़ाई कराई जाएगी। यादव ने बताया कि इस सिलसिले में उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय ने पहल करते हुए मंदिर प्रबंधन विषय पर डिप्लोमा और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पेश किए हैं जिनके जरिये विद्यार्थियों को विद्वानों के जरिये सैद्धांतिक और व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा, 'मंदिर हमेशा से हमारे लिए आस्था, श्रद्धा और विश्वास के केंद्र रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि मंदिरों के उचित प्रबंधन के जरिये किस तरह अर्थव्यवस्था को गति दी जा सकती है।'

यादव ने कहा कि उज्जैन के 'श्री महाकाल महालोक' की तर्ज पर राज्य के 13 तीर्थस्थलों पर धार्मिक गलियारे बनाए जा रहे हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने 'श्री महाकाल महालोक' परिसर से फाइबर की मूर्तियां हटाकर वहां पत्थरों और धातुओं की प्रतिमाएं लगाने का फैसला किया है।

मुख्यमंत्री ने बताया, 'देश की प्राचीन स्थापत्य कला पर आधारित ये प्रतिमाएं उज्जैन में ही गढ़ी जा रही हैं। इससे स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिल रहा है।'

ओडिशा के बंगाली बहुल गांवों में बाल विवाह के मामले बढ़े

केंद्रपाड़ा, (पंजाब केसरी): ओडिशा में केंद्रपाड़ा जिले के तालचुआ क्षेत्र में बाल विवाह के मामले उजागर होने के बाद शासन प्रशासन अलर्ट हो गया है। बाल विवाह पर रोकथाम के लिए अब इस क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाया गया। किशोर लड़के-लड़कियों के साथ ही परिजनों को बाल विवाह न करने की शपथ दिलाई गई। दरअसल, पिछले सोमवार को प्रकाशित एक विशेष रिपोर्ट में राजनगर ब्लॉक के तालचुआ मरीन पुलिस स्टेशन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बंगाली बहुल गांवों में बाल विवाह में बढ़ोतरी को उजागर किया था। हालांकि बाल विवाह परिवार की सहमति से किए जाते हैं। यह मुद्दा प्रशासन के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गया है और अधिकारियों ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए केरुपाल और रंगानी गांवों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

दिल्ली आर.एन.आई. नं. 40474/83

पंजाब केसरी

दिल्ली कार्यालय :

फोन आफिस: 011-30712200, 45212200,
प्रसार विभाग: 011-30712224
विज्ञापन विभाग: 011-30712229
सम्पादकीय विभाग: 011-30712292-93
मैगजीन विभाग: 011-30712330
फैक्स : 91-11-30712290, 30712384, 011-45212383, 84
Email: Editorial@punjabkesari.com

स्वत्वाधिकारी दैनिक समाचार लिमिटेड, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, नजदीक वजीरपुर डीटीसी डिपो, दिल्ली-110035 के लिए मुद्रक, प्रकाशक तथा सम्पादक अनिल शारदा द्वारा पंजाब केसरी प्रिंटिंग प्रैस, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से मुद्रित तथा 2, प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से प्रकाशित।

रामायण

राम की आंखों में प्रेम के आंसू आ गए

**तुलसी उठे अवलोकी कारन,
काह चित सोचत रहे।
सब समाचार किरात कोलन्हि,
आई तेहि अवसर दिये।**

भगवान राम कारण की खोज करते-करते कि यह क्या है? तभी भील दौड़ते हुए आकर कहते हैं कि महाराज। अयोध्या से राजकुमार भरत जी शत्रुघ्न जी आ रहे हैं। तो तुलसी जी जैसे उस समय गवाह हो वैसे लिखते हैं।

सुनत सुमंगल बैन मम प्रमोद तन पुलक भर।

शरीर पुलकित हो गया मन आनन्दित हो उठा। रामजी की स्थिति देखकर तुलसी जी को लगा।

शराब सरो रूह नैन तुलसी भरे स्नेह जल।

राम की आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। मेरा भाई आ रहा है। भगवान बहुत खुश हुये। फिर तुलसी जी लिखते हैं-

**बहुरि सोच बस भे सियरबनू। कारन कवन भरत आगमनू।।
एक आई अस कहा बहोरी। से संग चतुरंग न थोरी॥**

दूसरे क्षण राम विचार करने लगे कि भरत क्यों आ रहा होगा।? तभी एक भील ने सूचना दी भरत जी अकेले नहीं आ रहे हैं। साथ में चतुरंगिणी सेना भी है। चतुरंगिणी सेना शब्द सुनते ही राघवेन्द्र थोड़ी देर के लिए सोचने लगे। सेना साथ है तो महज मेरे साथ युद्ध करने आ रहा है। ऐसा विचार राम को नहीं आया। वे सोचने लगे कि सेना लेकर आया है इसका मतलब यह है कि मुझे राज गद्दी सौंपने आया है। क्योंकि राजनीति का नियम है जिसे गद्दी सौंपे, उसकी सेना भी सौंप दी जाय। राम सोचते हैं कि मैं भाई का प्रेम देखें या पिता की आज्ञा को मानूं। ऐसी असमंजस्ता राम के मन में पैदा हुई। थोड़े ही समय बाद राम का मन स्थिर हो गया। पर इस थोड़े समय में उनके चेहरे पर बदलते भाव लक्ष्मण जी ने देखे। उन्होंने दबा हुआ क्रोध प्रकट किया।

मोरारी बापू जी

लखन लखेऊ प्रभु हृदय खभारू।

राम जी के हृदय में दु:ख हो उठा है। अत: लक्ष्मण जी खड़े हो कर बोले, महाराज, आज पूछे बिना बोल रहा हूं। अविवेक हो तो क्षमा करना। भरत और शत्रुघ्न चतुरंगिणी सेना लेकर आ रहे हैं तो महाराज उसका हिसाब बहुत स्पष्ट है कि वे निष्कटक राज्य करने निकले हैं। उन दोनों ने माना होगा कि राम अकेले हैं उसे मार डालेंगे जिससे चौदह वर्ष बाद भी हमारे राज्य में कोई भाग लेने न आये, पर महाराज उसे पता नहीं है कि लक्ष्मण भी साथ गया है। आखिर है तो कैकेयी का लड़का, उसे दूसरा विचार आ ही नहीं सकता। उसमें भरत का भी दोष नहीं है-

विषयी जीवी पायी प्रभुताई।

महाराज, विषय जीव को बड़ी वस्तु मिलने पर अहंकार आ जाता है। उसका उदाहरण देखिए-

**राशि गुरतियगामी नहुष चढेऊ भूमिसुर जान।
लोक वेद ने विमुखभा अधम न वेन समान॥**

जगत में जिसे बड़ी वस्तुएं मिलती है प्रभु वे लोग होश हवास खो बैठते हैं। (क्रमश:)

जो जय और पराजय को समान भाव से गले लगाता है

सच्चा खिलाड़ी वह होता है, जो जय और पराज्य को समान भाव से गले लगाता है। सच्चा खिलाड़ी जय में फूलता नहीं है और पराज्य में पीड़ा की प्रतिमा नहीं बनता है। वह जय और पराज्य को खेल का अनिवार्य अंग मानता है। स्थित-प्रज्ञ व्यक्ति भी जीवन को एक खेल से अधिक कुछ नहीं मानता। वह जानता है सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। सुख भी अस्थिर है और दुख भी अस्थिर है। सम्मान भी अस्थिर है और असम्मान भी अस्थिर है। समृद्धि भी अस्थिर है और असमृद्धि भी अस्थिर है। धूप और छांव का खेल है जीवन। अनिवार्य अंग है ये जीवन के। फिर कैसा शोक? कैसा हर्ष? स्थित-प्रज्ञ अपनी प्रज्ञा में स्थिर बन जाता है। बाहर में घट रही घटनाएं उसे चलित नहीं करती हैं। बाहर में जो घट रहा है, उसे घटते हुए को वह द्रष्टा बनकर देखता रहता है। उसके साथ वह अपने चित्त को संलग्न नहीं बनाता है। वह संसार में ऐसे रहता है जैसे कमल में कीचड़ में रहता है। कीचड़ में जन्म लेकर और कीचड़ में रहकर भी कमल कीचड़ से असम्पृक्त रहता है। वैसे ही स्थित-प्रज्ञ संसार में रहकर संसार से ऊपर रहता है। संसारी व्यक्ति थोड़े से सुख में फूल जाता है और थोड़े से दुख में दुख रूप बन जाता है। थोड़ा-सा लाभ उसे आसमान पर आरोहित कर देता है और थोड़ा-सा अलाभ उसे रसातल में गिरा देता है। संसारी व्यक्ति इस तथ्य को नहीं जानता है कि सुख या दुख, हानि या लाभ सतह पर घटने वाली घटनाएं है। हमारे भीतर, हमारी अंतराला तक सुख और दुख की पहुंच नहीं है। ऊपरी लहरें हैं सुख और दुख। सुख, दुख, हानि, लाभ, समृद्धि, असमृद्धि, सम्मान, असम्मान आदि के संवेदनों से यदि हमें मुक्त होना है तो हमें समता के शास्त्र को आत्मशास्त्र बनाना होगा। स्थित-प्रज्ञता के सूत्र को आत्मसूत्र बनाना होगा। स्थित-प्रज्ञता को उपलब्ध व्यक्ति शीघ्र ही परमात्म-ध्येय परमात्म-पद को उपलब्ध बन जाता है। कर्म ही वह मूल कारण है जो आत्मा को संसार में बांधकर रखता है। कर्म से मुक्त हुए बिना आत्मा संसार से मुक्त नहीं हो सकती है। संसार में रहीं हुई सभी आत्माएं कर्म सेॅबंधी हैं। कोई राजा हो रंक हो, छोटा हो या बड़ा हो, सुरूप हो या कूरूप हो, सुखी हो या दुखी हो सभी कर्म में बंधे हैं। केवल मनुष्य और पशु जगत के ही प्राणी कर्मों के पाश में बद्ध नहीं है, देवलोक के देवता भी कर्म में बंधे हैं। जैसे पशु परतंत्र हैं, कर्मों के अधीन हैं, वैसे ही मनुष्य भी कर्मों के अधीन हैं। जैसे मनुष्य कर्मों के अधीन हैं वैसे ही देव भी कर्मों के अधीन हैं, परतंत्र हैं। जब पशु मनुष्य और देव तीनों ही समान रूप से कर्मों के अधीन हैं, परतंत्र है तो फिर तीनों में विभेद क्यों? यह प्रश्न विचारणीय है। यदी थोड़ा गहरमें हम चिंतन करेंगे तो पाएंगे की न देवता अधिक दुखी है न पशु अधिक दुखी हैं इनके मध्य में थोड़ा अंतर है। वह अंतर ऐसा है कि एक कैदी तृतीय श्रेणी के कारागृह में बंद हो और दुसरा प्रथम श्रोणी के कारागृह में बंद हो कि एक कैदी लोहे की बेड़ीयों में बंधा हो और दुसरा सोने की बेड़ीयों में बंधा हो। (क्रमश:)

मुनि मणिभद्र

क्या शरीर का विक्षेद होना मात्र मोक्ष है?

सत्यार्थ प्रकाश

आर्य समाज का महान ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश जिसके रचयिता स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं, में जीवन को सही दिशा में ले जाने के सूत्र हैं और अगर इंसान इसे पढ़े और इसकी शिक्षाओं पर चले तो मानव का कल्याण तो होगा ही बल्कि समाज में भी कुरीतियां दूर होंगी और नैतिक संस्कारों का उजाला होगा। पाठकों की भारी मांग पर इसे प्रस्तुत किया जा रहा है।

यदि कंटक आदि से उत्पन्न ही दुख का नाम नरक हो, तो उससे अधिक महारोगादि नरक क्यों नहीं? यद्यपि राजा को ऐश्वर्यवान और प्रजा पालन में समर्थ होने से श्रेष्ठ मानें तो ठीक है, परंतु जो अन्यायकारी पापी राजा हो उसको भी परमेश्वरवत् मानते हो, तो तुम्हारे जैसा कोई भी मूर्ख नहीं। शरीर का विच्छेद होना मात्र मोक्ष है, तो गधे, कुत्ते आदि तुममें क्या भेद रहा? न कोई स्वर्ग, न कोई नरक और न कोई परलोक में जाने वाली आत्मा है और न वर्णाश्रम की क्रिया फलदायक है ॥ 2 ॥

जो यज्ञ में पशु को मार होम करने से वह स्वर्ग को जाता है, तो यजमान अपने पिता आदि को मार होम करके स्वर्ग को क्यों नहीं भेजता?॥ 3 ॥ जो मरे हुए जीवों का श्राद्ध और तर्पण तृप्तिकारक होता है, तो पर देश में जाने वाले मार्ग में निर्वाहार्थ अन्न-वस्त्र और धनादि को क्यों ले जाते हैं? क्योंकि जैसे मृतक के नाम से अर्पण किया हुआ पदार्थ स्वर्ग में पहुंचता है, तो परदेश में जाने वालों के लिए उनके संबंधी भी घर में उनके नाम से अर्पण करके देशांतर में पहुंचा दे, जो यह नहीं पहुंचता तो स्वर्ग में वह क्यों कर पहुंच सकता है।। 4 ॥

जो मर्त्यलोक में दान करने से स्वर्गवासी तृप्त होते हैं, तो नीचे देने से घर के ऊपर स्थित पुरुष तृप्त क्यों नहीं होता?॥ 5 ॥ इसलिए जब तक जीएं तब तक सुख से जीएं। जो घर में पदार्थ न हो तो ऋण लेकर आनंद करे। ऋण देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिस शरीर में जीव ने खाया-पिया है, उन दोनों का पुनरागमन न होगा। फिर किससे कौन मांगेगा और कौन देगा?॥ 6 ॥

जो लोग कहते हैं कि मृत्यु समय जीव निकलकर परलोक को जाता है यह बात मिथ्या है, क्योंकि जो ऐसा होता तो कुटुंब के मोह से बद्ध होकर पुन: घर में क्यों नहीं आ जाता॥ 7 ॥

(उत्तर.) बिना चेतन परमेश्वर के निर्माण किए जड़ पदार्थ स्वयं आपस में स्वभाव से नियमपूर्वक मिलकर उत्पन्न नहीं हो सकते। जो स्वभाव से ही होते हों, तो द्वितीय सूर्य, चंद्र, पृथ्वी और नक्षत्रादि लोक आपसे आप क्यों नहीं बन जाते हैं ॥1 ॥

स्वर्ग सुख भोग और नरक दुख भोग का नाम है। जो जीवात्मा न होता तो सुख-दु:ख का भोक्ता कौन हो सके? जैसे इस समय सुख-दुख का भोक्ता जीव है वैसे परजन्म में भी होता है। क्या सत्य भाषण और परोपकारादि क्रिया भी वर्णाश्रमियों की निष्फल होगी? कभी नहीं ॥ 2 ॥

पशु मारकर होम करना वेदादि सत्य शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा और मृतकों का श्राद्ध तर्पण करना कपोल कल्पित है, क्योंकि यह वेदादि सत्य शास्त्रों के विरुद्ध होने से भागवतादिपुराणमत वालों का मत है, इसलिए इस बात का खंडन अखंडनीय है ॥3 ॥4 ॥ यजमान की कन्या से हंसी-ठट्ठा आदि करना सिवाय वाममार्गी लोगों से अन्य मनुष्यों का काम नहीं है। कार्य कारण भाव अर्थात कार्य के दर्शन से कारण और कारण के दर्शन से कार्यादि का साक्षात्कार प्रत्यक्ष से, शेष में अनुमान होता है।

इसके बिना प्राणियों के संपूर्ण व्यवहार पूर्ण नहीं हो सकते इत्यादि लक्षणों से अनुमान को अधिक मानकर चारवाक से भिन्न शाखा बौद्धों की हुई हैं। बौद्ध चार प्रकार के हैं-एक 'माध्यमिक,' दूसरा 'योगाचार,' तीसरा सौत्रांतिक और चौथा 'वैभाषिक।' 'बुद्धया निर्वर्त्तते स बौद्ध:' जो बुद्धि से सिद्ध हो अर्थात जो बात अपनी बुद्धि में आए उसको माने और जो बुद्धि में न आए उसको नहीं माने। इनमें से पहला 'माध्यमिक' सर्वशून्य मानता है अर्थात जितने पदार्थ हैं वे सब शून्य अर्थात आदि में नहीं होते, अंत में नहीं होते। (क्रमश:)

आशीर्वाद देने के लिए दाहिने हाथ का महत्व क्यों?

जब कोई बड़े-बुजुर्ग हमारे सिर पर हाथ रखकर खुश रहो या सदा सफल हो कहता है, तो उस पल में एक अजीब-सी गर्माहट महसूस होती है। यह सिर्फ शब्दों का असर नहीं होता, बल्कि स्पर्श की वह ऊर्जा होती है जिसे हम बचपन से महसूस करते आए हैं। दिलचस्प बात यह है कि लगभग हर संस्कृति और हर घर में आशीर्वाद देने का यही तरीका दिखता है- दाहिने हाथ से क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों? क्या यह केवल परंपरा है, या इसके पीछे कोई गहरा अर्थ और तर्क भी छिपा है? दरअसल, भारतीय मान्यताओं में दाहिने हाथ से आशीर्वाद देने की परंपरा ज्योतिष, योग और व्यवहारिक विज्ञान तीनों से जुड़ी बताई जाती है। यही वजह है कि यह आदत पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और आज भी उतनी ही स्वाभाविक लगती है।

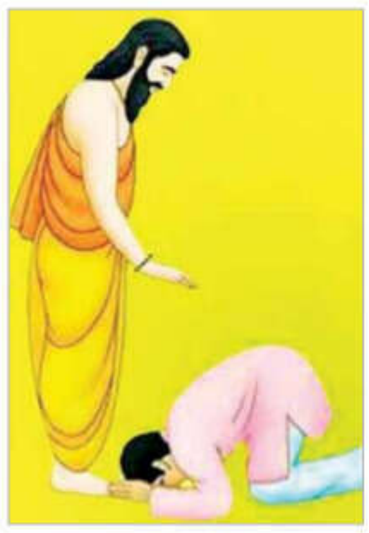

सकारात्मक ऊर्जा का संचार

प्राचीन शास्त्रों और ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, मानव शरीर ऊर्जा का एक केंद्र है। हमारे दाहिने हाथ में सकारात्मक ऊर्जा होती है। जब कोई सिद्ध पुरुष या बड़ा व्यक्ति अपना दाहिना हाथ हमारे सिर पर रखता है, तो उनके शरीर की संचित ऊर्जा और शुभ संकल्प एक विद्युत प्रवाह की तरह हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। आशीर्वाद देते समय अंगुलियों के पोरों से जो ऊर्जा निकलती है, वह सीधे व्यक्ति के सहस्त्रार चक्र पर प्रहार करती है, जिससे मानसिक शांति का अनुभव होता है।

मस्तिष्क का विज्ञान

हमारे मस्तिष्क की बनावट भी इस परंपरा का समर्थन करती है। हमारा शरीर क्रॉस-कनेक्टेड है। बायां मस्तिष्क शरीर के दाहिने हिस्से को नियंत्रित करता है। बायां मस्तिष्क तर्क, शुद्धि और अनुशासन का केंद्र है। इसलिए, जब हम दाहिने हाथ का इस्तेमाल करते हैं, तो वह हमारी चेतना और सक्रियता को दर्शाता है।

सूर्य स्वर और चंद्र स्वर

योग विज्ञान के अनुसार, हमारे शरीर में दो मुख्य नाड़ियां होती हैं- इड़ा और पिंगला। दाहिना हिस्सा पिंगला नाड़ी यानी सूर्य स्वर से जुड़ा होता है। सूर्य तेज, शक्ति और आरोग्य का प्रतीक है। दाहिने हाथ से आशीर्वाद देने का अर्थ है कि देने वाला अपनी सूर्य शक्ति के जरिए सामने वाले को आरोग्य और सौभाग्य का दान कर रहा है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार, दान, संकल्प और आशीर्वाद जैसी सात्विक क्रियाएं हमेशा सूर्य स्वर की प्रधानता में ही फलदायी होती हैं।

धार्मिक और सामाजिक कारण

पूजा-पाठ से लेकर भोजन करने तक, दाहिने हाथ को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि इसे शुद्ध हाथ माना जाता है। बाएं हाथ का उपयोग आमतौर पर शरीर की सफाई के कार्यों में किया जाता है, इसलिए उसे ऊर्जा के आदान-प्रदान के लिए उपयुक्त नहीं माना गया है। दाहिना हाथ कर्मठता और धर्म का प्रतीक है। जब कोई सिद्ध पुरुष या बड़ा व्यक्ति अपना दाहिना हाथ हमारे सिर पर रखता है, तो उनके शरीर की संचित ऊर्जा और शुभ संकल्प एक विद्युत प्रवाह की तरह हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। आशीर्वाद देते समय अंगुलियों के पोरों से जो ऊर्जा निकलती है, वह सीधे व्यक्ति के सहस्त्रार चक्र पर प्रहार करती है, जिससे मानसिक शांति का अनुभव होता है।

कोई दुआ ऐसी नहीं जिसमें...

फजाइले अमाल

हजरत अली रजि. पैगंबर साहब का यह इर्शाद नकल करते हैं, कोई दुआ ऐसी नहीं है कि जिसमें और अल्लाह के दर्मियान हिजाब न हो। यहां तक कि पैगंबर साहब पर दरूद भेजे। पर जब वह ऐसा करता है, तो वह पर्दा फट जाता है और वह महल्ले इजाबत में दाखिल हो जाती है वरना लौटा दी जाती है। इब्ने अता रह. कहते हैं कि दुआ के लिए कुछ अरकान हैं और कुछ पर हैं, कुछ अस्बाब हैं और कुछ औकात हैं। अगर अरकान के मुवाफिक होती है, तो दुआ कवी होती है और परों के मुवाफिक होती है तो आसमान पर उड़ जाती है और अगर अपने औकात के मुवाफिक होती है, तो फाइज होती है और अस्बाब के मुवाफिक होती है तो कामयाब होती है। दुआ के अरकान- हुजूरे कल्ब, रिक्कत, आजिजी, खुशूअ और अल्लाह के साथ कल्बी ताल्लुक है और इसके पर 'सिद्क' है और इसके औकात रात का आखिरी हिस्सा और इसके अस्बाब पैगंबर साहब पर दरूद भेजना। और भी मुतअद्दिद अहादीस में यह मज्मून आया है कि दुआ रुकी रहती है जब तक कि हुजूर सल्ल. पर दरूद न भेजे। हजरत अब्दुल्लाह बिन अबी औफा रजि. फरमाते हैं कि एक मर्तबा हुजूर सल्ल. बाहर तशरीफ लाए और यों इर्शाद फरमाया कि जिस शख्स को कोई हाजत अल्लाह तआला शानुहू से या किसी बंदे से पेश आ जाए, तो उसको चाहिए कि अच्छी तरह वुजू करे और दो रक्अत नमाज पढ़े, फिर अल्लाह जल्ल शानुहू पर हम्द व सना करे और पैगंबर साहब पर दरूद भेजे, फिर यह दुआ पढ़े : नहीं कोई माबूद बजुज अल्लाह के जो बड़े हिल्म वाला है और बड़े करम वाला है, हर ऐब से पाक है अल्लाह, जो रब है अर्शे अजीम का। तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं, जो रब है सारे जहानों का। ऐ अल्लाह! मैं तुझसे सवाल करता हूं उन चीजों का, जो तेरी रहमत को वाजिब करने वाली हों और मांगता हूं तेरी मग्फिरत की मुअक्किदात को (यानी ऐसे आमाल को, जिनसे तेरी मग्फिरत जरूरी हो जाए) और मांगता हूं हिस्सा हर नेकी से और सलामती हर गुनाह से। (क्रमश:)

केसरी सूडोकू- 5098

			2		3		5	
		4	7			8	6	
			9				7	3
6		8	1					4
1					4	3		7
5	7				1			
	6	3			8	7		
	1		4		7			

हल करने का तरीका

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं। इनका क्रमवार होना आवश्यक नहीं है।
- आड़ी व खड़ी पंक्ति में और 3x3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें।
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते।

सूडोकू 5097 का हल

5	1	9	3	7	2	6	4	8
2	4	8	1	6	5	7	3	9
7	6	3	4	8	9	2	5	1
4	9	7	2	1	3	5	8	6
8	3	1	6	5	7	4	9	2
6	2	5	8	9	4	1	7	3
9	8	2	5	4	1	3	6	7
1	7	4	9	3	6	8	2	5
3	5	6	7	2	8	9	1	4

बाइबल की कहानियां

धार्मिक मुखौटे के पीछे क्या है?

क्या ईश्वर के बारे में आपका नज़रिया सृष्टि के पहले तीन दिनों से मेल खाता है? क्या वह इतना बड़ा है, या उससे छोटा? अगर हाँ, तो आपके विचार में उसके साथ जीवन में क्या हुआ है? (इस प्रश्न के प्रति ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। धार्मिक मुखौटे के पीछे छिपने से कोई मदद नहीं मिलेगी।) अगर आप सचमुच परमेश्वर के प्रत्यक्ष सृजनात्मक कार्य का हिस्सा न होते, तो आपका जीवन कितना अलग होता? अगर मछली ज़मीन पर अकेले रेंगकर आती, तो क्या होता? यह कहना कि परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का रचयिता है, एक बहुत ही आम बात है। हम इस कथन की विशालता को समझने में एक-दूसरे की मदद कैसे कर सकते हैं? परमेश्वर बोलता है, और समय शुरू होता है। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति से बात की है जो अपनी कुंडली पर सच्चा विश्वास करता हो? उनके साथ इस बारे में बात करना कैसा रहा? उन्हें क्यों लगता है कि सितारे उनके जीवन को नियंत्रित करते हैं? ईश्वरविहीन विकासवाद का एक परिणाम यह है कि लोग खुद को खोया हुआ, खाली, अर्थहीन, प्रकृति की एक दुर्घटना महसूस करते हैं। आप उन्हें सृष्टि की बाइबिल की कहानी किस तरह से बता सकते हैं जिससे उन्हें मदद मिले। शायद आपको अपने समूह में थोड़ी भूमिका निभानी चाहिए। बहुत से लोग मानते हैं कि वे स्वाभाविक रूप से अच्छे हैं। दूसरे शब्दों में, वे यह नहीं समझते कि उनकी अच्छाई ईश्वर की रचनात्मक गतिविधि और इस घोषणा से उत्पन्न होती है कि वह उन्हें अच्छा बनाता है। क्या आपने कभी उनसे पूछा है कि ऐसा क्यों है? यह एक उपयोगी चर्चा हो सकती है। वे क्यों सोचते हैं कि वे अच्छे हैं, खासकर उस इतिहास के आलोक में जिसमें एक के बाद एक विनाशकारी युद्ध हुए हैं। अपने आस-पास की दुनिया, चाहे स्कूल हो या मीडिया, इस विचार पर कैसे हमला करती है कि हमारे ईश्वर ने ही सब कुछ बनाया है, इस बारे में कुछ कहानियाँ बताएँ। आप बातचीत को इस हद तक कैसे ले जा सकते हैं कि आप उन्हें बता सकें कि वे अपने हृदय में पाप का जवाब दे रहे हैं (बहुत सावधानी से नहीं)? अपने जीवन के उन पलों को साझा करें जब ईश्वर इतने छोटे हो गए हों कि इस दुनिया के देवता ज़्यादा शक्तिशाली और आमंत्रित लगने लगे हों। कृपया ईमानदारी से बताएँ। आप पर और शायद आपके परिवार पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? (क्रमश:)

अब दानियों के अनुरोध पर 'एक मिशन एक सेवा' का प्रकाशन प्रतिदिन किया जा रहा है ताकि दानदाता अपने प्रियजनों के जन्मदिन, पुण्यतिथि, वैवाहिक वर्षगांठ या किसी खास मौके की तिथि विशेष पर अपनी इच्छानुसार दान राशि प्रकाशित करा सकें।

एक मिशन एक सेवा

बुढ़ापा जीवन का अटल सत्य है। गरीबी, बीमारियां, तथा अपनों का मुंह फेर लेना, इसे अभिशाप बना देते हैं। आईये! ऐसे बुजुर्गों का सहारा बनें। सुखी-सम्पन्न लोगों के सहयोग से इनका अकेलापन, दु:ख दूर किये जा सकते हैं। ताकि भावी पीढ़ी इनसे प्रेरणा ले सकें।

दानियों के लिए विशेष सूचना

वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के लिए दान देने वाले सज्जन अब देशभर में **पंजाब नैशनल बैंक** की किसी भी शाखा में जाकर सहायता राशि जमा करवा सकते हैं, इसके लिए ध्यान रखें कि उक्त राशि **वृद्ध केसरी, रोमेश चंद्र ट्रस्ट के अकाऊंट नंबर** 3075002102006705 में देय होनी चाहिए। हमारा अनुरोध है कि सहायता राशि जमा करवाने के बाद हमें सूचित जरूर करें, ताकि रसीद भेजी जा सके। यह राशि आयकर छूट प्राप्त है। **जो सज्जन पंजाब नैशनल बैंक की किसी शाखा में नकद राशि जमा कराएं, वे बैंक की रसीद हमें कोरियर करा दें, ताकि आपको हम रसीद भेज सकें। सभी दानकर्ताओं से अनुरोध है कि दान भेजते समय पूरा पता, टेलीफोन नंबर और पैन कार्ड नंबर भी साथ में लिखें।**

दिल्ली के बाहर के दानकर्ता 500/- रुपए से कम की दानराशि कृपया ड्राफ्ट या मनीआर्डर से ही भेजें

कृपया अपना ड्राफ्ट या चैक **वृद्ध केसरी रोमेश चंद्र ट्रस्ट**, के नाम बना कर हमें भेजें। सभी दानी सज्जनों के नाम प्रति दिन प्रकाशित किए जाएंगे। लेकिन फोटो 5100/- या इससे अधिक की दान राशि देने वाले सज्जनों के प्रकाशित किए जाएंगे। दान के लिए पंजाब केसरी कार्यालय में प्रात: 10 से 5.30 बजे तक सम्पर्क करें।

*** यह राशि आयकर कानून की धारा 80-जी के अन्तर्गत करमुक्त है!**

पता :- वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब
2, प्रिंटिंग प्रेस काम्प्लेक्स, नियर वजीरपुर डिपो, दिल्ली-35

दान के लिए कृपया 01130712376, 09871598497, 9810107375 पर संपर्क करें। यदि कोई सज्जन या संस्था हमारे नाम से पैसा इकट्ठा करे तो इसका जिम्मेदार वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब नहीं होगा।

किसी के मदद मांगने पर उसे ज्यादा उपदेश की नहीं, संभव हो तो मदद दीजिए।

संपादकीय

अहंगंडग्रस्त नेत्याला वेसण

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी राबविलेल्या आक्रमक आयात शुल्क (टॅरिफ) धोरणाला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला धक्का, एका अहंगंडग्रस्त नेत्याला घातलेली वेसण तर आहेच, सोबतच तो जागतिक व्यापार व्यवस्थेतील संस्थात्मक संतुलनाच्या पुनर्स्थापनेचा क्षणही सिद्ध होऊ शकतो. ट्रम्प यांनी 'रेसिप्रोकल' या आकर्षक, पण भ्रामक संकल्पनेच्या आडून ज्या पद्धतीने आयात शुल्कांची सरबत्ती केली, त्यातून जागतिक व्यापाराचे समीकरणच ढवळून निघाले होते. त्या पार्श्वभूमीवरील न्यायालयाचा निर्णय संवैधानिक मर्यादांची आठवण करून देणारा आणि कार्यपालिकेच्या अतिरेकाला लगाम घालणारा म्हणावा लागेल. ट्रम्प यांचे प्रतिपादन असे की, अमेरिका दीर्घकाळ 'अन्यायकारक' व्यापार व्यवस्थेची बळी ठरली आहे आणि इतर देशांनी अमेरिकन बाजारपेठेचा लाभ घेतला. त्यांनी राष्ट्रीय आपत्कालीन अधिकारांचा वापर करून भारतासह अनेक देशांवर भरमसाट आयात शुल्क लादले. अमेरिकन काँग्रेसची मान्यता न घेताच हे धोरण राबविण्यात आले. न्यायालयाने याच मुद्द्यावर बोट ठेवले. व्यापार कर लादण्याचा विधिमंडळाचा अधिकार कार्यपालिकेने आपल्या हाती घेणे संविधानाच्या चौकटीबाहेरचे आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणामुळे जागतिक पुरवठा साखळ्या विस्कळीत झाल्या, उत्पादन खर्च वाढले आणि महागाईला खतपाणी मिळाले. अशात न्यायालयाने दिलेला निर्णय बाजारव्यवस्थेसाठी दिलासादायक आहे. या निर्णयानंतर ट्रम्प यांनी न्यायपालिकेवरच टीकास्त्र डागत, पर्यायी कायद्यांचा आधार घेऊन पुन्हा टॅरिफ वाढविण्याची घोषणा केली. ट्रम्प यांचा आक्रमक पवित्रा केवळ आर्थिक नसून राजकीय आहे. भारतासाठी या घडामोडींचे परिणाम बहुआयामी आहेत. भारतावरील ५० टक्के आयात शुल्कामुळे निर्यात क्षेत्रात अनिश्चितता निर्माण झाली होती. पोलाद-ॲल्युमिनियम, अभियांत्रिकी उत्पादने, औषधनिर्मिती आणि वस्त्रोद्योगासारख्या क्षेत्रांवर अप्रत्यक्ष परिणाम जाणवत होते; कारण अमेरिकन बाजारपेठ भारतीय निर्यातदारांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. अर्थात, भारत-अमेरिका व्यापार कराराच्या घोषणेनंतर आयात शुल्क १८ टक्के झाल्याने बराच दिलासा मिळाला होता. आता अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे त्यात आणखी भर पडली आहे; पण हा दिलासा कधीपर्यंत कायम राहील, हे सांगता येत नाही. ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कारकिर्दीतील धोरणात्मक अस्थिरता ही मोठीच समस्या आहे. न्यायालयाने एक आदेश देताच, दुसऱ्या कायद्याचा आधार घेऊन ट्रम्प यांनी नवीन शुल्क लागू केले आहे! त्यामुळे भारताने आपल्या व्यापार धोरणात वैविध्य आणणे अत्यावश्यक आहे. युरोपियन संघ, पश्चिम आशिया, आफ्रिका आणि आग्नेय आशियातील देशांशी मुक्त व्यापार करारांच्या वाटाघाटी पुढे नेणे, पुरवठा साखळ्यांचे पुनर्संतुलन करणे आणि देशांतर्गत उत्पादन क्षमतेत वाढ करणे, ही दीर्घकालीन गरज आहे. ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणामागील तत्त्वज्ञान मूलतः संरक्षणवादाचे आहे. जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत अमेरिकन उद्योगांची स्पर्धात्मकता कमी झाली, उत्पादन बाहेर गेले आणि रोजगार गमावले, हा त्यांचा युक्तिवाद; परंतु संरक्षणवाद हा दीर्घकालीन उपाय नसतो. आयात शुल्क वाढवून तात्पुरता दिलासा मिळू शकतो; पण त्यातून नवोन्मेष, कार्यक्षमता आणि जागतिक स्पर्धेला चालना मिळत नाही. उलट, परस्पर प्रतिशुल्कांच्या चक्रात अडकून सर्वच देशांचे नुकसान होते. यापूर्वी १९३० च्या दशकातील स्मूट-हॉले कायद्याने तो अनुभव दिला होता. जागतिक व्यापार संघटनेत सुधारणा, विवाद निवारण यंत्रणेचे पुनरुज्जीवन आणि पारदर्शक नियमावलीसाठी भारताने पुढाकार घ्यायला हवा. निर्यात क्षेत्रातील संरचनात्मक अडचणींचाही प्रामाणिकपणे विचार करणे आवश्यक आहे. टॅरिफ रद्द झाल्याने निर्यात आपोआप वाढणार नाही. जागतिक बाजारपेठेत टिकण्यासाठी दर्जा, नवोन्मेष आणि वेळेत पुरवठा, यामध्ये सुधारणा अपरिहार्य आहे. भारताने अमेरिकेसोबत अधिक परिपक्व आणि संतुलित व्यापार संवाद साधला पाहिजे. लोकशाही संस्थांची ताकद अजूनही शाबूत आहे, कार्यपालिकेचा अतिरेक रोखण्याची क्षमता न्यायपालिकेकडे असल्याचे, अमेरिकेतील न्यायालयीन हस्तक्षेपामुळे अधोरेखित झाले आहे; परंतु संस्थात्मक ताकद असूनही, धोरणात्मक अनिश्चितता कायम राहू शकते. म्हणूनच भारताने बाह्य परिस्थितीवर अवलंबून न राहता अंतर्गत सामर्थ्य वाढविण्यावर भर दिला पाहिजे. बहुपक्षीयतेला पाठिंबा, द्विपक्षीय संबंधांत संतुलन, देशांतर्गत सुधारणा आणि दीर्घकालीन धोरणात्मक दृष्टी यांवर भर दिल्यासच भारत या अस्थिर काळात आर्थिक हित सुरक्षित ठेवू शकेल!

अमित शाह यांच्या रडारवर आता ड्रग्ज माफिया !

नक्षलवादाचे उच्चाटन करण्याचे ध्येय सिद्धीच्या जवळपास पोहोचताना दिसते आहे. आता अमली पदार्थ विकणाऱ्या टोळ्या हे पुढील लक्ष्य असेल!

डॉ. विजय दर्डा
चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड, लोकमत समूह

अगदी अलीकडेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याशी बोलणे झाले. मी त्यांना म्हणालो, नक्षलवादाच्या उच्चाटनाची आपली मोहीम एक सिद्ध करते, की ठाम नेतृत्व असेल तर काहीही अशक्य नाही. आता देशाला अमली पदार्थांच्या व्यापारापासून मुक्ती द्या! हे काम सोपे नाही; परंतु आपणच ते करू शकाल!'- प्रसन्न हसत ते मला म्हणाले, 'तुम्ही पाहाल, अमली पदार्थ विकणाऱ्यांची अजिबात गय केली जाणार नाही. या देशात त्यांच्यासाठी जागा नाही!'

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या बाबतीत मला नेहमीच विश्वास वाटत आला आहे. मार्च २०२६ पर्यंत नक्षलवाद्यांना संपवण्याची घोषणा त्यांनी केली, तेव्हा सर्वांनाच शंका होती की राजकीय नेते, शेकडोने पोलिस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा जीव घेणारा हा रक्तरंजित आजार इतक्या लवकर कसा नष्ट होईल? - परंतु, अमित शाह यांचा निर्धार पक्का होता. प्रत्यक्षात घोषणा करण्याच्या कितीतरी आधीपासून त्यांनी व्यूहरचना करायला सुरुवात केली होती. संबंधित राज्यांना विश्वासात घेण्यात आले. नेमक्या जागी योग्य अधिकारी नेमले गेले. पुरेशी साधनसामग्री उपलब्ध करून दिली गेली. सन्मार्गावरून भरकटलेल्यांसाठी एका हाताने प्रेमाचा स्पर्श, तर दुसऱ्या हातात आग ओकणाऱ्या बंदुका होत्या. सक्षम नेतृत्वाची हीच लक्षणे असतात.

आता पाळी अमली पदार्थांच्या व्यापाऱ्यांची आहे. असे म्हणतात, की अमित शाह घोषणाबाजीपेक्षा प्रत्यक्ष परिणामांवर विश्वास असणारे नेते आहेत. थोडीशी माहिती समोर येते तेव्हा पुष्कळ सगळे काम झालेले असते. गेल्या आठवड्यात गोव्यात होतो. गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, त्यानंतर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि या दोन्ही राज्यांतल्या ज्येष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांशी चर्चा करताना लक्षात आले, की अमली पदार्थ विकणाऱ्या टोळ्यांच्या मुसक्या आवळण्याच्या तयारीने बराच वेग घेतला आहे.

केंद्र सरकारने १५ ऑगस्ट २०२० रोजी 'नशामुक्त भारत अभियाना'ची घोषणा केली. २०१८ मध्ये देशव्यापी पाहणी झाली. या पाहणीचा अहवाल २०१९ मध्ये आला. १६ कोटी लोक मद्यसेवन करतात असे आढळून आले. त्यातील ५.७ कोटींपेक्षा जास्त गंभीर स्थितीत आहेत. साधारणतः ३.१ कोटी लोक भांगेचे सेवन करतात. २५ लाख लोक या सवयीच्या आहारी गेलेले आहेत. सुमारे २ कोटी २६ लाख लोक अफू खातात. त्यातील ७७ लाखांची गंभीर स्थिती आहे. सुमारे ८.५ लाख लोक शिरेत इंजेक्शनच्या माध्यमातून अमली औषधे घेतात. उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा यासारख्या राज्यांत नशाबाजांची संख्या जास्त आहे.

गेल्यावर्षी सप्टेंबर महिन्यात राष्ट्रीय अमली पदार्थ कृती गटाच्या दुसऱ्या राष्ट्रीय संमेलनात केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी अत्यंत सुस्पष्ट असा तपशील दिला. भारतात अमली पदार्थांच्या जाळ्याचे तीन भाग आहेत. पहिला परदेशात बसून सीमेवरून अमली पदार्थ इकडे पाठवतो. दुसरा देशात आहे, जो विभिन्न राज्यांत अमली पदार्थ पोहोचवतो; आणि तिसरा स्थानिक पातळीवर अमली पदार्थांच्या पुड्या चौकाचौकातं विकतो. या तिघांवरही एकाचवेळी पूर्ण ताकदीने आघात करण्याची व्यूहरचना आखली जात आहे. भारताच्या कारागृहांत बांगलादेश, फिलिपाइन्स, घाना, म्यानमार, मलेशिया आणि नायजेरिया या देशांतले अमली पदार्थांचे सुमारे १६ हजार तस्कर कैद आहेत. त्यांना देशाबाहेर काढण्याचे काम सुरू झाले आहे. परदेशात बसलेल्या तस्करांना ताब्यात घेण्याची प्रक्रियाही सुरू आहे.

सीमेवरून भारतात अमली पदार्थांची तस्करी होऊ नये यासाठी मोठी मोहीम राबवली जात आहे. या धंद्यात प्रचंड पैसा असून, त्याचा उपयोग प्रलोभन दाखवण्यापासून धमकी देण्यापर्यंत किंवा जीव घेण्यापर्यंत केला जातो. पंजाब आणि राजस्थानच्या सीमेपासून गुजरातमध्ये समुद्री सीमेपर्यंत पाकिस्तानचे लष्कर आणि त्या देशाची गुप्तचर संस्था आयएसआय अमली पदार्थांच्या तस्करांना मदत करते. दुसरा मोठा रस्ता म्हणजे गुजरातचा समुद्रकिनारा. हेरॉइन नावाचा अमली पदार्थ कंटेनरमध्ये लपवून तस्करी करण्याची अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत. पाच वर्षांपूर्वी गुजरातच्या मुंद्रा बंदरावर अशाच एका कंटेनरमध्ये लपवून आणलेले २१ हजार कोटींचे हेरॉइन पकडले होते. याशिवाय बिहार आणि उत्तर प्रदेशमध्ये नेपाळमार्गे, तर पूर्वोत्तर भारतातील राज्यांत म्यानमार आणि बांगलादेश मार्गे अमली पदार्थांची तस्करी होत असते. हे सगळे तस्कर एकमेकांशी जोडलेले आहेत. मेक्सिको, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगलादेश, थायलंड, म्यानमारपासून नायजेरिया आणि घानापर्यंत सगळे व्यापारी एकाच माळेचे मणी आहेत.

या लढ्यात देशातले युवक, शिक्षक आणि सामाजिक कार्यकर्ते मोठी भूमिका बजावू शकतात. कारवाई तर पोलिसच करतील, पण हे सर्वजण गुप्त माहितीचे महत्त्वाचे स्रोत नक्कीच ठरू शकतात. अमली पदार्थांच्या सौदागरांचे जाळे गावोगावी पसरलेले आहे आणि त्यांचे मुख्य लक्ष्य आपले युवकच आहेत.

ही लढाई सोपी नाही; परंतु नरेंद्र मोदी यांचे नेतृत्व आणि अमित शाह यांचा निर्धार यावर विश्वास ठेवला पाहिजे. भारताने ज्याप्रकारे नक्षलवादाची लढाई जिंकली, त्याचप्रकारे अमली पदार्थांच्या विक्रीचे जाळे नेस्तनाबूत करण्यातही आपण यशस्वी होऊ.

vijaydarda@lokmat.com
डॉ. विजय दर्डा यांचे समग्र लेखन वाचण्यासाठी स्कॅन करा :

अन्वयार्थ

एसटीचे चाक चिखलात; 'लालपरी'ला सरकारी धक्क्याची प्रतीक्षा

सध्या एसटी महामंडळ आर्थिक विवंचनेत सापडले असून, तोटा वाढत चालला आहे. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी सरकारच्या आर्थिक मदतीची नितांत गरज आहे.

श्रीरंग बरगे
सरचिटणीस, महाराष्ट्र एस.टी. कर्मचारी काँग्रेस

महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात, डोंगरदऱ्यांत, खेड्यापाड्यांत आणि शहरांच्या गजबजाटात आपल्या चाकांवर विश्वासाचे ओझे वाहणारी 'लालपरी' आज स्वतःच आर्थिक चिखलात रुतलेली दिसत आहे. मात्र, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (एसटी) हा केवळ एक परिवहन उपक्रम नसून तो राज्याच्या सर्वसामान्य जनतेचा जीवनदायी धागा आहे. अन्न, वस्त्र आणि निवारा या मूलभूत गरजांप्रमाणेच स्वस्त, सुरक्षित आणि सुलभ दळणवळणाची जबाबदारी पार पाडणारे हे महामंडळ आज आर्थिक विवंचनेच्या कात्रीत सापडले आहे.

एसटी ही केवळ बससेवा नसून ती ग्रामीण महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी आहे. जिथे रेल्वेचे रूळ पोहोचले नाहीत, जिथे खासगी वाहतुकीचे पर्याय मर्यादित आहेत, तिथे एसटीनेच जनतेच्या आशा-आकांक्षांना पंख दिले आहेत. परंतु, आज वाढता आस्थापना खर्च, वाढता डिझेल खर्च, वाढता स्पेअर पार्ट्स खर्च व कर्मचाऱ्यांची प्रलंबित देणी, म्हणजेच थकीत उपदान रक्कम, भविष्य निर्वाह निधीचे हप्ते आणि बँक कर्जाचे हप्ते या सर्वांनी एसटीच्या चाकांना जणू आर्थिक चिखलातच अडकवून ठेवले आहे. या अडचणींचा डोंगर दिवसेंदिवस उंचावत असून, त्यातून मार्ग काढण्यासाठी सरकारच्या आर्थिक आधाराची नितांत गरज निर्माण झाली आहे. सर्वसामान्य जनतेच्या या लाडक्या लालपरीची चाके आर्थिक चिखलात अडकली असून, तिला आता सरकारच्या आर्थिक धक्क्याची गरज आहे.

सध्या एसटी महामंडळ आर्थिक विवंचनेत सापडले असून, तोटा वाढत चालला आहे. कर्मचाऱ्यांची तसेच महामंडळासमोरची तब्बल ४३०० कोटी रुपयांची वैधानिक देणी रक्कम थकली असून, डिझेलसारख्या दैनंदिन खर्चाला लागणाऱ्या रकमेसाठी निधीची जुळवाजुळव करताना व्यवस्थापनाची तारांबळ उडत आहे. तब्बल १२ हजार कोटी रुपयांचा संचित तोटा असल्याचे वास्तव चिंताजनक आहे. या तोट्याच्या सावटाखाली एसटीचा प्रवास अधिकच खडतर होत चालला आहे.

जर हीच परिस्थिती कायम राहिली, तर भविष्यात कर्मचाऱ्यांचे वेतन देणेच नव्हे, तर डिझेलसारख्या मूलभूत गरजांसाठीही निधी उभारणे कठीण होईल. अशा परिस्थितीत एसटीची गती मंदावणे अपरिहार्य ठरेल, आणि त्याचा सर्वाधिक फटका ग्रामीण व सर्वसामान्य जनतेला बसेल.

याचबरोबर, एसटीच्या ताफ्यात नवीन बसेस दाखल करण्यासाठी आवश्यक असलेला निधी उपलब्ध करून देणे अत्यंत गरजेचे आहे. पण जर वेतनवाढ फरक हप्ता रक्कम द्यायला सरकारकडे निधी नसेल, तो मिळण्यासाठी पायपीट करावी लागत असेल तर पुढे येणाऱ्या गाड्या खरेदीसाठी निधी उपलब्ध होईल का, अशी शंकासुद्धा निर्माण झाली आहे. अनेक बसेस कालबाह्य झाल्या असून, त्यांची जागा आधुनिक, सुरक्षित आणि इंधन बचतीच्या बसेसने घेणे आवश्यक आहे. यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेऊन येत्या अर्थसंकल्पात भरीव आर्थिक तरतूद अनुदान स्वरूपात करणे ही काळाची गरज आहे. आणि तो आर्थिक 'धक्का' मिळाल्यासच एसटीचे चाक पुन्हा गती घेऊ शकेल.

एसटी वाचली तरच ग्रामीण महाराष्ट्राची गती कायम राहील आणि 'लालपरी'चे चाक पुन्हा अभिमानाने, विश्वासाने आणि वेगाने फिरू लागेल. मध्यंतरी १३ ऑक्टोबर २५ रोजी, महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना वेतनासोबत सन २०२० ते २०२४ या कालावधीचा वेतनवाढ फरक देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

महामंडळाची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्याने राज्य सरकारकडून दर महिन्याला साधारण ६५ कोटी रुपयांची रक्कम देण्यात येईल असे राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी अर्थ मंत्रालयाचे अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश गुप्ता यांच्या उपस्थितीत जाहीर केले. पण, गेले तीन महिने ही रक्कम अर्थ खात्यातील अधिकाऱ्यांनी महामंडळाच्या तिजोरीत वर्ग केली नाही. त्यामुळे राज्य सरकारची अब्रू राखण्यासाठी एसटी महामंडळाने आपल्या तिजोरीतून सदरची रक्कम नोव्हेंबर व डिसेंबर २५ या महिन्यात वेतनासोबत कर्मचाऱ्यांना दिली. पण जानेवारीत मात्र महामंडळाच्या तिजोरीत खडखडाट असल्यामुळे व्यवस्थापन ही रक्कम देऊ शकले नाही आणि हा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला. यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष पसरला असून, राज्यभर आंदोलने सुरू झाली आहेत. यासंदर्भात वेळीच योग्य निर्णय घेण्याची गरज आहे.

जगभर

शिक्षकानं केलं देशी-विदेशी ८९ मुलींचं शोषण!

गोष्ट आहे फ्रान्समधली. ही गोष्ट सुरू होते १९६०च्या दशकात. ती अजूनही संपलेली नाही. या गोष्टीला हिरो नाही, आहे फक्त व्हिलन. हा व्हिलन आहे पूर्वीचा शिक्षक. त्याचं नाव जॅक्स लेवुग्ले. वय ७९ वर्षे!
शिक्षकाचं काम मुलांना शिकवण्याचं, त्यांच्यावर सुसंस्कार करण्याचं, त्यांना घडवण्याचं आणि भविष्यात त्यांनी 'माणूस' म्हणून पुढे यावं यासाठी प्रयत्न करण्याचं. पण या शिक्षकानं काय करावं? १९६७ ते २०२२ या कालावधीत त्यानं तब्बल नऊ देशांतील बालिकांवर लैंगिक अत्याचार केले. त्यात जर्मनी, स्वीत्झर्लंड, मोरक्को, नायजर, अल्जिरिया, फिलीपिन्स, कोलंबिया, फ्रान्स आणि भारतीय अल्पवयीन मुलींचाही समावेश आहे. अत्याचारपीडित मुलींची संख्या आहे तब्बल ८९!

अर्थात ही संख्या आहे फक्त उघड झालेल्या प्रकरणांची. अजून बऱ्याच मुलींवर त्यानं अत्याचार केले असावेत, असा अधिकाऱ्यांचा कयास आहे. पण ते कळावं कसं? त्यासाठी हा खटला नुकताच सार्वजनिक करण्यात आला आहे. फ्रान्सच्या ग्रेनोबल शहरातील सरकारी वकील एटिएन मंटो यांनी यासंदर्भात पीडितांनी पुढे यावं आणि आपल्यावर झालेल्या अत्याचारांची माहिती द्यावी, असं आवाहन केलं आहे.

पूर्वी ज्या मुलींवर त्यानं अत्याचार केले असतील, पण बदनामीच्या भीतीपोटी ज्यांनी तक्रारी केल्या नसतील आता त्या मुलीही सज्ञान आणि मोठ्या झालेल्या असतील, पण हा 'तोच' आरोपी आहे, ज्यानं आपल्यावर अत्याचार केले होते, हे ओळखू यावं यासाठी एक अभिनव मार्ग अवलंबिण्यात आला आहे.

आरोपी जॅक्स लेवुग्ले याचे १९६५ पासून २००० पर्यंतचे अनेक फोटो जाहीर करण्यात आले आहेत, जेणेकरून पीडित त्याला ओळखू शकतील आणि पुढे येऊ शकतील!

जॅक्स लेवुग्ले फ्रेंच भाषेचा शिक्षक आणि गुहांचा अभ्यास (स्पेलिऑलॉजी) यासंदर्भात प्रशिक्षक म्हणून काम करत होता. विविध ठिकाणी जाऊन तो तरुणवर्गाशी संपर्क साधत असे आणि नंतर त्यांच्यासोबत लैंगिक गैरवर्तन करत असे.

ज्या-ज्या पीडितांवर त्यानं अत्याचार केले, त्यातील बहुतांश मुलींचं वय १३ ते १७ वर्षांदरम्यान होतं. जॅक्सवरील आरोप निश्चित झाल्यानंतर २०२४ पासून तो कोठडीत आहे. पण या आरोपीच्या गुन्ह्यांचा पाढा इथेच थांबत नाही. त्याची चौकशी केल्यानंतर आपली आजारी आई आणि वृद्ध मावशी यांचीही त्यानं हत्या केल्याचं समोर आलं आहे. त्यानं त्याची कबुलीही दिली आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे त्याच्या नातेवाइकांनाच त्याच्या गुन्हेगारी कृत्यावर संशय आल्यानं त्याचे हे भयानक कारनामे उघडकीस आले.

जॅक्सच्या पुतण्यालाच त्याच्या कृत्यांचा संशय आला. त्यामुळे त्याने एके दिवशी गुपचूप जॅक्सच्या खोलीची झडती घेतली. तेथे त्याला एक यूएसबी ड्राईव्ह सापडला. त्यात त्यानं अल्पवयीन मुलींवर केलेल्या लैंगिक अत्याचाराची छायाचित्रे होती. या ड्राइव्हमध्ये १५ भागांमध्ये सविस्तर माहिती लिहिलेली होती. त्यात त्यानं स्वतःच या लैंगिक अत्याचारांची नोंद केलेली होती. तपास अधिकाऱ्यांनी हे दस्तऐवज वाचून ८९ पीडितांची ओळख पटवली.

१९७० च्या दशकात त्यानं कर्करोगाने पीडित असलेल्या आपल्या आईला आणि १९९० च्या दशकात आपल्या ९२ वर्षांच्या मावशीची उशीने तोंड दाबून हत्या केली होती.

करनीती

'जीएसटी' आणि 'आयटीसी'ची कहाणी

अर्जुन (काल्पनिक पात्र) : कृष्णा, जीएसटी प्रणालीतील GSTR-3B रिटर्नमध्ये झालेले बदल कोणते?

कृष्ण (काल्पनिक पात्र) : अर्जुन, मुख्य बदल व्याज गणनेच्या पद्धतीत झाला आहे. त्यामुळे करदात्यांना त्यांच्या इलेक्ट्रॉनिक कॅश लेजरमधील शिल्लक राहिलेल्या रकमेचा फायदा होईल. त्याचप्रमाणे, आयटीसी वापरण्याच्या प्रक्रियेत सुधारणा केली जात आहे, ज्याचा मुख्य उद्देश CGST, SGST आणि IGSTमधील क्रॉस-युटिलायझेशन सुलभ करणे.

अर्जुन : GSTR-3B मध्ये व्याज गणनेसंबंधित बदल काय आहेत?

कृष्ण : नव्या बदलानुसार, करदात्यांकडे इलेक्ट्रॉनिक कॅश लेजरमध्ये पुरेशी रक्कम शिल्लक असेल, तर त्यांना संपूर्ण विलंबित कालावधीसाठी व्याज भरण्याची शिक्षा दिली जाणार नाही. नवीन व्याज सूत्र असे आहे :-

व्याज = (NTL - ECL मध्ये कमाल शिल्लक) × (विलंबित दिवसांची संख्या / ३६५) × लागू व्याजदर

अर्जुन : आयटीसी वापरण्याच्या प्रक्रियेत काय नवीन बदल झाले आहेत?

कृष्ण : जानेवारी २०२६ पासून, GSTR-3B मध्ये आयटीसी वापरण्याची प्रक्रिया आणखी सुधारण्यात आली आहे. जीएसटी पोर्टल आता करदात्यांना IGST लायबिलिटी CGST आणि SGST ITC मधून कोणत्याही क्रमाने भरता येईल. यामुळे करदात्यांसाठी कर लायबिलिटी भरण्याची प्रक्रिया सोपी होईल. IGST देयकासाठी CGST किंवा SGST ITC कोणत्याही क्रमाने वापरण्याची सुविधा फेब्रुवारी २०२६ पासून उपलब्ध होईल.

- उमेश शर्मा, सीए

समकालीन महत्त्वाचे मुद्दे मांडणारी, नवी चर्चा सुरू करणारी वाचक-पत्रे या स्तंभामध्ये प्रसिद्ध केली जातील. आपली पत्रे येथे पाठवा : **janman@lokmat.com**

जेन झी

भारतातल्या जेन झींचे आई-बाबा आणि आजी-आजोबा

भारतातल्या जेन झींचे आई-बाबा आणि आजी-आजोबा यांच्या दोन पिढ्या विरोधाभासांच्या उंबरठ्यावरून देशातल्या नव-तारुण्याकडे पाहात आहेत.

राही श्रु. ग.
सीनिअर रिसर्च फेलो
जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ

जागतिक पातळीवर बूमर्स ते झूमर्स या पिढ्यांची चर्चा होते तेव्हा बहुतांश वेळा ही चर्चा पाश्चात्त्य संदर्भांमध्येच होत असते. बूमर्स, जेन एक्स, मिलेनियल्स आणि जेन झी यांची जी वैशिष्ट्यं सांगितली जातात तीसुद्धा पाश्चात्त्य जगाच्या संदर्भानेच ठरवली जातात. जागतिक पातळीवर काही सामाजिक, आर्थिक प्रवाह सगळीकडेच पाहायला मिळत असले तरी, भारतात मात्र पिढ्यांचं वर्गीकरण काहीसं वेगळ्या पद्धतीने करणं आवश्यक आहे.

स्वतंत्र भारतातली सर्वात जेष्ठ पिढी साधारण १९३१ ते १९५०च्या दरम्यान जन्मलेली आहे. भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याचा अखेरचा टप्पा, फाळणी आणि नव्याने मिळालेलं स्वातंत्र्य अनुभवलेली ही पिढी. अमेरिकन अर्थाने या पिढीतल्या लोकांना 'ग्रेटेस्ट जनरेशन', 'सायलंट जनरेशन' किंवा 'बूमर्स' यापैकी कुठल्याही पिढीचे प्रतिनिधी म्हणता येणार नाही. स्वातंत्र्यलढ्याचं वारं पिऊन ही पिढी वाढली. त्यांच्या बालपणातच त्यांनी नव्या स्वतंत्र देशाची स्वप्नं पाहिली. स्वातंत्र्यसैनिकांच्या त्यागाच्या कथा ऐकत ही मुलं कळती झाली. त्यांच्या बालपणात आणि तारुण्यात हळूहळू आधुनिकतेशी आणि लोकशाही देशाच्या जडणघडणीशी त्यांची ओळख झाली.

परंपरा आणि आधुनिकता, समूहकेंद्री आणि व्यक्तिकेंद्री विचारसरणी अशी रस्सीखेच आयुष्यभर त्यांच्या वाट्याला आली. समता, स्वातंत्र्य आणि न्यायासाठी झालेल्या समाजसुधारणांच्या चळवळींनी स्वातंत्र्यपूर्व काळापासूनच जातसंस्था, पितृसत्ता आणि धार्मिक पुराणमतवादावर हल्ला चढवायला सुरुवात केली. ही पिढी स्वतंत्र भारताची, तरुण मतदारांची पहिली पिढी ठरली. स्वतंत्र देशाच्या उभारणीसाठीचे प्रयत्न, नव्या संस्थांची स्थापना आणि नेहरूवादी राजकारणाचा काळ हे या पिढीचे तारुण्य. काटकसर आणि कष्ट करत ही पिढी वाढली. आधुनिकतेबरोबर जुळवून घेण्याचा या पिढीने पुन्हा पुन्हा प्रयत्न केला.

१९५१ ते १९८०च्या दरम्यान जन्मलेले भारतीय लोक अमेरिकन अर्थाने बूमर्स आणि जेन एक्स यांचं मिश्रण आहेत. भारत-चीन युद्ध, पंचवार्षिक योजनांमधून होणारा आर्थिक आणि पायाभूत सुविधांचा विकास आणि पुढे आणीबाणी या महत्त्वाच्या घटना या पिढीच्या बालपणी घडल्या. नेहरूंच्या मृत्यूनंतर भारतीय राजकारणाची दिशा वेगाने बदलत गेली. स्वातंत्र्यलढ्याच्या अनुभवाचा, त्यागाचा आणि समाजपरिवर्तनाच्या एका पठडीतल्या विचारसरणीचा दुवा असलेली पिढी काळाच्या पडद्याआड जाऊ लागली तशी देशासमोरच्या नव्या आव्हानांना, विशेषतः सुरक्षा आणि आर्थिक विषमतेला तोंड देण्यासाठी स्वातंत्र्याच्या पूर्वसंध्येला जन्मलेली पिढी सज्ज झाली. इंदिरा गांधींच्या राजकारणाने देशाच्या भवितव्यावर दूरगामी परिणाम केले. बँकांचं राष्ट्रीयीकरण आणि बांगलादेश युद्धाने भारताची एक बलशाली समाजवादी देश म्हणून ओळख निर्माण झाली. पण, त्याचवेळी आणीबाणीने लोकशाहीसमोरची आव्हानं दाखवून दिली.

आंबेडकरवाद, स्त्रीवाद आणि मार्क्सवादाच्या आदर्शांना प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी देशभरात आंदोलनं उभी राहिली. एकाचवेळी डाव्या आणि उजव्या राजकीय समूहांनी काँग्रेसच्या काहीशा नेमस्त राजकारणाला आव्हान दिलं. आधीच्या पिढीपेक्षा सावध आणि चिकित्सक अशी ही पिढी सध्या उद्योगधंदे, राजकारणापासून सांस्कृतिक विश्वाचं नेतृत्व करते आहे. कल्याणकारी राज्यसंस्थेतून सोयीसुविधा, शिक्षण आणि प्रसंगी रोजगारदेखील मिळवलेल्या या पिढीने खासगीकरणाचं मात्र स्वागत केलं. याच पिढीतल्या एका समूहाने समता-सामाजिक न्यायासाठी आंदोलनं उभी केली, तर दुसऱ्या एका कंपूने धार्मिक राष्ट्रवादावर आधारित राजकारण रेटलं.

भारतातल्या जेन झींचे आई-बाबा आणि आजी-आजोबा हे असे अनेक विरोधाभासांच्या उंबरठ्यावरून या पिढीकडे पाहात आहेत.

raheeshrutiganesh@gmail.com

तिरकस आणि चौकस

गजानन घोंगडे

हे पत्र लोकमत मीडिया प्रा. लिमिटेडच्या वतीने मुद्रक व प्रकाशक **बालाजी मुळे** यांनी प्लॉट नं. ए - ८१८ इंडस्ट्रियल एरिया, एम.आय.डी.सी., महापे, नवी मुंबई येथे मुद्रित करून 'लोकमत', पृथ्वी पार्क, सेक्टर ३०, सानपाडा, नवी मुंबई कार्यालय - ४००७०५ येथून प्रसिद्ध केले. ● दूरध्वनी क्र : ०२२ ४६०४१७८४
● **मुंबई कार्यालय :** लोकमत मीडिया प्रा. लिमिटेड, तिसरा मजला, पारिजात हाउस, प्लॉट नं. १०७६, आपटे इंडस्ट्रियल इस्टेट, लक्ष्मीनरसिंग पपन मार्ग, डॉ. ई मोझेस रोडसमोर, गांधीनगर, वरळी, मुंबई, ४०००१८. ● दूरध्वनी क्र : ०२२- ४६०३५९३०, ०२२- ४७५०७९४६ ● **ठाणे कार्यालय :** वेस्टर्न व्ह्यू, श्री गजानन महाराज चौक, वारकरी भवनाजवळ, ठाणे, फोन : २५४४१९०५, २५३८१७७४ ● **नवी मुंबई कार्यालय :** पृथ्वी पार्क, सेक्टर ३०, सानपाडा, नवी मुंबई ४००७०५. फोन : ०२२ ४६०४१७८४ ● संस्थापक संपादक : **स्व. जवाहरलाल दर्डा** ● मानद संपादिका : **श्रीमती उषाताई दर्डा** ● चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड : **डॉ. विजय दर्डा** ● एडिटर इन चिफ : **राजेंद्र दर्डा** ● समूह संपादक : **विजय बाविस्कर**
● संपादक : **अतुल कुलकर्णी*** (*पी. आर. बी. कायद्यानुसार संपादकीय जबाबदारी यांची आहे.)
'लोकमत'मधील लेखांचे हक्क राखून ठेवले आहेत. लोकमत ® हे चिन्ह लोकमत मीडिया प्रायव्हेट लि. चे. व्यापारचिन्ह आहे.

‘रोमिओ-ज्युलिएट क्लॉज’ची गरज का?

कोर्ट डायरी

दीप्ती देशमुख
उपमुख्य उपसंपादक

बारावीत शिकणारी १७ वर्षांची मुलगी आणि तिच्या शेजारचा १९ वर्षांचा मुलगा दोघेही एकमेकांना आवडतात, भविष्यासाठी स्वप्नं पाहतात; पण, मुलीच्या कुटुंबीयांचा विरोध होताच मुलावर गुन्हा दाखल होतो, तोही थेट ‘पॉक्सो’अंतर्गत. एका क्षणात प्रेमसंबंध ‘लैंगिक अत्याचार’ ठरतो आणि तरुणाचे आयुष्य न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकते.

पॉक्सो कायदा २०१२ मध्ये बालकांना लैंगिक शोषणापासून संरक्षण देण्यासाठी लागू झाला. १८ वर्षांखालील कोणतीही व्यक्ती ‘बालक’ मानली जाते आणि तिच्याशी संबंधित कोणतेही लैंगिक कृत्य संमती असली तरी गुन्हा ठरतो. कायद्याचा हेतू निःसंशयपणे संरक्षणात्मक आहे; परंतु सामाजिक वास्तव अधिक गुंतागुंतीचे आहे. किशोरवयात आकर्षण, प्रेमसंबंध आणि भावनिक जवळीक ही नैसर्गिक प्रक्रिया आहे. अशा वेळी वयातील दोन-तीन वर्षांच्या फरकामुळे गंभीर गुन्हेगारी कलमे लागू होणे, हा मानवी आणि कायदेशीर दोन्ही पातळ्यांवरील प्रश्न आहे.

सर्वोच्च न्यायालय आणि विविध उच्च न्यायालयांनी अलीकडील निरीक्षणांत असे नमूद केले आहे की, प्रत्येक किशोरवयीन प्रेमसंबंधाला ‘अत्याचार’ म्हणून पाहणे योग्य नाही. अनेक प्रकरणांत तक्रारी पालकांच्या असहमतीमुळे किंवा सामाजिक दबावातून दाखल होतात. परिणामी, मुलांवर कठोर गुन्हे दाखल केले जातात. त्यांना अटक केली जाते आणि त्याचे शिक्षण, करिअर धोक्यात येते. न्यायालयांनी अशा प्रकरणांत ‘सहमतीने प्रेमसंबंध’ आणि ‘शोषणात्मक लैंगिक अत्याचार’ यांतील फरक अधोरेखित केला आहे.

याच पार्श्वभूमीवर ‘रोमिओ-ज्युलिएट क्लॉज’ची चर्चा पुढे आली आहे. ही अशी तरतूद असू शकते की, जर दोन्ही व्यक्ती समवयस्क असतील आणि त्यांच्यातील संबंध परस्पर संमतीने असतील, तर त्यांना गुन्हेगारी कारवाईपासून सूट मिळावी. यामुळे खऱ्या अर्थाने शोषणाच्या प्रकरणांवर कठोर कारवाई सुरू राहील; पण निरपराध किशोरवयीन मुलांचे आयुष्य उद्ध्वस्त होणार नाही.

कायद्याचा आत्मा संरक्षणाचा आहे; पण त्याची अंमलबजावणी मानवी वास्तवाशी सुसंगत असणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. प्रेम आणि गुन्हा यांच्यातील सीमारेषा आखताना न्याय, संवेदनशीलता आणि सामाजिक बदल यांचा समतोल राखणे आवश्यक आहे. ‘रोमिओ-ज्युलिएट क्लॉज’वरील चर्चा ही केवळ कायदेशीर नव्हे, तर तरुण पिढीच्या भवितव्याशी निगडित महत्त्वाचा विषय आहे.

मुख्य आव्हान म्हणजे संरक्षण आणि स्वातंत्र्य यांच्यातील संतुलन. एकीकडे बालकांचे संरक्षण अबाधित राहिले पाहिजे; दुसरीकडे, निरपराध किशोरवयीन मुलांचे आयुष्य उद्ध्वस्त होता कामा नये.

न्यायालये विधिमंडळाला याबाबत विचार करण्याचा सल्ला देत आहेत. अंतिम निर्णय संसदेकडे आहे. मात्र या चर्चेमुळे एक व्यापक सामाजिक प्रश्न पुढे आला आहे - कायद्याने वास्तवातील मानवी भावना आणि बदलत्या सामाजिक परिस्थितीचा कितपत विचार करावा?

मुंबई पालिका आयुक्तपदासाठी ‘काँटे की टक्कर’ !

मुक्काम पोस्ट महामुंबई

अतुल कुलकर्णी
संपादक, मुंबई

महाराष्ट्राचे पोलिस महासंचालक, मुंबईचे पोलिस आयुक्त या दोनपैकी कोणते पद तुम्हाला आवडेल? असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना विचारले तर दहापैकी आठ अधिकारी मुंबईचे पोलिस आयुक्तपद मागतील. जगभरात मुंबई आणि मुंबईचे पोलिस आयुक्त या दोघांची प्रचंड उत्सुकता असते. मुंबई महापालिकेचे आयुक्तपदही तितक्याच तोलामोलाचे. राज्याचे मुख्य सचिव व्हायचे की मुंबई महापालिकेचे आयुक्त अशी चॉईस दिल्यास प्रत्येकाची पसंती महापालिका आयुक्तपद असेल.

एस. एस. तिनईकर १९८६ ते १९९० या काळात महानगरपालिकेचे आयुक्त होते. प्रामाणिक आणि निर्भीड अधिकारी अशी त्यांची ओळख होती. भ्रष्टाचाराच्या विरोधात, सार्वजनिक हितासाठी राजकीय नेत्यांनाही न जुमानणारे म्हणून ते परिचित होते. १९९७ च्या त्यांच्या स्लम पुनर्वसन समितीच्या अहवालाने भूमाफिया आणि राजकारणी यांच्यातील साटेलोटे उघड केले होते. त्यानंतर अनेक आयुक्त आले. प्रत्येकाने वेगळे काम करण्याचे प्रयत्न केले. जयराज फाटक यांनी पाणीपुरवठ्याच्या कामात लक्ष घातले. सुबोधकुमार यांच्या काळात फंजीबल एफएसआयचा निर्णय मार्गी लागला. बीएमसीला त्यामुळे मोठा आर्थिक लाभ झाला. सीताराम कुंटे, अजोय मेहता या आयुक्तांनी त्यावेळी फायलींवर घेतलेल्या ठाम भूमिका आजही बदलायचा प्रयत्न केला तरी बदलता येत नाहीत. भूषण गगराणी विद्यमान पालिका आयुक्त. इंजिनिअर असो की वॉर्ड ऑफिसर; प्रत्येकाशी थेट संबंध ही त्यांची जमेची बाजू. फार गाजावाजा न करता त्यांनी अनेक मोठे बदल घडवले. प्रत्येक आयुक्तांच्या काळातली राजकीय परिस्थिती वेगळी होती. काहींनी राजकीय नेतृत्वाशी जुळवून घेतले. फार कमी अधिकाऱ्यांनी ‘मोडेन पण वाकणार नाही’ अशी भूमिका घेतली. प्रशासकीय राजवट आता संपली आहे. या पार्श्वभूमीवर पालिकेला १ एप्रिलपासून नवे आयुक्त मिळतील.

विद्यमान आयुक्त गगराणी ३१ मार्च रोजी निवृत्त होतील. आयुक्त होण्यासाठी पडद्याआड मोठे राजकारण सुरू आहे. काहींनी दिल्ली गाठली आहे. काहींनी आपणच आयुक्त होणार असे सांगणे सुरू केले आहे. आपल्या पाठीशी हा मोठा नेता आहे. दिल्लीतून मुख्यमंत्र्यांकडे निरोप आणू असेही काहीजण बोलत आहेत. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी शब्द दिला असेही काही जण सांगत आहेत. काही अधिकाऱ्यांनी आपण आहे तिथेच समाधानी आहोत असेही मुख्यमंत्र्यांना सांगितल्याची चर्चा आहे. मुंबई महापालिकेच्या आयुक्त पदासाठी अशा चर्चा दरवेळी होतात. मात्र यावेळी स्पर्धेतल्या काही अधिकाऱ्यांवर आक्षेप येतील अशी जुनी प्रकरणे काढणे, त्यांना अडचणीत कसे आणता येईल, त्यांचे नाव स्पर्धेतून बाद कसे करता येईल या पातळ्यांवर काहीजण ॲक्टिव्ह झाल्याची चर्चा आहे. एकाने तर यासाठी एक एजन्सी भाड्याने घेतल्याची मंत्रालयात

चर्चा आहे. हे असे कधी घडले नव्हते.

पालिका आयुक्तांकडे छोट्या माणसापासून बड्या व्यक्तीपर्यंत सगळ्यांची कामे पडतात. बिल्डिंग प्लॅन मंजुरी, बिल्डरांना कन्सेशन देण्याचे अधिकार आयुक्तांना आहेत. मुंबई महापालिकेचे वार्षिक बजेट ७५ हजार कोटींचे आहे. डोअर टू डोअर कचरा गोळा करण्याचे ४५०० कोटींचे टेंडर काढले आहे. वेस्ट मॅनेजमेंट प्रोजेक्ट ७ वर्षासाठी ५ हजार कोटी खर्च होणार आहेत. सिव्हरेज ट्रीटमेंट प्लांटची एकत्रित किंमत ३५ हजार कोटींची आहे. कोस्टल रोडचे एक्सटेन्शन २२ हजार कोटी, गोरेगाव मुलुंड लिंक रोड ६,२०० कोटी, असे प्रकल्प सुरू आहेत. मुंबईतील रस्ते सिमेंट काँक्रीटचे करण्याचे ६५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. यासाठी १७ हजार कोटी रुपये खर्च होत आहेत. ‘नाईट फ्रँक इंडिया’ने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, २०३० पर्यंत म्हणजे येत्या ४ वर्षात ४४,२७७ घरे या शहरात बांधली जातील. त्यासाठी १,३०,५०० कोटी रुपये खर्च होतील. ही घरे उभारणाऱ्या प्रत्येक बिल्डरला महापालिका आयुक्तांकडे यावेच लागते. त्यामुळे काही राजकीय नेत्यांना आपल्या ऐकण्यातला आयुक्त असावा असे वाटते. अमुक अधिकारी आला तर आपल्याला काम करता येणार नाही. तमुक अधिकारी आला तर आपल्याला सोयीचे होईल अशा चर्चा सुरू आहेत.

मुंबईत रोज ७ हजार मेट्रिक टन कचरा गोळा होतो. घनकचऱ्याचे संकलन, वाहतुकीसाठी वर्षाला ७२२ कोटी रुपये खर्च होतात. घनकचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी वर्षाला १७८ कोटी रुपये खर्च होतात. कचऱ्याचे एक मोठे कार्टेल बीएमसीमध्ये वर्षानुवर्षे काम करत आहे. त्यात खालपासून वरपर्यंत अनेकांचे हात आहेत. अमर, अकबर, अँथनी पद्धतीने हे काम सुरू आहे. हे कार्टेल तोडले पाहिजे अशी मुख्यमंत्र्यांचीच तीव्र इच्छाशक्ती आहे. चाळीस वर्षांनंतर भाजपचा महापौर मुंबईत आला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना अनेक गोष्टी करून दाखवायच्या आहेत.

हे सगळे वाचल्यानंतर मुंबई महापालिका आयुक्त किती महत्त्वाची व्यक्ती आहे हे लक्षात आले असेलच. आशिया खंडातील ही सगळ्यात श्रीमंत महापालिका आहे. देशातल्या टॉप सहा-सात महापालिकांचे बजेट एकत्रित केल्यावर मुंबई महापालिकेचे बजेट होते. दिल्ली ते गल्ली एकाच पक्षाची आता सत्ता आहे. निवडून आलेल्यांची अपेक्षापूर्ती, महापालिकेची खालावलेली आर्थिक स्थिती याचा सुवर्णमध्य साधणारा आयुक्त मुंबई महापालिकेसाठी गरजेचा आहे. पण, आयुक्त होण्यासाठी जे राजकारण सुरू आहे तसे आजपर्यंत कधीही झाले नाही. अधिकाऱ्यांचे लॉबिंग, राजकीय नेत्यांची भिन्न मते मुख्यमंत्र्यांपासून लपलेली नाही. ते बोलत नाहीत, पण कृतीतून बरोबर संदेश देतात. तो संदेश समजून घेण्यासाठी आणखी महिनाभर वाट पाहावी लागेल.

‘एमएमआरडीए’ची मदार २३,७११ कोटींच्या उधारीवर

प्रासंगिक

अमर शैला
प्रतिनिधी

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) यंदा ४८,०७२ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. त्यात ८७ टक्के म्हणजे ४२,०२६ निधी विकासकामांसाठी प्रस्तावित केला आहे. सात वर्षांनंतर प्रथमच १७ लाख रुपयांचा ‘अधिशेष’ दाखवून एमएमआरडीए आर्थिक शिस्तीचा दावा करीत असले तरी, वास्तवात तिजोरीत जमा होणाऱ्या रकमेपैकी निम्मा वाटा हा कर्जाचाच आहे. मुंबईच्या पायाभूत सुविधांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी प्राधिकरणाची मदार ‘उधारी’वर असल्याचे अर्थसंकल्पीय आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे.

प्रकल्पांसाठी भरीव तरतूद

अटल सेतू प्रभावित क्षेत्रातील ‘मुंबई ३.०’च्या उभारणीसाठी ४,००० कोटी

नव्या ९२ किमी मेट्रो मार्गिकांसह एकूण मेट्रो प्रकल्पांसाठी १३,८३९ कोटी

मुंबईत भुयारी मार्गांचे जाळे तयार करण्यासाठी ५,५४३ कोटी

विविध रस्ते मार्गांसाठी १२,८१६ कोटी

अर्थसंकल्पातील तरतुदींमध्ये ५६ टक्के वाटा केवळ कर्जाचाच

❶ अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार २३,७११ कोटी रुपये उधारीवर घेण्यात येणार आहेत. पायाभूत प्रकल्पांसाठी राज्य सरकारकडून ३,५२० कोटींचे दुय्यम कर्ज मिळणार आहे. त्यातून अर्थसंकल्पातील तरतुदीत ५६ टक्के वाटा केवळ कर्जाचाच आहे.

❷ गेल्या पाच वर्षांची आकडेवारी पाहिली, तर कर्ज हेच एमएमआरडीएच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत राहिला आहे. २०२२-२३ मध्ये ८,७४७ कोटींचे कर्ज घेतले होते. ते वाढून २०२३-२४ मध्ये ९,३९६ कोटी, तर २०२४-२५ मध्ये १०,००९ कोटी झाले. २०२५-२६ मधील सुधारित अंदाजानुसार ते १५,५४८ कोटींपर्यंत पोहोचणार आहे.

❸ वाढत्या कर्जामुळे एमएमआरडीएला व्याजापोटी ३,२४८ कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागली आहे, तर कर्जाची मुद्दल फेडण्यासाठी ७०५ कोटींची तरतूद केली आहे. अशी कर्जे, त्यावरील व्याज आणि कर्जाची मुद्दल अशी ३,९५३ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

❹ मागील काही वर्षांत एमएमआरडीएने मोठ्या प्रमाणात प्रकल्प हाती घेतले आहेत. मात्र, त्या प्रमाणात उत्पन्न वाढले नाही. सध्या बीकेसीतील जमिनींची विक्री हा उत्पन्नातील सर्वांत मोठा स्रोत आहे. आगामी आर्थिक वर्षात यातून ११,१७८ कोटी रुपये मिळण्याची आशा प्राधिकरणाला आहे.

भाजप बंडखोराला महापौर केले; पण काँग्रेसने काय मिळवले?

भिवंडी महापालिका

नितीन पंडित
प्रतिनिधी

नाट्यमय घडामोडींनंतर भिवंडी महापालिकेच्या महापौरपदी भाजपचे बंडखोर नारायण चौधरी विराजमान झाले; पण यात काँग्रेसने काय मिळवले? असा प्रश्न विचारला जात आहे. काँग्रेसच्या पदरात उपमहापौरपद पडले, तर सेक्युलर फ्रंटसोबत जाण्याचा स्थानिक भाजप नेत्यांचा छुपा अजेंडा असल्याची चर्चा सुरू आहे.

महापालिकेत २२ नगरसेवक आहेत. भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी नारायण चौधरी यांचे नाव महापौरपदाचे उमेदवार म्हणून जाहीर केले होते. त्यामुळे माजी केंद्रीय मंत्री कपिल पाटील यांचे पुतणे नगरसेवक सुमित पाटील नाराज झाले होते. तेव्हापासूनच भाजपमध्ये पाटील आणि चौधरी असे गट पडले. त्यानंतर भाजपचे शहर अध्यक्ष रविकांत सावंत यांनी महापौरपदासाठी स्नेहा पाटील यांच्या नावाची घोषणा केली आणि नाराज झालेल्या चौधरी यांनी सेक्युलर फ्रंटचा रस्ता धरला.

विशेष म्हणजे भाजप प्रदेशाध्यक्षांनी जाहीर केलेला उमेदवार शहराध्यक्षांनी का बदलला, अशी विचारणा भाजपच्या वरिष्ठांनी केली नाही, अथवा त्याबद्दल कोणतेही स्पष्टीकरण दिले नाही. भाजपचे शहराध्यक्ष सावंत हे भिवंडी पश्चिमचे आ. महेश चौघुले यांचे निकटवर्तीय आहेत. चौधरी यांच्यासोबत गेलेल्या पाच नगरसेवकांपैकी चार आ. चौघुले यांचे निकटवर्तीय आहेत. त्यातील तीन नगरसेवक आ. चौघुलेंच्या प्रयत्नांनी बिनविरोध निवडून आले आहेत.

महत्त्वाचे म्हणजे भाजपच्या फुटिर गटातील

भाजपचाच छुपा अजेंडा?

९० नगरसेवक असलेल्या भिवंडी पालिकेत काँग्रेस-३०, राष्ट्रवादी (शरद पवार)-१२, समाजवादी-६,भाजप- २२, शिंदेसेना-१२, कोणार्क विकास आघाडी-४, भिवंडी विकास आघाडी-३, अपक्ष- १ असे पक्षीय बलाबल आहे. कोणालाही बहुमत नसल्याने फोडाफोडीच्या राजकारणाला सुरुवात झाली होती. त्याचा फायदा सेक्युलर फ्रंटने घेतला. मात्र, महापौर भाजपचा बंडखोर झाला.

शहरात नारायण चौधरी यांच्या शुभेच्छांच्या बॅनरवर अनेक ठिकाणी खा. सुरेश म्हात्रे, आ. महेश चौघुले आणि आ. रईस शेख यांची छायाचित्रे झळकली आहेत. त्यामुळे हा भाजपचाच छुपा अजेंडा असावा, अशी चर्चा रंगली आहे.

सुहास नकाते यांनाच भाजपने उपमहापौरपदाचे उमेदवार केले. त्यांना चौधरी यांचे एक मत वगळता २१ मते मिळाली. त्यामुळे या निवडणुकीत भाजपने छुपा अजेंडा वापरल्याचे बोलले जात आहे. तसेच माजी केंद्रीय मंत्री कपिल पाटील आणि शिंदेसेनेचा पाठिंबा घेतलेले विलास पाटील यांना सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठीदेखील आ. चौघुले यांनी ही खेळी केली असावी, अशी चर्चा आहे. राष्ट्रवादीचे (शरद पवार) खा. सुरेश म्हात्रे यांचे आणि आ. चौघुले यांचे जवळचे संबंध आहेत. नारायण चौधरी हेदेखील आ. चौघुले यांचे निकटवर्तीय मानले जातात.

ठाण्यात अपुरा निधी, विकासगती रोडावली

ठाणे डायरी

अजित मांडके
मुख्य उपसंपादक

ठाणे महानगरपालिकेच्या तिजोरीत पुरेसा निधी नसल्याने गेल्या तीन वर्षांपासून शहरातील बहुसंख्य विकासकामे थेट राज्य शासनाच्या माध्यमातून केली जात आहेत. राज्य शासनाने विविध प्रकल्पांसाठी अध्यादेश काढले असून, हजारो कोटींच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली आहे. मात्र, मंजूर निधीच्या तुलनेत केवळ ५ ते ७ टक्केच रक्कम प्रत्यक्षात महापालिकेला मिळाल्याने विकासकामांची गती रोडावली आहे. त्याचा परिणाम थेट कामांच्या दर्जावरही होण्याची शक्यता आहे.

राज्य शासनाने गेल्या तीन वर्षांत ठाणे शहराच्या विकासासाठी सुमारे ६,५०० कोटी रुपयांच्या निधीचे निर्णय घेतले. यामध्ये ६०५ कोटींची रस्त्यांची कामे, १५० कोटींचे शहर सौंदर्यीकरण, ७५ कोटींची शौचालय दुरुस्ती, कळवा रुग्णालयासाठी ६५ कोटी, राम गणेश गडकरी रंगायतनसाठी ८.५० कोटी यांसह इतर अनेक कामांचा समावेश आहे. या प्रकल्पांसाठी निधी टप्प्याटप्प्याने मिळाल्याने संबंधित कामे तुलनेने वेगाने पूर्ण झाली आहेत.

पाणीपुरवठा, रस्ते, शौचालये, आरोग्य केंद्रे आणि इतर नागरी सुविधांसाठी १६५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यातील काही रक्कम महापालिकेला मिळाली असली, तरी उर्वरित निधी प्रलंबित आहे. कळवा येथे नवीन नाट्यगृह उभारण्यासाठी ४० कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे. घाणेकर नाट्यगृहासाठी ५ कोटी मंजूर करण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर आणखी ५ कोटींच्या निधीची मागणी करण्यात आली आहे.

रेमंड येथील जागेत नवे महापालिका मुख्यालय उभारण्यासाठी ५९४ कोटींच्या निधीला राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. काही महिन्यांपूर्वी या कामाला

दर्जावर प्रश्नचिन्ह, टक्केवारीचे राजकारण

अपुऱ्या निधीवरही टक्केवारीचे राजकारण सुरू असल्याची चर्चा आहे. प्रत्यक्षात केवळ २ कोटी रुपये मिळाले असताना, टक्केवारी मात्र संपूर्ण १०० कोटींच्या अंदाजपत्रकावर आधारित मागितली जात असल्याचे सांगण्यात येते. परिणामी कामे कशी पूर्ण करायची, असा गंभीर प्रश्न ठेकेदारांसमोर आहे. एकीकडे निधी अपुरा, तर दुसरीकडे ठराविक मुदतीत कामे पूर्ण करण्यासाठी राजकीय दबाव टाकला जात असल्याने विकासकामांच्या दर्जावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.

सुरुवात झाली असली, तरी आतापर्यंत केवळ २९.७६ कोटी रुपयेच प्रत्यक्षात पालिकेला मिळाले आहेत. शिवाय २५० कोटींचे अध्यादेश दोन टप्प्यांत मंजूर झाले असले, तरी हा निधी नेमका केव्हा मिळणार, याबाबत कोणतीही स्पष्टता नाही. वर्ष २०२४मध्ये विविध विकासकामांसाठी ८५० कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली आहे. यात तरण तलाव, खुला रंगमंच, उपवन तलाव परिसराचा विकास, महापौर निवास, वॉक-वे, मराठा भवन, व्यायामशाळा, समाज भवन, रुग्णालये, कुंपण भिंती, सायकल आणि जॉगिंग ट्रॅक, गायमुख येथील कचरा प्रकल्प, खाडी किनारा विकास, कांदळवन परिसरातील उद्याननिर्मिती आदी कामांचा समावेश आहे. मात्र, १०० कोटींच्या कामासाठी अवघे २ कोटी रुपयेच प्रत्यक्षात मिळाल्याची माहिती आहे.

निवडणुकीपूर्वी मोठा गाजावाजा करत जाहीर केलेले प्रकल्प आणि मंजूर निधी प्रत्यक्षात तुटपुंजा ठरत असल्याने ठाण्यातील ‘कथित’ विकासाचे वास्तव उघड झाले असून, याचा थेट फटका नागरिकांनाच बसत आहे.

फनेल झोनचे करायचे काय? असे आहेत काही उपाय!

निमित्त

सीताराम कुंटे
माजी मुख्य सचिव

फनेल झोनचा विषय मुंबईच्या विकासासाठी एक अडचणीचा आणि सहजासहजी न सुटणारा विषय होऊन बसला आहे. या लेखात फनेल झोनची संकल्पना काय आणि त्यातील अडचणी काय, याचे विवेचन केले आहे.

‘फनेल झोन’ म्हणजे विमानतळामुळे आजूबाजूच्या परिसरात बांधकामावर घातलेल्या मर्यादा असा आहे. मुंबईत छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आहे. त्याच्या दोन धावपट्ट्या आहेत. विमानांचे टेक-ऑफ आणि लँडिंग व्यवस्थितपणे होण्यासाठी धावपट्टीच्या दोन्ही बाजूला एक फनेलसारखा झोन तयार होतो जो आकाशात अदृश्यरीत्या आखला जातो. उड्डाण घेताना किंवा उतरताना विमाने या फनेलमधून ये-जा करतात. म्हणून या फनेल झोनमध्ये बांधकामांच्या उंचीवर मर्यादा घालण्यात येते; बांधकाम फनेलच्या आत येणार नाही, याची खबरदारी घेतली जाते.

मुंबईतील दोन धावपट्ट्यांचा विचार केल्यास चार फनेल झोन तयार होतात. त्यातच जुहू विमानतळ जोडले, तर फनेल झोन आणखी विस्तारला जातो. उपनगरांच्या दृष्टीने विचार केल्यास त्यातील जवळपास पन्नास टक्के बांधकामयोग्य जमिनी कमी-अधिक प्रमाणात फनेल झोनने बाधित झालेल्या आहेत. सांताक्रुझ, विलेपार्ले, कुर्ला, अंधेरी, बांद्रा आणि घाटकोपर या उपनगरांतील काही भाग फनेल झोनमुळे बाधित झालेले आहेत. या परिस्थितीत विशेष करून जुन्या इमारतींच्या पुनर्वसनाच्या प्रकल्पांना मोठ्या प्रमाणात अडचणी निर्माण होत आहेत. त्याचं कारण असं आहे की, पुनर्वसनाकरिता वाढीव एफएसआय विकास नियंत्रण नियमावलींच्या माध्यमातून उपलब्ध होत असतो; तांत्रिकदृष्ट्या उंच इमारती बांधणे शक्य

असते; मात्र विमानतळाच्या फनेल झोनमुळे त्या उंचीचे बांधकाम करता येत नाही. नागरी उड्डाण विभागाकडून परवानगीच मिळत नाही. यामुळे जमीन मालकांची, रहिवाशांची मोठी पंचाईत होऊन बसते. यावर शासनाने काय केले हे पाहायचे असेल, तर मार्च २०२५ मध्ये नगर विकास विभागाने काही धोरणात्मक बदल केले आहेत, यांचा उल्लेख करावा लागेल. या धोरणाद्वारे शासनाने फनेल झोनमधील पुनर्वसनाच्या योजनांकरिता विकास नियंत्रण नियमावली २०३४ अंतर्गत काही प्रोत्साहने जाहीर केलेली आहेत. त्यातील सर्वांत महत्त्वाचे आहे टीडीआरची सोय उपलब्ध करून देणे. म्हणजेच ज्या ठिकाणी पुनर्वसनाकरिता अनुज्ञेय एफएसआय फनेल झोनमुळे वापरता येत नसेल, अशा ठिकाणी न वापरलेला एफएसआय हा टीडीआर म्हणून सर्टिफिकेटद्वारे दिला जाईल आणि त्या टीडीआरचा वापर अन्य अनुज्ञेय अशा भागांमध्ये करता येईल. थोडक्यात, ज्या व्यक्ती किंवा सोसायटीची जमीन फनेल झोनने बाधित होत असेल, तर त्यांच्या नुकसानीची भरपाई टीडीआरच्या स्वरूपात मिळेल. याशिवाय तेथील इमारतींचे आराखडे मंजूर करताना प्रीमियममध्येदेखील काही सूट देण्यात आली आहे. तसेच, जिन्याच्या आणि लिफ्टच्या संदर्भात काही सवलती देण्यात आल्या आहेत. या नवीन धोरणाबाबत बरीच मतमतांतरे आहेत. लोकांच्या मनात आशा आणि निराशा हे भाव एकाच वेळी तयार झाले. आशा ही की या ज्वलंत प्रश्नाची दखल शासनाने घेऊन काही उपाययोजना केल्या तरी. निराशा अशी की, ज्या उपाययोजना शासनाने करण्याचा प्रयत्न केला आहे, त्यातून हा जटिल प्रश्न सुटत नसून अनेक नवीन प्रश्न तयार होतात.

नवीन धोरणात टीडीआर देण्याबाबत जी तरतूद आहे, त्यावर बरीच टीका होत आहे. खरंतर फनेल झोन ही संकल्पना विमानतळ सेवेत रुजू झाले तेव्हापासून आहे; म्हणजेच साधारण १९३० च्या दशकापासून. मग अनुज्ञेय उंचीच्या वरचे जे बांधकाम फनेल झोनच्या नियमानुसार करता येत नाही, त्याचा टीडीआर देणे म्हणजे पातळ हवेतून निर्माण केलेली आर्थिक व्यवस्था आहे व ही शहर नियोजनाकरिता धोक्याची आहे.

फनेल झोनमधून निघालेला टीडीआर ठिकठिकाणी वापरल्यास अनेक ठिकाणी लोकसंख्येची घनता प्रचंड वाढेल आणि पायाभूत सोयीसुविधा अतिरिक्त भार पेलू शकतील का, याबाबत साशंकता आहे. असाही विचार पुढे आला आहे की, फनेल झोनला इन्फ्रास्ट्रक्चरबाधित क्षेत्र घोषित करावे आणि संबंधितांना योग्य मोबदला द्यावा. माझ्या मते या प्रश्नावर राष्ट्रीय व राज्य पातळीवर साकल्याने विचार व्हावा. सर्व विमानतळांची वर्गवारी करून फनेल झोनची संकल्पना राबवली गेली पाहिजे आणि बाधित होणाऱ्या लोकांना योग्य मोबदला दिला गेला पाहिजे.

एआइ पर भारत के साथ विश्व

दिल्ली में संपन्न 'इंडिया एआइ इंपैक्ट समिट' के घोषणापत्र पर 86 देशों और दो अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा हस्ताक्षर किया जाना एआइ के प्रभावों पर मिले वैश्विक समर्थन को दर्शाता है. हस्ताक्षर करने वालों में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, चीन, डेनमार्क, रूस और जर्मनी आदि शामिल हैं. यह 'ग्लोबल साउथ' में आयोजित होने वाला दुनिया का पहला वैश्विक एआइ शिखर सम्मेलन तो था ही, इसमें दुनियाभर के सरकारी नीति-निर्माताओं, एआइ क्षेत्र के उद्योग विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, टेक्नोलॉजी इनोवेटर्स और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया. इस समिट का फोकस एआइ की परिवर्तनकारी क्षमता पर विचार करने के साथ-साथ, 'मानवता के लिए एआइ' के वैश्विक सिद्धांत को आगे बढ़ाना था. यह शिखर सम्मेलन एआइ के प्रशासन, सुरक्षा मानकों और समाज पर इसके प्रभाव को लेकर वैश्विक सहयोग को मजबूत करने की एक विकसित होती अंतरराष्ट्रीय प्रक्रिया का भी हिस्सा था. शिखर सम्मेलन के समापन पर अपनायी गयी घोषणा में एआइ को एक परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसके लाभों का व्यापक वितरण होना चाहिए. 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' के मार्गदर्शक विचार पर आधारित यह घोषणा एआइ के जिम्मेदार संचालन और उपयोग के लिए गहन अंतरराष्ट्रीय सहयोग और बहु-हितधारक दृष्टिकोण का आह्वान करती है. प्रतिभागियों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि वर्तमान क्षण तकनीकी विकास में एक निर्णायक मोड़ का प्रतिनिधित्व करता है. दस्तावेज में सात स्तंभों वाला एक ढांचा प्रस्तुत किया गया है, जिसे 'चक्र' कहा जाता है, और जिसमें मानव पूंजी विकास, समान पहुंच, विश्वास और सुरक्षा, ऊर्जा दक्षता, वैज्ञानिक प्रगति, संसाधन लोकतंत्रीकरण और सामाजिक हित के अनुरूप आर्थिक विकास शामिल हैं. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ह्यूमन सेंटर्ड एआइ की दृष्टि को वैश्विक स्तर पर स्वीकार किया गया है. एआइ संसाधनों, सेवाओं और टेक्नोलॉजी को समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने का लक्ष्य सभी देशों ने स्वीकार किया है. उन्होंने यह भी कहा कि आर्थिक वृद्धि के साथ सामाजिक भलाई को संतुलित करने को प्राथमिकता दी जा रही है. सुरक्षा और भरोसा इस योजना के केंद्र में हैं और इन्हें मुख्य बिंदुओं में शामिल किया गया है.

राष्ट्रीय राजधानी में संपन्न एआइ शिखर सम्मेलन में एआइ को एक परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसके लाभों का व्यापक वितरण होना चाहिए. इसके घोषणापत्र पर 86 देशों व दो वैश्विक संगठनों ने दस्तखत कर बताया कि वे एआइ पर भारत के नजरिये के साथ हैं.

टैरिफ पर ट्रंप का अगला कदम अहम

अनिल त्रिगुणायत
पूर्व राजनयिक
amb.trigunayat@gmail.com

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह संदेश गया है कि ट्रंप के टैरिफ नाजायज थे और उसका कोई ठोस आधार नहीं था, लेकिन जाहिर है, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है. हो सकता है कि अमेरिकी कांग्रेस के जरिये ट्रंप टैरिफ से जुड़ा कोई बिल पारित कराएं. वैसे मामले में फिर अदालत के पास भी करने के लिए कुछ नहीं होगा. ट्रंप ने यह धमकी भी दी है कि अमेरिकी हितों के खिलाफ काम करने वाले देशों के साथ वह व्यापार बंद कर सकते हैं. यह फैसला भारतीय निर्यातकों के लिए स्वागतयोग्य है, क्योंकि टैरिफ के दबाव से टेक्सटाइल तथा रत्न और आभूषण क्षेत्र भीषण दबाव में थे और 50 अरब डॉलर से अधिक का व्यापार प्रभावित हो रहा था.

एकतरफा टैरिफ लगाने से संबंधित डोनाल्ड ट्रंप के फैसले को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से जिस तरह गैरकानूनी बताया है, वह ट्रंप प्रशासन के लिए बड़ा झटका है. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि संविधान के तहत टैक्स और टैरिफ लगाने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं, सिर्फ संसद को है. अदालत ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कांग्रेस से मंजूरी लिये बिना टैरिफ लगाकर अपने कानूनी अधिकार का उल्लंघन किया है. ट्रंप के लिए परेशान करने वाली बात इसलिए भी है कि अपने पहले राष्ट्रपति काल में उन्होंने जिन दो जजों को नियुक्त किया था, वे भी ट्रंप प्रशासन के खिलाफ गये हैं. ऐसा माना जा रहा था कि कंजरवेटिव जज ट्रंप का साथ देंगे, लेकिन फैसला इसके उलट आया. चूंकि वहां जज जीवनभर के लिए नियुक्त होते हैं और उन्हें हटाया नहीं जा सकता, ऐसे में, ट्रंप के लिए चिंता की बात तो यह है ही.

ध्यान रखने की बात है कि अमेरिका नियम-कानूनों का पालन करने वाला देश है. यह मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया था, तभी से ट्रंप प्रशासन इस उधेड़बुन में लगा था कि अगर फैसला खिलाफ में आया, तो क्या विकल्प हो सकते हैं. फैसला करते हुए जजों की टिप्पणियां भी ट्रंप प्रशासन के लिए परेशान करने वाली हैं. प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि अमेरिका दुनिया के सभी देशों के साथ युद्ध की स्थिति में नहीं है, जबकि ट्रंप द्वारा नियुक्त एक जज ने सवाल किया कि क्या स्पेन और फ्रांस वाकई अमेरिकी सुरक्षा और औद्योगिक आधार को खतरा पहुंचाने की स्थिति में हैं? सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले के पीछे अमेरिका के पूर्व एक्टिंग सॉलिसिटर जनरल नील कत्याल का हाथ है, जो भारतीय मूल के हैं. उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (आइइइपीए) के इस्तेमाल के खिलाफ तर्क पेश किया था. उनका कहना था कि ट्रंप ने लगभग हर ट्रेडिंग पार्टनर के सामान पर 'गलत, गैर-संवैधानिक टैक्स' लगाये हैं. उनकी दलीलों ने सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप के टैरिफ की हवा निकाल दी. जैसा कि प्रत्याशित ही था, ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी अप्रसन्नता जतायी. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 'बेहद निराशाजनक' बताया और कहा कि फैसला सुनाने वाले न्यायाधीशों पर उन्हें 'बेहद शर्म' आ रही है. ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट पर 'विदेशी हितों' से प्रभावित होने का आरोप भी लगाया. अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस फैसले का विरोध करने वाले तीनों न्यायाधीशों को धन्यवाद दिया और कहा कि कई देश वर्षों से हमारा शोषण कर रहे थे, टैरिफ के जरिये हमने उस शोषण को खत्म किया था. कोर्ट के फैसले से वे खुशी से नाच रहे हैं. उन्होंने आगे कहा, 'मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वे ज्यादा देर तक नहीं नाचेंगे'.

दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नील कत्याल ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट कानून के राज और हर जगह अमेरिकियों के लिए खड़ा हुआ. कोर्ट का संदेश काफी अहम था कि राष्ट्रपति शक्तिशाली होते हैं, लेकिन हमारा संविधान उससे भी ज्यादा ताकतवर है. अमेरिका में सिर्फ कांग्रेस ही अमेरिकी लोगों पर टैक्स लगा सकती है.' अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा टैरिफ रद्द करने के फैसले के तीन घंटे के अंदर ट्रंप ने हालांकि ट्रेड एक्ट 1974 के सेक्शन 122 का इस्तेमाल करते हुए पहले 10 फीसदी ग्लोबल टैरिफ लगाया, फिर उसे बढ़ाते हुए 15 फीसदी कर अपने इरादों का परिचय दिया. यह टैरिफ 24 फरवरी से दुनियाभर के देशों पर लागू हो जायेगा. सेक्शन 122 के तहत व्यापार घाटे को संतुलित करने के लिए राष्ट्रपति को अधिकतम 15 फीसदी तक टैरिफ लगाने की शक्ति मिली है. हालांकि कानून के मुताबिक, इसे बिना संसद की मंजूरी के केवल 150 दिनों के लिए ही लागू किया जा सकता है. अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दुनियाभर में अनुकूल प्रतिक्रिया हुई है. फैसले से यह संदेश गया है कि ट्रंप के टैरिफ नाजायज थे और उसका कोई ठोस आधार नहीं था, लेकिन जाहिर है, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है. हो सकता है कि अमेरिकी कांग्रेस के जरिये ट्रंप टैरिफ से जुड़ा कोई बिल पारित कराएं. वैसे मामले में फिर अदालत के पास भी करने के लिए कुछ नहीं होगा. ट्रंप ने यह धमकी भी दी है कि अमेरिकी हितों के खिलाफ काम करने वाले देशों के साथ वह व्यापार बंद कर सकते हैं. अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐसे समय में आया है, जब भारत और अमेरिका व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की तरफ बढ़ रहे हैं. केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि नयी दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच अंतरिम ट्रेड के एग्रीमेंट मार्च में साइन होने और अप्रैल में लागू होने की संभावना है. ट्रंप ने भारत-अमेरिका ट्रेड डील के बारे में भी बयान दिया है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा टैरिफ रद्द करने के बावजूद भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील में कोई बदलाव नहीं होगा. वैसे अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला भारतीय निर्यातकों के लिए खासकर स्वागतयोग्य है. टैरिफ के दबाव से टेक्सटाइल तथा रत्न और आभूषण क्षेत्र भीषण दबाव में थे और 50 अरब डॉलर से अधिक का व्यापार प्रभावित हो रहा था. भारत इसलिए भी लाभ की स्थिति में है, क्योंकि अमेरिका से व्यापार समझौते पर अभी दस्तखत नहीं हुए हैं और भारतीय उत्पादों पर टैरिफ 18 प्रतिशत से घटकर अब 15 प्रतिशत पर आ गया है, जो जाहिर है, हमारे लिए अच्छी स्थिति है, लेकिन जिन देशों ने अमेरिका के साथ द्विपक्षीय समझौते कर लिये हैं, उन देशों को टैरिफ घटाने के लिए ट्रंप प्रशासन से बात करनी होगी.

इसके बावजूद दो चीजें बिल्कुल साफ हैं. एक तो ट्रंप टैरिफ के मामले में अनिश्चितता अभी बनी रहेगी. दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद ट्रंप अपना तौर-तरीका नहीं बदलने वाले. आखिर करीब पचास साल पुराने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के जरिये पिछले करीब एक साल से ट्रंप दुनियाभर के देशों पर टैरिफ का बोझ लाद ही रहे थे. चूंकि अमेरिकी राष्ट्रपतियों के पास आपातकालीन शक्तियां होती हैं. लिहाजा अदालत द्वारा एक प्रावधान को निरस्त कर दिये जाने के बाद वह किसी दूसरे प्रावधान की शरण लेंगे. हां, राहत की बात सिर्फ यह है कि पुराने इमरजेंसी टैरिफ के बजाय ट्रंप अब जिन कानूनों का सहारा ले रहे हैं, उसमें एक तय प्रक्रिया होती है. **(ये लेखक के निजी विचार हैं.)**

'चौरंगी' के शंकर की भाषा सरल थी, पर भाव गंभीर

कृपाशंकर चौबे
प्रोफेसर, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा
drkschaubey2@gmail.com

स्मृतिशेष

'चौरंगी' शंकर का दूसरा उपन्यास है. उनका पहला उपन्यास 'ये अनजाने' 1954 में छपा था और छपते ही क्लासिक की श्रेणी में आ गया था. शंकर स्वामी विवेकानंद पर अपनी किताबों के कारण अलग से जाने जाते हैं.

शंकर के नाम से मशहूर बांग्ला साहित्यकार मणिशंकर मुखर्जी के निधन के साथ ही भारतीय कथा साहित्य के एक जीवंत युग का अवसान हो गया है. सौ से अधिक कृतियों के एकांत स्रष्टा शंकर अपने कालजयी उपन्यास 'चौरंगी' से पूरे भारत और विदेशों में विख्यात हुए. इस उपन्यास ने पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध किया. बांग्ला उपन्यास 'चौरंगी' 1962 में प्रकाशित हुआ था और प्रकाशित होते ही उसने बांग्ला कथा साहित्य में अपनी अलग और विशिष्ट जगह बना ली थी. देज पब्लिशिंग से इस उपन्यास के अब तक 126 संस्करण निकल चुके हैं. देज पब्लिशिंग से पहले बाल साहित्य प्रकाशन से उसके 25 संस्करण निकले थे. इस तरह 'चौरंगी' के अब तक 151 संस्करण निकल चुके हैं.

शंकर की भाषा सरल थी, किंतु भाव गंभीर. वह पाठकों को कथा के अंदर ले जाते थे और चरित्रों के साथ जीने का एहसास कराते थे. 'चौरंगी' के कई विविधरंगी चरित्र पाठकों को आज भी याद हैं. इसमें लेखक पाठकों को मार्कोपोलो, बायरन, जेन, मिस ग्रे, कनि, गुड़बेरिया, लैम्ब्रेटा, अनिंद्य, विलियम, सिलवर्टन, मिसेज पकड़ासी, सुजाता मित्रा, गोमेज, करवी गुहा, श्याम सुंदर बोस, नगेन पाल, नित्यहरि भट्टाचार्य, शंपा सान्याल, शराबजी, मिस्टर बनर्जी जैसे चरित्रों से मिलवाता है. 'चौरंगी' में इतने ज्यादा विविधरंगी चरित्र हैं कि इसे सहज ही मानव जीवन की महागाथा मान लिया गया है. सिर्फ चरित्र ही नहीं, पाठकों को 'चौरंगी' के कई संवाद भी याद हैं. जैसे बायरन साहब का यह संवाद, 'जीवन ऐसा ही है. अपने दुख के धुएं से उबकर बाहर आओ, तो और ज्यादा बुरी हालत पाओगे. हमारे अपने दुख को दबाकर औरों का दुख और भी तकलीफ देने लगेगा'. ऐसा ही एक और अविस्मरणीय संवाद है, 'सृष्टि में जितना आनंद था, जितना सौंदर्य था, सारा कुछ पृथ्वी के अविचारी मनुष्यों ने समाप्त कर दिया है. बच गया है केवल दुख. किसी के लिए भी, कहीं भी सुख का एक कण नहीं है'. इस औपन्यासिक कृति में लेखक ने शाहजहां होटल के मार्फत केवल कोलकाता का ही नहीं, अपितु संपूर्ण मानव व्यवहार का मुकम्मल चित्र प्रस्तुत करने में सफलता पायी है. लेखक मानव व्यवहार की परत-दर-परत गांठें खोलता है. कई बार तो एक ही व्यक्ति के चरित्र के दो रूप सामने आते हैं. उपन्यास बताता है कि महानगर के जीवन में महत्वाकांक्षाओं के बीच किस तरह संबंध टूटते हैं और इच्छाएं दम तोड़ती हैं. किंतु टूटते-टूटते भी बहुत कुछ बचा रह जाता है. शाहजहां होटल में काम करते हुए नायक को सबसे ज्यादा जो हासिल हुआ, वह था-साथ काम करनेवालों का स्नेह. यह सहज मानवीय स्नेह ही इस उपन्यास के बहुरंगी चरित्रों की महागाथा को बांधे रखता है.

(07.12.1933-20.02.2026)

देज पब्लिशिंग से प्रकाशित 'चौरंगी' के संस्करणों की सूचना चार पृष्ठों में छापी गयी है. शंकर ने अपने जीते जी इस उपन्यास के 151 संस्करण देखे. इस उपन्यास के प्रकाशन के पचास वर्ष पूरे होने पर एक भव्य, किंतु आत्मीय कार्यक्रम में लेखक की उपस्थिति में प्रकाशक सुधांशु शेखर दे और अप्पू दे ने इसका 111वां संस्करण निकाला था. देश-विदेश में कई भाषाओं में 'चौरंगी' का अनुवाद हुआ. अंग्रेजी, स्पेनिश, इटैलियन और फ्रेंच में यह अनूदित हो चुका है. 'चौरंगी' का हिंदी में राजकमल चौधरी ने अनुवाद किया था और राजकमल प्रकाशन से यह उपन्यास पहली बार 1964 में प्रकाशित हुआ था. राजकमल से इसके कई हार्ड बाउंड संस्करण निकल चुके हैं. यह किताब पेपरबैक में भी उपलब्ध है. हिंदी पाठक इसे हाथों-हाथ लेते रहे हैं. उन्हें यह लगता ही नहीं कि वे अनूदित किताब पढ़ रहे हैं.

'चौरंगी' शंकर का दूसरा उपन्यास है. उनका पहला उपन्यास 'ये अनजाने' 1954 में छपा था और छपते ही क्लासिक की श्रेणी में आ गया था. शंकर स्वामी विवेकानंद पर अपनी किताबों के कारण अलग से जाने जाते हैं. इनकी लगभग हर किताब प्रसिद्धि के नये शिखर का स्पर्श करती रही है. उनके कहानी संग्रह की किताब 'एक-दुई-तीन', यात्रा वृत्तांत की किताब 'ए पार बांग्ला ओपार बांग्ला और ललित निबंधों की किताब 'जा बोलो ताई बोलो' और 'रसोवती' को भी क्लासिक का दर्जा मिला है. शंकर के हर उपन्यास में विमान की तरह एक टेक ऑफ रहता है, फिर कुछ समय उड़ने का मामला होता है और उसके बाद लैंडिंग का. उनकी कई कथाकृतियों पर फिल्में बनीं. 'सीमाबद्ध' के आधार पर सत्यजित राय ने बहुप्रशंसित फिल्म 'कंपनी लिमिटेड' बनायी थी. सत्यजित राय ने 'जन अरण्य' पर भी उसी नाम से फिल्म बनायी, जिसे अंतरराष्ट्रीय ख्याति हासिल हुई. 'चौरंगी' पर भी फिल्म बनी.

(ये लेखक के निजी विचार हैं.)

देश दुनिया

नेपाली मतदाताओं को सोच-समझकर अपने मत का उपयोग करना होगा

नेपाल की पुरानी राजनीतिक पार्टियां बीते वर्ष सितंबर में हुए जेन जेड आंदोलन के दौरान अपने खिलाफ भारी जन आक्रोश देख चुकी हैं. अब जबकि चुनाव नजदीक है, तो राजनीतिक पार्टियां संभवतः अपने खिलाफ नकारात्मक लहर उठने से डर रही हैं. विदित हो कि नेपाल में चुनावी लोकतंत्र की शुरुआत के बाद से हर बार मतदाताओं को अपमानित होना पड़ा है. उनके सपने चकनाचूर हो गये हैं, क्योंकि चुनावी वादे कभी पूरे ही नहीं होते. संरचनात्मक और संस्थागत सुधारों की वकालत करने वाली क्रांतियों के कई दौर के बावजूद नागरिक अभी भी राजनीतिक दलों द्वारा ठगा हुआ महसूस करते हैं. इसी कारण नेपाली मतदाताओं ने जेनरेशन जेड आंदोलन के दौरान बड़े पैमाने पर प्रदर्शनों में भाग लिया, उनका समर्थन किया और उनके साक्षी बने. यह आंदोलन इतना व्यापक था कि न केवल मौजूदा सरकार हटने पर मजबूर हुई, बल्कि पांच मार्च, 2026 को चुनाव कराने के लिए एक अंतरिम सरकार का गठन भी किया गया. जाहिर है कि पांच मार्च को होने वाले चुनावों का सामना कर रहे नेपाली मतदाता बदलाव के विकल्पों पर विचार कर रहे होंगे. चुनावों से पहले कई जनरेशन जेड प्रतिनिधि और नागरिक समाज के नेता संवैधानिक बदलाव चाहते थे. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. अब चुनाव नजदीक आ चुका है. चुनाव के बाद मनमुताबिक परिणाम आये, इसके लिए मतदाताओं को मतदान से पहले अधिक समझदारी से सोचने की जरूरत है. यदि चुनाव के बाद निराशाजनक परिणाम आते हैं, तो जनादेश के खंडित होने की आशंका है. इससे सत्ता की होड़ में लगी राजनीतिक पार्टियों के बीच सौदेबाजी होगी. ऐसी स्थिति में, शासन और जनसेवा गौण हो जायेंगे. ऐसे परिणामों से बचने के लिए मतदाताओं को उम्मीदवारों से सुधार का वादा लेना होगा और उनसे प्रश्न पूछना होगा कि वे संरचनात्मक सुधारों को किस तरह अंजाम देंगे और उसमें आम नागरिकों को किस तरह शामिल करेंगे. वास्तविक सुधार के लिए संस्थाओं को बदलने की स्पष्ट प्रतिबद्धता आवश्यक है.

THE KATHMANDU POST
WITHOUT FEAR OR FAVOUR

-विद्याधर मलिक

बोधि वृक्ष

भीतर का परिवर्तन

संसार में हर जीव प्रकृति के नियमानुसार अपना जीवन व्यतीत करता है. जैसे गाय कभी मांस नहीं खाती, शेर कभी घास नहीं खाता, चिड़िया अपने बनाये घोंसले में ही रहती है, जंगली जानवर जंगलों में ही रहते हैं. वे प्रकृति की मर्यादाओं को नहीं तोड़ते, क्योंकि उन्हें अपनी सीमा का बोध है. इनकी तुलना में आज मनुष्य क्या से क्या कर बैठा है? सुंदर-सुंदर बंगले, सुंदर बाग-बगीचे, घूमने-फिरने के अनेक साधन और बेशुमार धन-दौलत के साथ ऐशो-आराम की जिंदगी जी रहा है. पर जल, हवा, अग्नि, गर्मी, सर्दी आदि पर विज्ञान के चमत्कारों द्वारा अपना स्वामित्व जताने वाला मनुष्य क्या अपने आपको निर्भय, दयालु, कृपालु, परोपकारी, स्नेही, हर्षित, सुखी व संतुष्ट कह सकता है? नहीं. आज भले हमारे घरों में रेफ्रीजरेटर चल रहे हैं, परंतु दिल में मौजूद क्रोध की गर्मी, ईर्ष्या की तपिश और असंतोष की आग हमें भीतर ही भीतर झुलसा रही है. कड़वा ही सही, परंतु यही सत्य है. आज भले ही हम नृत्य नाटिकाओं एवं फिल्मों के माध्यम से देवी-देवताओं का रूप धारण कर लेते हैं, पर क्या केवल अच्छा मेकअप कर, सुंदर बनकर हम अपनी सीरत भी उन जैसी बना पाते हैं? स्मरण रहे! चित्र की नकल करना बहुत आसान है, परंतु चरित्र भी उन जैसा हो, इसके लिए हमें कड़ी मेहनत करनी होगी. क्योंकि चरित्र निर्माण किसी रंग-रोगन से नहीं होता, वह तो विचारों की शुद्धि और कर्मों की पवित्रता से होता है. गांधीजी का रामराज्य का जो सपना था, क्या वह कभी साकार हो पायेगा? यदि हम सचमुच रामराज्य चाहते हैं, तो हमें सर्वशक्तिमान परमात्मा द्वारा दिये गये दिव्य गुणों को फिर से अपने भीतर जगाना होगा और उन गुणों के प्रकाश से दूसरों के जीवन के अंधेरे को मिटाना होगा और एक नयी सृष्टि का निर्माण करना होगा. यह कार्य सुनने में जितना मुश्किल लगता है, वास्तव में उतना है नहीं. आरंभ में बस अपने मन में छोटे-छोटे परिवर्तन करने होंगे. शिकायत के स्थान पर कृतज्ञता, प्रतिस्पर्धा के स्थान पर सहयोग और स्वार्थ के स्थान पर सेवा को स्थान देना है. यदि हम सब इस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ेंगे, तो रामराज्य आना मुश्किल नहीं है.

-ब्रह्माकुमार निकुंज जी

प्रबंध सूत्र

एक से ज्यादा कौशल जरूरी

आलोक पुराणिक
स्तंभकार
puranika@gmail.com

भारत के सॉफ्टवेयर जगत में हड़कंप है. कभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की नौकरियां मोटी तनख्वाह वाली और सुरक्षित मानी जाती थीं. अब एआइ ने बहुत कुछ बदल दिया है. जो काम सॉफ्टवेयर इंजीनियर करते थे, उनमें से बहुत-सा काम एआइ द्वारा बहुत सस्ते में कराना संभव हो रहा है. उद्योग जगत कम लागत में अधिकतम लाभ के सिद्धांत पर चलता है. ऐसी सूरत में सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की मांग वैसी नहीं रहनेवाली, जैसी कुछ समय पहले होती थी. ऐसी हालत धीमे-धीमे कई और धंधों में हो सकती है. जो काम कोई कर रहा है, उसे करने के लिए अब एआइ का कोई औजार आ गया. अस्सी के दशक में जब कंप्यूटर व्यापक तौर पर आ रहे थे, तब ऐसी आशंका व्यक्त की जाती थी कि कंप्यूटर बहुत-सी नौकरियां खा जायेंगे. कंप्यूटरों ने बहुत नौकरियां खायीं और बहुत नयी नौकरियां पैदा कीं. दिक्कत उनको आयी, जो तब पचास की उम्र के आसपास थे और कंप्यूटरों से दोस्ती करने में उन्हें दिक्कत आ रही थी. कुछ ऐसा संकट अब आ सकता है कि कई धंधों में जिस कौशल पर रोजगार टिका था, वह रोजगार एआइ के जरिये सस्ते में हो रहा है.

एक से ज्यादा कौशल को मिलाकर नौकरी के बाजार में अपनी जगह बनाना अब समय की जरूरत है. पत्रकार हैं, तो इनफोग्राफिक्स का अतिरिक्त ज्ञान बेहतर है. सेल्स में हैं, तो सेल्स के नये औजारों से दोस्ती करना जरूरी है. अध्यापक हैं, तो एआइ की चुनौतियों को भांपकर रणनीति बनाना बेहतर है. आज हमें 'विविधता' की आवश्यकता है. एक व्यक्ति को अपने भीतर ज्ञान के कई 'वृक्ष' लगाने चाहिए, ताकि यदि एक कौशल का संगीत मौन हो जाए, तो दूसरे की लय हमें थामे रखे. एक पुरानी सूक्ति है, 'अनन्तशास्त्रं बहुलाश्च विद्याः' (शास्त्र अनंत हैं और विद्याएं बहुत सारी हैं).

आज के दौर में जिसे हम 'करियर' कहते हैं, वह किसी एक विद्या तक सीमित नहीं रह गया है. यदि आप केवल एक कौशल पर निर्भर हैं, तो 'कूपमंडूक' बनने के जोखिम में रहते हैं. जैसे ही कुएं का पानी (बाजार की मांग) सूखता है, जीवन संकट में आ जाता है. इसके विपरीत, बहु-कौशल वाला व्यक्ति उस नदी की तरह है, जो अपना मार्ग स्वयं ढूंढ लेती है. यहां 'विद्या' का अर्थ केवल डिग्री नहीं, बल्कि विभिन्न प्रकार की 'कलाओं' का अर्जन है. हमें समझना होगा कि भविष्य उन लोगों का नहीं है, जो केवल 'एक काम' बहुत अच्छा करते हैं, बल्कि उनका है जो 'कई काम' अच्छा कर लेते हैं और उन्हें जोड़ पाते हैं. क्लास रूम में बेहतर लेक्चर देना और उनके वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालने की तकनीकी दक्षता हों, तो टीचर की जिंदगी बेहतर हो जायेगी. इस तरह से हर क्षेत्र के व्यक्ति को अपने क्षेत्र की तकनीकी चुनौतियां समझनी होंगी.

आपके पत्र

गलत निर्णय ने ली छात्रा की जान

बिहार के पटना जिले के मसौढ़ी क्षेत्र में 10वीं की एक छात्रा ट्रेन लेट होने के कारण परीक्षा केंद्र पर सात मिनट की देरी से पहुंची. इस कारण उसे परीक्षा नहीं देने दिया गया. इससे वह इतनी निराश हो गयी कि अपनी जान ही दे दी. परीक्षा संचालकों के एक गलत निर्णय से एक छात्रा की जान चली गयी. कानून और नियम एक तरफ हैं, पर मानवता और व्यावहारिकता दूसरी तरफ. किसी की मेहनत बर्बाद करने और जीवन से खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है.

वीरेन्द्र कुमार जाटव, दिल्ली

बच्चों पर मोबाइल का दुष्प्रभाव

मोबाइल और सोशल मीडिया का ऐसा नशा है कि बच्चे इसके पीछे अपना बहुमूल्य समय नष्ट कर रहे हैं. मोबाइल का अत्यधिक उपयोग उनकी शारीरिक-मानसिक स्थिति को प्रभावित कर रहा है. बच्चों को इस लत से बाहर निकलने के लिए बहुत जरूरी है कि घर के बड़े मोबाइल पर समय बिताने की अपनी आदत बदलें. यह शिक्षकों का भी दायित्व है कि वे मोबाइल के दुष्प्रभाव से बच्चों को अवगत करायें. यदि अभी नहीं चेता गया, तो बच्चों का भविष्य मोबाइल के अंधेरे में कहीं गुम हो जायेगा.

धीरेंद्र कुमार, ईमेल से

चिंतन

ट्रेड डील पर सावधान और सतर्क रहने की जरूरत

मुद्दा
महेन्द्र तिवारी

भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित अंतरिम व्यापार समझौते (आईटीए) पर अनिश्चितता एक बार फिर गहरा गई है। 23 से 26 फरवरी तक वाशिंगटन में होने वाली बैठक का टल जाना केवल एक तारीख का बदलना नहीं, बल्कि बदलते वैश्विक व्यापार समीकरणों का संकेत है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ संबंधी रुख में 24 घंटे के भीतर आए बदलावों ने इस अनिश्चितता को और बढ़ा दिया है। पहले सभी वैश्विक टैरिफ को समाप्त करने की बात, फिर 10% का सार्वभौमिक टैरिफ और उसके तुरंत बाद 15% का संशोधित टैरिफ यह क्रम बताता है कि अमेरिकी व्यापार नीति फिलहाल स्थिरता से दूर है। यह अस्थिरता किसी भी देश के लिए रणनीतिक चुनौती से कम नहीं। ऐसे परिदृश्य में भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण है संयम, विवेक और दीर्घकालिक सोच के साथ आगे बढ़ना जरूरी है। मूल प्रस्ताव में भारत पर 18% टैरिफ लागू होने की बात थी। अब जब 15% का ग्लोबल टैरिफ प्रभावी हो रहा है, तो तकनीकी रूप से यह भारत के लिए अपेक्षाकृत राहत की स्थिति है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस राहत को स्थायी माना जा सकता है? जब नीतिगत फैसले इतने कम समय में बदल रहे हों, तब किसी भी समझौते को अंतिम मान लेना जोखिम भरा हो सकता है। यदि अमेरिकी प्रशासन का रुख अस्थिर बना रहता है, तो भारत को हर शर्त का सूक्ष्म मूल्यांकन करना होगा, ताकि भविष्य में अचानक नीति परिवर्तन से भारतीय निर्यातकों को नुकसान न उठाना पड़े। प्रस्तावित समझौते में कुछ सकारात्मक पहलू भी हैं। जेनेरिक दवाओं, रत्न एवं हीरे और विमान पार्ट्स पर जीरो टैरिफ की बात भारतीय उद्योग के लिए बड़ा अवसर हो सकती है। टेक्सटाइल, चमड़ा, फुटवियर, प्लास्टिक, रबर उत्पाद, ऑर्गेनिक केमिकल्स और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों को अमेरिकी बाजार में बेहतर पहुंच मिलने की संभावना है। अमेरिका का लगभग 30 ट्रिलियन डॉलर का बाजार भारतीय एमएसएमई, किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों और युवाओं के लिए नए अवसर खोल सकता है। विशेषकर फार्मास्यूटिकल सेक्टर, जिसमें भारत वैश्विक स्तर पर मजबूत स्थिति रखता है, उसे बेहतर शर्तों के साथ प्रवेश मिलने से निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। लेकिन यह अवसर तभी सार्थक होंगे, जब शर्तें स्पष्ट, स्थिर और पारदर्शी हों। भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि टैरिफ में दी गई छूट या रियायतें अस्थायी राजनीतिक फैसलों की भेंट न चढ़ें। विमान पार्ट्स पर अमेरिकी सेक्शन 232 के तहत छूट और ऑटो पार्ट्स के लिए टैरिफ रेट कोटा जैसी व्यवस्थाएं भारतीय विनिर्माण क्षेत्र के लिए सकारात्मक संकेत हैं। लेकिन यह भी ध्यान रखना होगा कि अमेरिका अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर भविष्य में किसी भी समय नई शर्तें जोड़ सकता है। भारत को चाहिए कि वह इन प्रावधानों को केवल निर्यात अवसर के रूप में न देखे, बल्कि घरेलू विनिर्माण क्षमता बढ़ाने, गुणवत्ता सुधारने और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टिके रहने की रणनीति के साथ जोड़े। अमेरिकी नीति में दिख रही अनिश्चितता यह संकेत देती है कि भारत को जल्दबाजी में कोई अंतिम निर्णय नहीं लेना चाहिए। समीक्षा, पुनर्मूल्यांकन और सभी हितधारकों से परामर्श के बाद ही आगे बढ़ना समझदारी होगी। कुल मिलाकर बदलते वैश्विक व्यापार परिदृश्य में भारत को उत्साह नहीं, बल्कि संयम, सावधानी और सतर्कता के साथ कदम बढ़ाने होंगे। यही नीति देश के किसानों, उद्योगों और उभरते उद्यमियों के हितों की वास्तविक रक्षा कर सकेगी।

बदलता टैरिफ और भारत की रणनीति

25 फरवरी 2026 से प्रभावी होने वाले इन 15% के शुल्कों का सीधा प्रहार भारत के औषधीय निर्माण, वस्त्र उद्योग और अभियांत्रिकी वस्तुओं पर पड़ेगा। भारतीय औषधीय क्षेत्र का 20% निर्यात केवल अमेरिका को होता है, जो अब महंगा हो जाएगा। भारत को अब केवल अमेरिका पर केंद्रित न रहकर उन देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर पुनः विचार करना आवश्यक है जहां भारतीय वस्तुओं की मांग बढ़ सकती है। अमेरिकी न्यायालय के निर्णय से सिद्ध है कि वहां की लोकतांत्रिक संस्थाएं राष्ट्रपति की शक्तियों पर अंकुश लगा सकती हैं, और भारत को अपनी कानूनी दलीलों और कूटनीतिक वार्ताओं में इसका लाभ उठाना चाहिए। 150 दिनों की समय सीमा भारत के लिए अवसर की खिड़की है जिसमें वह अपनी मोलभाव करने की शक्ति प्रदर्शित कर सकता है।

ट्रंप प्रशासन द्वारा वैश्विक आयात पर लगाए गए नए करों ने अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक जगत में एक अभूतपूर्व हलचल पैदा कर दी है। वर्ष 2026 के शुरुआती महीनों में अमेरिकी शासन और न्यायपालिका के बीच जो खींचतान देखने को मिली है, उसने भारत जैसे बड़े व्यापारिक साझेदारों के लिए अनिश्चितता और अवसर दोनों की स्थिति उत्पन्न की है। 20 फरवरी 2026 को अमेरिकी उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति द्वारा पूर्व में लगाए गए कुछ विशेष शुल्कों को अवैध ठहराते हुए यह स्पष्ट किया कि अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम के तहत दी गई शक्तियों का असीमित उपयोग नहीं किया जा सकता। इस न्यायिक निर्णय ने भारत के लिए कुछ समय के लिए राहत की स्थिति उत्पन्न की थी, क्योंकि इससे पारस्परिक करों की दर जो अठारह से पच्चीस प्रतिशत तक जा सकती थी, वह घटकर न्यूनतम व्यापारिक दरों पर आने की संभावना बन गई थी। किंतु इसके तुरंत बाद अमेरिकी नेतृत्व ने व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 122 का प्रयोग करते हुए वैश्विक स्तर पर पहले दस प्रतिशत और फिर पंद्रह प्रतिशत के नए शुल्कों की घोषणा कर दी। ये नए शुल्क 150 दिनों की अवधि के लिए लागू किए गए हैं, जिसका मुख्य आधार भुगतान संतुलन की समस्या को बताया गया है।

भारत के दृष्टिकोण से देखें तो अमेरिका उसका सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है, जहां वह प्रतिवर्ष लगभग अठारह प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ अठहत्तर अरब डॉलर से अधिक का माल भेजता है। अमेरिकी प्रशासन का यह तर्क कि अन्य देश दशकों से उनका शोषण कर रहे हैं और व्यापार घाटे को कम करना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है, भारत के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करता है। भारतीय वाणिज्य मंत्रालय ने इन परिस्थितियों का सूक्ष्मता से आकलन करना आरंभ कर दिया है। 25 फरवरी 2026 से प्रभावी होने वाले इन पंद्रह प्रतिशत के शुल्कों का सीधा प्रहार भारत के औषधीय निर्माण, वस्त्र उद्योग और अभियांत्रिकी वस्तुओं पर पड़ेगा। भारतीय औषधीय क्षेत्र का लगभग बीस प्रतिशत निर्यात केवल अमेरिका को होता है, जो अब महंगा हो जाएगा। इसी प्रकार वस्त्र उद्योग में दस प्रतिशत की हिस्सेदारी और अभियांत्रिकी वस्तुओं की व्यापक पहुंच पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अमेरिकी वित्त विभाग ने यह भी संकेत दिया है कि यद्यपि यह कदम वर्तमान में अस्थायी हैं, परंतु आने वाले समय में राष्ट्रीय सुरक्षा और अनुचित व्यापार प्रथाओं से संबंधित अन्य धाराओं के अंतर्गत इन्हें स्थायी रूप से भी लागू किया जा सकता है।

भारत की प्रतिक्रिया इस पूरे विवाद में बहुत ही संतुलित और परिपक्व रही है। भारत सरकार ने नियम-आधारित व्यापार व्यवस्था पर जोर देते हुए यह स्पष्ट किया है कि वह बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने की पक्षधर है। 7 फरवरी 2026 को जारी किए गए संयुक्त वक्तव्य में भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा बदलाव करते हुए रूस से कच्चा तेल खरीदने की मात्रा कम करने और उसके बदले अमेरिका से ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी और कोयले की खरीद बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई है। यह अनुमान लगाया गया है कि भारत आने वाले समय में अमेरिका से लगभग पांच सौ अरब डॉलर की खरीद कर सकता है, जो दोनों देशों के बीच व्यापारिक संतुलन को बेहतर बनाने में सहायक सिद्ध होगा। भारत का मानना है कि यदि द्विपक्षीय व्यापार समझौता सफलतापूर्वक संपन्न होता है, तो वह इन अतिरिक्त शुल्कों से मुक्ति पा सकता है। भारतीय संघ बजट

2026 में भी इस दिशा में दूरदर्शिता दिखाई गई है, जहां निर्यातकों को राहत देने के लिए सीमा शुल्क में कटौती की गई है। व्यक्तिगत आयात पर करों को बीस प्रतिशत से घटाकर दस प्रतिशत करना इसी रणनीति का हिस्सा है।

भारत की आगामी रणनीति बहुआयामी होनी चाहिए ताकि अमेरिकी बाजार पर उसकी निर्भरता कम हो और वह एक स्वावलंबी आर्थिक शक्ति के रूप में उभर सके। सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ निर्यात का विविधीकरण है। भारत को अब केवल अमेरिका पर केंद्रित न रहकर यूरोपीय संघ, दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के संगठन और अफ्रीकी महाद्वीप के उभरते बाजारों की ओर देखना होगा। उन देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर पुनः विचार करना आवश्यक है जहां भारतीय वस्तुओं की मांग बढ़ सकती है। दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष घरेलू विनिर्माण क्षमता को सुदृढ़ करना है। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से भारत ने पहले ही स्मार्टफोन और विद्युत चालित वाहनों के क्षेत्र में सफलता प्राप्त की है, जिसे अब अन्य क्षेत्रों में भी दोहराने की आवश्यकता है। मूल्य संवर्धन की शृंखला में ऊपर की ओर बढ़ना भारत के लिए अनिवार्य है ताकि वह केवल कच्चे माल का निर्यातक न रहकर उच्च तकनीक वाली वस्तुओं का निर्माता बने। इस व्यापारिक विवाद ने 'मित्र-तटीयकरण' की अवधारणा को भी जन्म दिया है, जिसका अर्थ है कि अमेरिकी कंपनियां चीन जैसे देशों से अपना उत्पादन हटाकर भारत जैसे मित्र राष्ट्रों में स्थानांतरित करें। यह लंबी अवधि में भारत के लिए वरदान सिद्ध हो सकता है। यदि अमेरिकी कंपनियां भारत में निवेश करती हैं और यहां से वैश्विक आपूर्ति सुनिश्चित करती हैं, तो टैरिफ के प्रभाव को कम किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, भारत को विश्व व्यापार संगठन जैसे बहुपक्षीय मंचों पर भी अपनी आवाज बुलंद रखनी होगी। यदि अमेरिकी प्रशासन धारा 122 का दुरुपयोग करता है, तो भारत को अन्य प्रभावित राष्ट्रों के साथ मिलकर एक सामूहिक मोर्चा बनाना चाहिए। जी-20 और क्वाड जैसे समूह भी इस दिशा में कूटनीतिक दबाव बनाने के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। जवाबी कर लगाना एक अंतिम विकल्प होना चाहिए, क्योंकि इससे व्यापार युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होगी, जैसा कि हमने 2018 में देखा था।

डिजिटल सेवाओं और सॉफ्टवेयर निर्यात के क्षेत्र में भारत की स्थिति अधिक सुरक्षित है क्योंकि ये क्षेत्र भौतिक वस्तुओं पर लगने वाले सीमा शुल्कों से कम प्रभावित होते हैं। भारत को अपनी इस शक्ति का लाभ उठाना चाहिए। साथ ही, निर्यातकों के लिए बीमा योजनाओं और धन वापसी की प्रक्रियाओं को सरल बनाना होगा। अमेरिकी न्यायालय के निर्णय ने यह सिद्ध कर दिया है कि वहां की लोकतांत्रिक संस्थाएं राष्ट्रपति की शक्तियों पर अंकुश लगा सकती हैं, और भारत को अपनी कानूनी दलीलों और कूटनीतिक वार्ताओं में इस पक्ष का लाभ उठाना चाहिए। 150 दिनों की समय सीमा भारत के लिए एक अवसर की खिड़की है जिसमें वह अपनी मोलभाव करने की शक्ति का प्रदर्शन कर सकता है। प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताएं इस गतिरोध को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। अंततः, ट्रंप प्रशासन की आक्रामक व्यापारिक नीतियां भारत को अपनी आर्थिक नीतियों के पुनर्मूल्यांकन का संदेश दे रही हैं। यह विवाद न केवल एक चुनौती है, बल्कि भारत के लिए अपनी विनिर्माण शक्ति को वैश्विक मानकों के अनुरूप ढालने का एक संकेत भी है। यदि भारत चतुराई और दृढ़ता के साथ अपनी रणनीति पर चलता है, तो वह इस संकट को एक ऐसे अवसर में बदल सकता है जहां उसकी अर्थव्यवस्था और अधिक लचीली, विविध और स्वतंत्र होकर उभरेगी। वैश्विक व्यापार के इस संक्रमण काल में भारत की भूमिका एक तटस्थ और नियम-पालक राष्ट्र की होनी चाहिए जो अपने हितों की रक्षा के साथ-साथ वैश्विक आर्थिक स्थिरता का भी सम्मान करे। संतुलित मार्ग ही वह एकमात्र रास्ता है जो भारत को एक विकसित राष्ट्र की ओर ले जाएगा और उसे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का एक विश्वसनीय केंद्र बनाएगा।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)
लेख पर अपनी प्रतिक्रिया haribhoomi@gmail.com पर दे सकते हैं।

कला बनाम समुदाय
अम्बरीष प्रजापति

फिल्म 'घूसखोर पंडित' विवाद और अभिव्यक्ति

भारतीय सिनेमा और विवादों का चोली-दामन का साथ रहा है, लेकिन हाल ही में नेटफ्लिक्स पर आने वाली फिल्म 'घूसखोर पंडित' के नाम पर मचे बवाल ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19(1)(a) की सीमाओं को एक बार फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है। फिल्म के शीर्षक को लेकर न केवल सामाजिक विरोध हुआ, बल्कि देश की सर्वोच्च अदालत को भी इस मामले में हस्तक्षेप करना ही पड़ा। फिल्म के निर्माता नीरज पांडे और मुख्य अभिनेता मनोज बाजपेयी की इस फिल्म का शीर्षक जैसे ही सार्वजनिक हुआ। ब्राह्मण समुदाय और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया। जनता की भावना यह थी कि 'घूसखोर' जैसे नकारात्मक विशेषण को एक विशिष्ट जाति सूचक शब्द पंडित के साथ जोड़ना पूरे समुदाय की छवि को धूमिल करने और रूढ़िवादिता को बढ़ावा देने का प्रयास है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अलावा कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन भी हुए। यहां तक कि एफआईआर भी दर्ज की गई।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुयान की पीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए फिल्म निर्माताओं को कड़ी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणियां करते हुए स्पष्ट कहा कि किसी भी समुदाय को नीचा दिखाने वाला शीर्षक नैतिकता और सार्वजनिक व्यवस्था के खिलाफ है। जस्टिस नागरत्ना ने याद दिलाया कि हमारे संविधान निर्माताओं ने विविधता के बीच भाईचारे की अवधारणा रखी थी, जिसे कला के नाम पर खंडित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने दो टूक कहा कि जब तक शीर्षक नहीं बदला जाता, फिल्म रिलीज नहीं होगी। उसके बाद अभी ताजा सुनवाई में फिल्म निर्माताओं ने अदालत में हलफनामा दायर कर सूचित किया कि उन्होंने 'घूसखोर पंडित' शीर्षक को पूरी तरह वापस ले लिया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि फिल्म से संबंधित सभी पुराने प्रोमोशनल मटेरियल हटा दिए गए हैं और नया नाम ऐसा होगा जो पुराने नाम से मिलता-जुलता नहीं होगा। इस आश्वासन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया।

यह विवाद फिल्म सेंसर बोर्ड और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ओटीटी के नियमों पर भी सवाल उठाता है। आमतौर पर सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली फिल्मों को सिनेमैटोग्राफ एक्ट 1952 के तहत कड़े दौर से गुजरना पड़ता है, लेकिन ओटीटी सामग्री को लेकर नियम थोड़े अलग हैं। क्या ओटीटी प्लेट फॉर्म्स को भी फिल्मों की तरह सेंसर बोर्ड के कड़े दायरे में आना चाहिए? यह विवाद कोई पहली बार नहीं है इससे पहले भी पद्मावत, लक्ष्मी, सत्य प्रेम की कथा, बिल्लू बार्बर, रामलीला, मेंटल है क्या, लवरात्रि, पृथ्वीराज और सिंह साहिब द ग्रेट जैसी कई फिल्मों के समय भी हुआ था। धार्मिक प्रतीकों, नाम के गलत इस्तेमाल या सामुदायिक भावनाओं के प्रति असंवेदनशीलता के दावों के चलते दबाव में इन फिल्मों के नाम बदलने पड़े थे।

"फिल्म का उद्देश्य मनोरंजन और जागरूकता होना चाहिए। जब कला विवादों की ढाल बनकर किसी की भावनाओं को आहत करती है, तो वह अपनी मौलिकता खो देती है। 'घूसखोर पंडित' विवाद भारतीय फिल्मकारों के लिए एक चेतावनी भी है और जिम्मेदारी का पाठ भी।"

विवाद के बाद फिल्म के ट्रेलर री-एडिट करने, डिजिटल मार्केटिंग से पुराने नाम के लिंक हटाने और नई ब्रांडिंग करने में आने वाला भारी खर्च का नुकसान होना। विवादों में आने से फिल्म की नेगेटिव पब्लिसिटी से कई बार बड़े ब्रांड्स विज्ञापन से हाथ खींच लेते हैं जिसके कारण भारी आर्थिक नुकसान का खामियाजा झेलना पड़ता है। इसलिए फिल्म निर्माताओं को फिल्म की घोषणा से पहले ही 'सोशल ऑडिट' या कानूनी सलाह लेनी चाहिए ताकि बाद में होने वाले आर्थिक नुकसान व विवाद से बचा जा सके।

सिनेमा समाज का दर्पण है, लेकिन दर्पण को ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी वर्ग विशेष की छवि को विकृत ही कर दे। घूसखोर पंडित विवाद यह सीख देता है कि क्रिएटिव फ्रीडम का अर्थ 'जिम्मेदारी से मुक्ति' नहीं है। कला तभी सार्थक है जब वह समाज को जोड़ने का काम करे, न कि विवादों के जरिए सुर्खियां बटोरने का। फिल्म की सफलता उसके शीर्षक के विवाद में नहीं, बल्कि उसकी कथावस्तु में होनी चाहिए। यदि कहानी दमदार है, तो नाम बदलने से उसकी आत्मा नहीं मरती। फिल्मकारों को अब समझना होगा कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में 'अभिव्यक्ति' और 'संवेदनशीलता' को एक ही पटरी पर साथ चलना होगा।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लोकहित में त्याग करने वाले ही बनते हैं संत

संकलित
दर्शन

सब कुछ क्षणिक होते हुए भी इस जगत की अनंत यात्र का कभी अंत नहीं होता। यह अनवरत गतिमान रहती है। वास्तव में त्याग की पवित्र भावना ही इसकी गतिशीलता और जीवंतता का कारण है। इसलिए जिन गुणों से मानव जीवन महान बनता है, त्याग उनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जैसे-शीतलता के बिना जल, दाहकता के बिना अग्नि, स्पर्श के बिना वायु का कोई अस्तित्व नहीं। उसी प्रकार त्याग के बिना मानव जीवन का कोई मूल्य नहीं, परंतु त्याग वही सार्थक है, जो परार्थ के लिए हो। स्वार्थ के लिए त्याग तो पशु-पक्षी भी करते हैं। इसीलिए निःस्वार्थ भाव से लोकहित में त्याग करने वाले मानव संत बन जाते हैं। श्रीमद्भगवद्गीता में त्याग को शांति का प्रदाता कहा गया है, परंतु इसके विलक्षण आनंद का अनुभव कोई विरला ही कर सकता है। वस्तुतः त्याग का जन्म उदारता से होता है, क्योंकि औदार्य भाव ही मनुष्य को स्वार्थ और मोह से मुक्तकर परार्थ के लिए प्रेरित करता है। इसलिए उदारता का भाव जिसमें जितना प्रबल होगा, त्याग की भावना भी उतनी ही प्रबल होगी। कल्पना कीजिए कि महर्षि दधीचि में उदारता का भाव कितना प्रबल रहा होगा, जिससे उन्होंने जीवित रहते ही लोक कल्याणार्थ शरीर त्याग करने का निर्णय लिया। कर्ण ने यह जानते हुए भी कि जीवन रक्षक कवच का दान करने से उसके प्राणों पर संकट निश्चित है, उसे सहर्ष काटकर याचक को समर्पित कर दिया। उदारता के बिना यह कदापि संभव नहीं था।

लक्ष्मी जी कहां निवास करतीं हैं

संकलित
प्रेरणा

एक बार की बात है, राजा बलि समय बिताने के लिए एकान्त स्थान पर गधे के रूप में छिपे हुए थे। देवराज इन्द्र उनसे मिलने के लिए उन्हें ढूंढ रहे थे। एक दिन इन्द्र ने उन्हें खोज निकाला और उनके छिपने का कारण जानकर उन्हें काल का महत्व बताया। साथ ही उन्हें तत्वज्ञान का बोध कराया। तभी राजा बलि के शरीर से एक दिव्य रूपात्मा स्त्री निकली। उसे देखकर इन्द्र ने पूछा- दैत्यराज! यह स्त्री कौन है? देवी, मानुषी अथवा आसुरी शक्ति में से कौन-सी शक्ति है? राजा बलि बोले- देवराज! ये देवी तीनों शक्तियों में से कोई नहीं हैं। आप स्वयं पूछ लें। इन्द्र के पूछने पर वे शक्ति बोलीं- देवेन्द्र! मुझे न तो दैत्यराज बलि जानते हैं और न ही तुम या कोई अन्य देवगण। पृथ्वी लोक पर लोग मुझे अनेक नामों से पुकारते हैं। जैसे- श्री, लक्ष्मी आदि। इन्द्र बोले- देवी! आप इतने समय से राजा बलि के पास हैं लेकिन ऐसा क्या कारण है कि आप इन्हें छोड़कर मेरी ओर आ रही हैं? लक्ष्मी जी बोलीं- देवेन्द्र! मुझे मेरे स्थान से कोई भी हटा या डिगा नहीं सकता है। मैं सभी के पास काल के अनुसार आती-जाती रहती हूं। जैसा काल का प्रभाव होता है मैं उतने ही समय तक उसके पास रहती हूं। अर्थात मैं समयानुसार एक को छोड़कर दूसरे के पास निवास करती हूं। इन्द्र बोले- देवी! आप असुरों के यहां निवास क्यों नहीं करतीं? लक्ष्मी जी बोलीं- देवेन्द्र! मेरा निवास वहीं होता है जहां सत्य हो, धर्म के अनुसार कार्य होते हों, व्रत और दान देने के कार्य होते हों। लेकिन असुर भ्रष्ट हो रहे हैं।

अंतर्मन

आज की पाती

शिक्षण संस्थानों में फूहड़ मनोरंजन

विद्यालय किसी भी राष्ट्र की आत्मा का निर्माण करते हैं। यही वे स्थान हैं जहां से समाज की दिशा तय होती है और आने वाली पीढ़ियों के विचार, मूल्य तथा व्यवहार गढ़े जाते हैं। एक सभ्य समाज की पहचान उसके विद्यालयों से होती है, क्योंकि यहीं बच्चों को केवल अक्षर ज्ञान ही नहीं, बल्कि अनुशासन, नैतिकता, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का बोध कराया जाता है। ऐसे में यदि विद्यालय परिसरों में अशोभनीय गीतों पर नृत्य, फूहड़ मनोरंजन और मर्यादाविहीन प्रस्तुतियां सामने आती हैं, तो यह केवल किसी एक संस्था की चूक नहीं, बल्कि पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए गंभीर चेतावनी है। हाल के वर्षों में देश के विभिन्न हिस्सों से ऐसे दृश्य सामने आए हैं जहां विद्यालयों में फूहड़ मनोरंजन के किस्से सामने आए।

– विवेक चौबे, रायपुर

ट्रेंड

नए युग का साक्षी

आज उत्तर प्रदेश समेत पूरा देश वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के नए युग का साक्षी बन रहा है। मेरठ मेट्रो, नमो भारत ट्रेन और रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के नए सेक्शन के शुभारंभ से एनसीआर के लोगों का जीवन और अधिक सरल, सुगम एवं सुविधाजनक बनेगा। -नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

अवैध प्रवासियों को बाहर करेंगे

अगर देश नक्सलवाद से मुक्त हो सकता है, तो घुसपैठियों से भी मुक्त हो सकता है। अवैध प्रवासियों को न केवल मतदाता सूची से हटाया जाएगा, बल्कि अगले पांच वर्षों में देश से भी बाहर किया जाएगा। नक्सलवाद को भी 31 मार्च तक पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। इससे देश लाल आतंक से मुक्त होगा। -अमित शाह, गृहमंत्री

जिम्मेदारी से बोलते हैं राहुल

राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। वे जिम्मेदारी से बोलते हैं, कैजुअली नहीं। वे तथ्यों के आधार पर बोलते हैं और जो भी कहते हैं, उसके सबूत देते हैं। सरकार नहीं चाहती थी कि सदन में चर्चा हो। महिला सांसदों पर आरोप लगाए गए। इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। -जयराम रमेश, कांग्रेस सांसद

ममता की नीति सफल नहीं होगी

शायद ममता बजर्नी को लग रहा है इस बार चुनाव में गैर-बंगाली लोग उनकी पार्टी टीएमसी को वोट नहीं देंगे। इसीलिए वह प्रवासी बांग्लादेशी मजदूरों पर हमले का मुद्दा भुनाना चाहती है। लेकिन ममता की यह नीति सफल नहीं होगी। -अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस नेता

करंट अफेयर

वेनेजुएला की आम माफी योजना में रिहा होंगे कैदी

वेनेजुएला में राजनीतिक कारणों से हिरासत में लिए गए कम से कम 1,557 लोगों ने इस सप्ताह पारित हुए माफी विधेयक के तहत अपने आवेदन जमा कर दिए हैं और उनके रिहा होने की उम्मीद है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। बृहस्पतिवार को पारित किए गए इस कदम से विपक्षी सदस्यों, कार्यकर्ताओं, मानवाधिकार रक्षकों, पत्रकारों और महीनों या वर्षों से हिरासत में रखे गए कई अन्य लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इस विधेयक पर हस्ताक्षर के साथ ही राष्ट्रपति ने एक तरह से यह स्वीकार किया कि सरकार ने सैकड़ों लोगों को राजनीतिक कारणों से जेल में रखा हुआ है। राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के इस कदम को बड़े बदलाव के संकेत के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि इससे पहले दक्षिण अमेरिकी देश के अधिकारी दशकों से किसी राजनीतिक कैदी को हिरासत में रखे जाने की बात से इनकार करते रहे हैं। यह पिछले महीने देश की राजधानी काराकस में तत्कालीन राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के लिए अमेरिकी सेना की कार्रवाई के बाद नीति में आया नवीनतम बदलाव है। 'नेशनल असेंबली' के नेता जॉर्ज रोड्रिगेज ने शनिवार को कहा, 'आज तक 1,152 नए आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिससे कुल आवेदनों की संख्या 1,557 हो गई है जिन पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है।

ऑफ बीट

जाने कुछ ब्लैक होल दूसरों से बड़े क्यों?

ब्लैक होल घने खगोलीय पिंड होते हैं, जिनका गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि कुछ भी खुद में समेट लेते हैं, यहां तक कि प्रकाश भी, इससे बच नहीं सकता है। जो कुछ भी ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव की सीमा को पार करेगा, वह ब्लैक होल में गिर जाएगा। इस गहरे, घने गड्ढे के अंदर, इसे फिर कभी नहीं देखा जा सकेगा। ब्लैक होल ब्रह्मांड में यहां-वहां फैले रहते हैं। हमारी आकाशगंगा जैसी आकाशगंगाओं में कुछ छोटे ब्लैक होल बेतरतीब ढंग से बिखरे हुए हैं। अन्य विशाल ब्लैक होल, जिन्हें 'सुपरमैसिव' ब्लैक होल कहा जाता है, आकाशगंगाओं के केंद्र में स्थित हैं। इनका वजन हमारे सूर्य के द्रव्यमान से दस लाख से एक अरब गुना तक हो सकता है। तो आप सोच रहे होंगे: खगोलशास्त्री संभवतः इतनी अंधेरी और इतनी बड़ी चीज़ कैसे देख सकते हैं? मैं एक खगोलशास्त्री हूं जो हमारे ब्रह्मांड में बने पहले सुपरमैसिव ब्लैक होल का अध्ययन करता है। मैं यह समझना चाहता हूं कि ब्लैक होल कैसे बनते हैं और वे किस प्रकार के खगोलीय माहौल में विकसित होते हैं। दो प्रसिद्ध वैज्ञानिकों, अल्बर्ट आइंस्टीन और कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड ने सबसे पहले ब्लैक होल का विचार प्रस्तुत किया था।

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय
टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से hbcgpati@gmail.com पर भेज सकते हैं।

बोरा बोले: कांग्रेस ने असमिया समुदाय की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाई है

भाजपा परिवार बोरा का ख्याल रखेगा और उन्हें प्यार एवं सम्मान देगा: सरमा

भूपेन कुमार बोरा भाजपा में शामिल, असम कांग्रेस को लगा बड़ा झटका

हरिभूमि ब्यूरो ⏭ नई दिल्ली

कांग्रेस की असम इकाई के पूर्व अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा रविवार को गुवाहाटी में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया की उपस्थिति में सत्तारूढ़ पार्टी में शामिल हो गए। भाजपा की असम इकाई के मुख्यालय 'वाजपेयी भवन' में आयोजित एक समारोह के दौरान बोरा भाजपा के सदस्य बन गए। बोरा ने भाजपा में शामिल होने के बाद कहा, मैंने कांग्रेस से यह सोचकर इस्तीफा नहीं दिया था कि मैं भाजपा में शामिल हो जाऊंगा। मैंने यह सोचकर इस्तीफा दिया था कि कांग्रेस में हुई गलतियों के बारे में आत्मनिरीक्षण किया जाएगा और मुझे यह उम्मीद थी कि उन्हें सुधारने का वादा किया जाएगा।बोरा साथ ही पूर्व कांग्रेस नेता संजू बोरा, राजेश कुमार जोशी, कंगन दास, गगन चंद्र बोरा और विपक्षी दल के कई अन्य कार्यकर्ता भी भाजपा में शामिल हो गए। इसके कुछ ही घंटों बाद, भाजपा ने बोरा को प्रदेश कार्यकारी समिति में शामिल किया। बोरा ने 16 फरवरी को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था, जिसे पार्टी आलाकमान ने स्वीकार नहीं किया था। राहुल गांधी ने भी उनसे बात की थी। बोरा ने अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए समय मांगा था, लेकिन अगले दिन मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा उनके आवास पर गए और घोषणा की थी कि वह 22 फरवरी को भाजपा में शामिल हो जाएंगे। बोरा ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व ने उनकी 'भावनाओं को ठेस पहुंचाई' है। उन्होंने आरोप लगाया, कांग्रेस ने असमिया समुदाय की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाई है। मैंने विचारधारा, अंतरात्मा और देशभक्ति के साथ 32 वर्षों तक कांग्रेस की सेवा की; लेकिन अब मुझे दुख हुआ है। इससे पहले, भूपेन कुमार बोरा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की फोटो एक्स में शेयर की थी। भाजपा में बोरा का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि बोरा के भीतर 'कुछ कड़वाहट' हो सकती है, क्योंकि उन्होंने 32 से अधिक वर्षों तक कांग्रेस की सेवा करने और बहुत योगदान देने के बाद पार्टी छोड़ दी। उन्होंने कहा, आज से भाजपा में उनका नया जीवन शुरू होता है। अब वह पार्टी के गौरवान्वित सदस्य हैं। भाजपा परिवार उनका ख्याल रखेगा और उन्हें प्यार एवं सम्मान देगा। असम भाजपा अध्यक्ष सैकिया ने भी बोरा और सत्तारूढ़ पार्टी में शामिल होने वाले अन्य कांग्रेस नेताओं का स्वागत किया।

इधर, मणिशंकर ने राहुल को फिर घेरा

ममता दी के बिना आईएनडीआईए गठबंधन खत्म हो जाएगा, बेनर्जी को बनाएं 'नेता'

एजेंसी ⏭ कोलकाता

यहां कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने इंडिया ब्लॉक को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर ममता बेनर्जी नहीं रहीं तो इंडिया गठबंधन का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। अय्यर ने ममता को गठबंधन का नेता बताते हुए कहा कि उनके साथ कुछ अन्य क्षेत्रीय नेता भी इस भूमिका को निभाने की क्षमता रखते हैं।

छोटे दलों के नेताओं को आगे लाएं

उन्होंने सुझाव दिया कि राहुल गांधी को इस पद पर बने रहने की कोशिश करने के बजाय क्षेत्रीय दलों के नेताओं को आगे आने देना चाहिए। उन्होंने कहा कि चाहे एमके स्टालिन हों, ममता बेनर्जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव या कोई अन्य नेता, छोटे दलों से आने वाले ये नेता गठबंधन का नेतृत्व संभाल सकते हैं।अय्यर का यह बयान विपक्षी गठबंधन की नेतृत्व भूमिका को लेकर नई राजनीतिक चर्चा को जन्म दे सकता है।

राहुल को पद छोड़ देना चाहिए

मणिशंकर ने कहा कि ममता दी के बिना आईएनडीआईए गठबंधन खत्म हो जाएगा, क्योंकि ममता ही इस गठबंधन की नेता हैं। उनके साथ दो-चार अन्य नेता भी हैं जो इस पद को हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि राहुल को इस पद पर बने रहने की कोशिश करने के बजाय जो छोटे दलों के नेताओं का स्थान है ।

खबर संक्षेप

पूर्व विधायक बिस्वास वापस टीएमसी में गए

कोलकाता। बंगाल के बशीरहाट दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक दीपेंदु बिस्वास ने रविवार को टीएमसी में फिर से वापसी कर ली। उनके साथ जिले के कई नेताओं ने भी सत्तारूढ़ दल का दामन थामा है। इनमें कांग्रेस अध्यक्ष कादेर सरदार और बशीरहाट नगरपालिका के पूर्व उपाध्यक्ष पार्थसारथी बसु भी शामिल हैं।

रोटियों पर थूक, पुलिस ने होटल करवाया बंद

अलीगढ़। यहां रोटी पर थूक लगाकर बनाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह मामला रोरावर क्षेत्र के तेलीपाड़ा इलाके का बताया जा रहा है। करीब छह-छह सेकंड के दो वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर हो रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी कारीगर को गिरफ्तार कर लिया है।

धूल भरी आंधी से इंडिगो फ्लाइट इंफाल डायवर्ट

डिब्रूगढ़। असम के डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे पर रविवार को तेज धूल भरी आंधी के चलते अहमदाबाद से आ रही इंडिगो की फ्लाइट को इंफाल डायवर्ट करना पड़ा। विमान में 144 यात्री सवार थे। आंधी से दृश्यता बेहद कम हो गई थी। चालक दल ने तुरंत फ्लाइट 6ई-6457 का रास्ता बदलकर उसे डिब्रूगढ़ के सबसे पास इंफाल ले गया।

60 दिन तक 'डिजिटल अरेस्ट', 3 करोड़ ठगे

देहरादून। साइबर ठगों ने 60 दिन तक 'डिजिटल अरेस्ट' करके 70 साल की महिला से 3 करोड़ की ठगी कर ली। जालसाजों ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताया। इसके बाद पीड़ित महिला को वीडियो कॉल पर घंटों धमकाया। गिरफ्तारी कहकर करोड़ों ट्रांसफर करवा लिए।

'मन की बात' में पीएम ने कई मुद्दों को सामने रखा

डिजिटल लेन-देन, बैंकिंग सेवाओं के साथ साइबर सुरक्षा के प्रति लोगों को सचेत किया

एजेंसी ⏭ नई दिल्ली

पीएम ने मन की बात के 131वें एपिसोड में देशवासियों से सीधे संवाद किया। डिजिटल दुनिया में सुरक्षा और जागरूकता की अहमियत को रेखांकित किया। डिजिटल फ्रॉड और अरेस्ट की घटनाएं बनी हुई हैं। लोग फोन के माध्यम से धोखाधड़ी का शिकार हो रहे हैं

पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 131वें एपिसोड में देशवासियों से सीधे संवाद किया।कार्यक्रम के जरिए सामाजिक, आर्थिक और डिजिटल मुद्दों पर नागरिकों को जागरूक किया। डिजिटल लेन-देन, बैंकिंग सेवाओं और साइबर सुरक्षा जैसे विषयों पर चर्चा के माध्यम से पीएम लोगों को सजग रहने और सुरक्षित वित्तीय व्यवहार अपनाने की दिशा में सचेत रहने को कहा। इसमें डिजिटल दुनिया में सुरक्षा और जागरूकता की अहमियत को रेखांकित किया गया।

131वें एपिसोड में किया देशवासियों से संवाद

केवाईसी आपकी सुरक्षा करेगी

साइबर सुरक्षा पर बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि डिजिटल फ्रॉड और अरेस्ट की घटनाएं समाज में बनी हुई हैं। लोग कभी-कभी फोन या मैसेज के माध्यम से धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। व्यवसायियों से भी ठगी होती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि केवाईसी सिर्फ बैंकिंग प्रक्रिया नहीं, बल्कि आपकी सुरक्षा का तरीका है।नागरिकों को सलाह दी कि वे केवल बैंक के अधिकारिक माध्यमों जैसे बैंक एप, शाखा या वेबसाइट से ही केवाईसी कराएं। पासवर्ड नियमित बदलें और निजी जानकारी केवल अधिकृत अधिकारियों को दें।

त्योहारों पर वोकल फॉर लोकल की अपील

प्रधानमंत्री ने आने वाले त्योहारों को लेकर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं और वोकल फॉर लोकल का मंत्र याद रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि होली समेत कई त्योहारों में विदेशी सामान की भरमार हो गई है। ऐसे उत्पादों को त्योहारों से दूर रखकर स्वदेशी अपनाना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि जब लोग स्वदेशी खरीदते हैं, तो वे देश को आत्मनिर्भर बनाने के अभियान को भी मजबूत करते हैं।

परीक्षा को लेकर घबराएं नहीं

प्रधानमंत्री ने छात्रों के लिए कहा कि परीक्षा के समय मन में शंका आना स्वाभाविक है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि हर पीढ़ी ने यह अनुभव किया है और छात्र अकेले नहीं हैं। पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि किसी का मूल्य उसकी मार्कशीट से तय नहीं होता। उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की कि जो पढ़ा है, उसे आत्मविश्वास के साथ लिखें और एक कठिन सवाल को मन पर हावी न होने दें।

अम्मा जयललिता जनसेवा की प्रतीक थीं, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि

प्रधानमंत्री ने कहा कि जो नेता समाज के कल्याण के लिए काम करते हैं, वे हमेशा जनता के दिलों में बसे रहते हैं। उन्होंने अम्मा जयललिता को ऐसी ही लोकप्रिय नेता बताया। पीएम मोदी ने कहा कि उनके नाम से ही तमिलनाडु के लोगों के चेहरे खिल उठते हैं। उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई सराहनीय कदम उठाए। प्रधानमंत्री ने उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की।

एआई समिट में जीता दुनिया का दिल

पीएम मोदी ने कहा कि नई दिल्ली में एआई समिट में दो भारतीय उत्पादों ने विश्व नेताओं को खास तौर पर प्रभावित किया। पहला उत्पाद अमूल के बूथ पर प्रदर्शित किया गया, जहां बताया गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से पशुओं के इलाज को बेहतर बनाया जा रहा है। एआई के जरिए किसान 24 घंटे अपनी डेयरी और पशुओं का रिकॉर्ड रख सकते हैं। दूसरा उत्पाद भारत की संस्कृति से जुड़ा था। इसमें दिखाया गया कि एआई तकनीक के माध्यम से प्राचीन ग्रंथों, पांडुलिपियों और पारंपरिक ज्ञान को सुरक्षित रखा जा रहा है। इस पहल को देखकर कई देशों के प्रतिनिधि आश्चर्यचकित रह गए और भारत की तकनीकी व सांस्कृतिक पहल की सराहना की।

केरल की 10 माह की अंगदाता शेरिन को किया याद

प्रधानमंत्री ने केरल की 10 महीने की अंगदाता एलिन शेरिन अब्राहम की कहानी भी साझा की। हाल ही एक सड़क दुर्घटना में एलिन और उसके माता-पिता गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उसे कोच्चि के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां 13 फरवरी को डॉक्टरों ने बच्ची को ब्रेन डेड घोषित कर दिया था। बाद में परिवार ने बच्ची के अंगदान का फैसला किया। बच्ची का लिवर, दोनों किडनी, हार्ट वाल्व और आंखें दान की गई हैं। इससे 5 मरीजों को नया जीवन मिलेगा।

राष्ट्रपति भवन में लगेगी राजगोपालाचारी की प्रतिमा

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश गुलामी के प्रतीकों को पीछे छोड़कर भारत की संस्कृति से जुड़ी चीजों को महत्व देने लगा है। इस दिशा में हमारे राष्ट्रपति भवन ने भी एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने बताया कि 23 फरवरी को राष्ट्रपति भवन में 'राजाजी उत्सव' मनाया जाएगा। राष्ट्रपति भवन में राजगोपालाचारी की प्रतिमा लगेगी।

पित्रोदा के बयान पर भड़की भाजपा

'लश्कर-ए-कांग्रेस' के सैम ने झूठ बोल देश का मजाक उड़ाया

पूनावाला ने कहा- देश को बदनाम कर रहे

एजेंसी ⏭ नई दिल्ली

वरिष्ठ कांग्रेस नेता की टिप्पणी पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि 'लश्कर ए कांग्रेस' के मुख्य सलाहकार ने एक बार फिर से झूठ बोलकर भारत का मजाक उड़ाने की कोशिश की है। एआई समिट में कांग्रेस के टॉपलेस ऐक्ट के बाद लश्कर-ए-कांग्रेस के मुख्य सलाहकार सैम पित्रोदा मैदान में हैं। एक एक बार फिर भारत को बदनाम करने के एजेंडे पर चले हैं। सैम झूठ बोलकर भारत का मजाक उड़ाते हैं। कहते हैं कि भारत पर शर्म आती है कि उसने मोबाइल के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम तक विकसित नहीं किया है। उन्होंने पित्रोदा की टिप्पणियों का खंडन करते हुए भारत में विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का एकमात्र मिशन झूठ बोलकर भारत को बदनाम करना है।

ये बोले पित्रोदा

दूसरों की सेवा के लिए हैं भारतीय

भारतीय प्रवासी कांग्रेस के प्रमुखपित्रोदा ने एक बार फिर से एक बयान के जरिए पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। सैम ने दावा किया कि भारत ने दूसरों की सेवा के लिए युवाओं की बड़ी फौज को खड़ा किया है।यह दिशियों के लिए काम करती है। सैम ने टेक्नोलॉजी निर्माण की स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक 1.5 अरब आबादी वाले देश के लिए यह शर्म की बात है कि उनके पास अपना ऑपरेटिंग सिस्टम तक नहीं है। इसी टिप्पणी पर भाजपा ने हमला बोला।

खोजों का लाभ उठाने में दिल्ली असमर्थ

एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में सैम ने विदेशी कंपनियों में भारतीयों की संख्या जिक्र करते हुए अपनी बात को रखा। उन्होंने कहा कि भारत ने अपनी शिक्षा संस्थाओं के जरिए युवा प्रतिभा का एक बड़ा आधार तैयार किया है, लेकिन भारत में ही नई खोजों के लिए इसका लाभ उठाने में नई दिल्ली पूरी तरह से असमर्थ रही है। उन्होंने कहा कि हमने बहुत सारी युवा प्रतिभा का निर्माण किया है, लेकिन यह अपरिपक्व है। इस प्रतिभा ने भारत का नहीं बल्कि दुनिया की तमाम बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोग्रामिंग, कानून, उद्योग, लॉजिस्टिक्स, इनोवेशन, बैंकिंग में मदद की है। इस प्रतिभा के दम पर भारत ने वैश्विक स्तर के प्रोडक्ट्स नहीं बनाए, बल्कि इस प्रतिभा का इस्तेमाल दूसरे की सेवा के लिए किया।

सीबीएसई फिजिक्स परीक्षा पर उठा विवाद

शिक्षक ने बोर्ड के खिलाफ जनहित याचिका दायर की

परीक्षा के अलग- अलग प्रश्नपत्रों की कठिनाई का स्तर समान नहीं रखा गया

एजेंसी ⏭ दनई दिल्ली

देशभर में बोर्ड परीक्षाओं के बीच एक नया विवाद खड़ा हो गया है जिसने लाखों विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है। शिक्षक प्रशांत किराड ने सीबीएसई के खिलाफ जनहित याचिका दायर की है। आरोप है कि परीक्षा के अलग अलग प्रश्नपत्रों की कठिनाई का स्तर समान नहीं रखा गया, जिससे छात्रों के साथ न्याय नहीं हुआ और उनके अंक उनकी मेहनत से ज्यादा किस्मत पर निर्भर हो गए। शिक्षक का कहना है कि कुछ विद्यार्थियों को

अपेक्षाकृत आसान प्रश्नपत्र मिले, जबकि अन्य को ऐसे प्रश्न हल करने पड़े जिनका स्तर प्रतियोगी परीक्षाओं जैसा बताया जा रहा है। इससे छात्रों में असमानता की भावना पैदा हुई है और पूरे परीक्षा तंत्र पर सवाल उठने लगे हैं।

क्या है पूरा मामला

दायर की गई जनहित याचिका में कहा गया है कि वर्षों से बोर्ड अलग अलग प्रश्नपत्र तैयार करता रहा है ताकि नकल जैसी समस्याओं पर रोक लगाई जा सके। लेकिन इस बार प्रश्नपत्रों के बीच कठिनाई का अंतर असामान्य रूप से ज्यादा बताया जा रहा है। आरोप है कि कुछ प्रश्नपत्र सीधे और कोर्स आधारित थे, जबकि अन्य में अवधारणात्मक और गहराई वाले प्रश्न अधिक थे, जिनके लिए अतिरिक्त तैयारी की जरूरत पड़ी।

हरियाणा महिला कांग्रेस को नया अध्यक्ष, गोवा पुडुचेरी और ओडिशा में भी नई जिम्मेदारियां

नई नियुक्तियों की जानकारी एआईसीसी के महासचिव वेणुगोपाल ने दी

हरिभूमि ब्यूरो ⏭ नई दिल्ली

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) ने संगठनात्मक स्तर पर अहम बदलाव करते हुए कई नई नियुक्तियों और जिम्मेदारियों की घोषणा की है। यह निर्णय कांग्रेस अध्यक्ष की मंजूरी के बाद तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। नई नियुक्तियों की जानकारी एआईसीसी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दी।

हरियाणा महिला कांग्रेस को नई कमान

उन्होंने बताया कि पर्ल चौधरी को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महिला कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। पार्टी ने उम्मीद जताई है कि उनके नेतृत्व में हरियाणा में महिला संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी।

गोवा और पुडुचेरी में अतिरिक्त जिम्मेदारी

संगठनात्मक बदलाव के तहत डॉ. अंजली निंबालकर, जो वर्तमान में एआईसीसी सचिव के रूप में गोवा प्रभारी के साथ संबद्ध हैं, उन्हें पुडुचेरी विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र पुडुचेरी के प्रभारी के साथ अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह नियुक्ति भी तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

ओडिशा में नई तैनाती

इसी क्रम में मयूरा जयकुमार को उनकी वर्तमान जिम्मेदारी (कर्नाटक के प्रभारी महासचिव के साथ संबद्ध एआईसीसी सचिव) से मुक्त करते हुए ओडिशा के प्रभारी के साथ एआईसीसी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। कांग्रेस नेतृत्व का कहना है कि आगामी चुनावों और संगठनात्मक मजबूती को ध्यान में रखते हुए यह फेरबदल किया गया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, इन नियुक्तियों से राज्यों में संगठन को अधिक प्रभावी और सक्रिय बनाने में मदद मिलेगी।

नौ राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की सूची जारी

चुनाव आयोग ने जारी किए आंकड़े

देशभर में घटे 1.70 करोड़ मतदाता यहां संख्या 9.75 करोड़ ही रह गई

एजेंसी ⏭ नई दिल्ली

भारत के छह राज्यों और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का काम पूरा हो गया है। चुनाव आयोग द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार इस प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में ऐसे मतदाताओं के नाम हटाए गए, जिन्हें अयोग्य पाया गया। 9 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाताओं की संख्या मिलाकर 1 करोड़ 70 लाख से ज्यादा घट गई है। आयोग ने स्पष्ट किया कि यह हटाए गए मतदाताओं और नए जोड़े गए योग्य मतदाताओं

के अंतर के आधार पर नेट बदलाव है। गुजरात, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, राजस्थान, छत्तीसगढ़, अंडमान-निकोबार द्वीप, गोवा और केरल समेत 9 राज्यों-केंद्रशासित प्रदेशों में एसआईआर शुरू होने से पहले मतदाताओं की संख्या लगभग 21.45 करोड़ थी।

बंगाल में न्यायिक जांच आज से होगी शुरू

कोलकाता। बंगाल में चल रहे विशेष गहन निरीक्षण (एसआईआर) के तहत मतदाता सूची में दावों और आपत्तियों की पूर्ण न्यायिक जांच सोमवार से शुरू हो जाएगी। कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त 150 सेशन जज, 250 न्यायिक अधिकारी इस व्यवस्था में लगाए गए हैं। प्रत्येक जिले में हाई कोर्ट द्वारा गठित तीन सदस्यीय समिति इस प्रक्रिया की निगरानी करेगी। समिति में जिला जज, जिला मजिस्ट्रेट होंगे।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने किया एक्स पर पोस्ट

यह डील नहीं, दबाव है, संसद संचालन को लेकर भी सरकार पर निशाना

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर केंद्र पर बोला हमला

हरिभूमि ब्यूरो ⏭ नई दिल्ली

कांग्रेस महासचिव और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 'संतुलित समझौता' का अर्थ लेन-देन यानी गिव एंड टेक होता है, लेकिन इस समझौते में भारत की ओर से 'ज्यादा दिया गया और कम लिया गया' है, इसलिए इसे डील नहीं बल्कि 'दबाव' कहा जाना चाहिए।

उन्होंने कहा 'डील का मतलब संतुलन होता है। अगर आप केवल देते जाएं और बदले में बहुत कम प्राप्त करें, तो उसे समझौता कैसे कहा जा सकता है? यह एकतरफा व्यवस्था है।'

किसानों की चिंताओं का जिक्र

रमेश ने दावा किया कि किसान संगठनों और किसानों में इस समझौते को लेकर चिंता है। उनके अनुसार, आयात शुल्क में कमी और आयात के उदारीकरण का असर आने वाले महीनों में दिखाई देगा। उन्होंने कहा, 'आयात अभी होगा, लेकिन निर्यात का लाभ 20 साल बाद मिलेगा—इसका क्या अर्थ है?'

उन्होंने अमेरिकी टैरिफ नीति का जिक्र करते हुए कहा कि जब अमेरिका अपने टैरिफ बदल सकता है, तो भारत को भी अपने हितों की रक्षा करनी चाहिए। 'समझौता बराबरी के आधार पर होना चाहिए, एकतरफा नहीं,'उन्होंने कहा।

हम तथ्यों के आधार पर बोल रहे हैं

कांग्रेस नेता ने कहा कि वे और पार्टी नेतृत्व तथ्यों के आधार पर बात कर रहे हैं, कोई आरोप नहीं लगा रहे। हम तथ्य रख रहे हैं। किसानों की चिंता वास्तविक है और सरकार को इसका जवाब देना चाहिए, उन्होंने कहा।

संसद संचालन सरकार की जिम्मेदारी

संसद के कामकाज को लेकर भी जयराम रमेश ने सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि संसद चलाने की प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार की होती है। 'कई सांसद नेता प्रतिपक्ष और पूर्व प्रधानमंत्रियों के खिलाफ आधारहीन और आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती',उन्होंने आरोप लगाया। कांग्रेस ने मांग की है कि सरकार व्यापार समझौते के सभी बिंदुओं को सार्वजनिक करे और संसद में विस्तृत चर्चा कराए, ताकि किसानों और उद्योग जगत की आशंकाओं का समाधान हो सके।

Be part of Community and Get Early Access to All.

✅ I Give My Earliest Newspapers updates from 5 AM in Private channel with All Editions

♦ Indian Newspaper

1) Times of India
2) The Hindu
3) Business line
4) The Indian Express
5) Economic Times
6) Financial Express
7) Live Mint
8) Hindustan Times
9) Business Standard

♦ International Newspapers channel

[Europian, American, Gulf & Asia]

♦ Magazine Channel

National & International
[Genaral & Exam related]

♦ English Editorials

[National + International Editorials]

संपादकीय जागरण

सोमवार, 23 फरवरी, 2026: फाल्गुन शुक्ल - 6 वि. 2082

अनियंत्रित इच्छा विवेक को ढक देती है

आतंकी गठजोड़

दिल्ली पुलिस की ओर से तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किए गए आठ संदिग्ध आतंकवादियों के बारे में जिस तरह यह जानकारी सामने आई कि वे देश की राजधानी में किसी बड़े हमले की साजिश रच रहे थे, उससे यही पता चलता है कि आतंकी संगठनों का दुस्साहस कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तमिलनाडु और बंगाल से जो आतंकी गिरफ्तार किए गए, उनमें से अधिकांश बांग्लादेशी हैं, लेकिन वे पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्करे तैयबा के इशारे पर काम कर रहे थे। उनका हैंडलर बांग्लादेश में बैठा एक कुख्यात कश्मीरी आतंकी बताया जा रहा है। इसका मतलब है कि बांग्लादेशी और पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के बीच साठगांठ कायम हो गई है। यह एक नया खतरा है और इससे भारत की चिंता बढ़ जाना स्वाभाविक है। यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के आतंकी तत्वों के बीच साठगांठ पिछले लगभग डेढ़ वर्ष में तब हुई, जब मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का संचालन कर रहे थे। यह किसी से छिपा नहीं कि इस दौरान उन्होंने न केवल अपने देश के भारत विरोधी कट्टरपंथी तत्वों को उकसाने का काम किया, बल्कि पाकिस्तान से संबंध बढ़ाने में भी जुटे रहे। हैरानी नहीं कि इस सबके चलते पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के सरगना बांग्लादेश पहुंचे हों। जो भी हो, भारत की सुरक्षा एजेंसियों को सतर्कता बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि कश्मीर के बहाने आतंकी तत्वों को बहकाने और उकसाने का काम जारी है।

दिल्ली पुलिस की ओर से पकड़े गए आतंकियों के दुस्साहस का पता इससे चलता है कि उन्होंने दिल्ली और कोलकाता में भारत विरोधी पोस्टर चस्पा किए थे। इन पोस्टरों की छानबीन के तहत ही दिल्ली पुलिस संदिग्ध आतंकियों तक पहुंची। ध्यान रहे कि कुछ महीने पहले दिल्ली में लालकिले के निकट धमाका करने वाले आतंकी के साथियों ने भी इसी तरह श्रीनगर में भारत के खिलाफ पोस्टर लगाए थे। श्रीनगर में लगाए गए पोस्टरों की छानबीन से ही फरीदाबाद के उस आतंकी माड्यूल का भंडाफोड़ हुआ था, जिसमें कई डाक्टर शामिल थे और जिनमें से एक ने आत्मघाती हमलावर बनकर लालकिले के निकट कार में विस्फोट किया था। ये दोनों घटनाएं यही बताती हैं कि पुलिस एवं सुरक्षा एजेंसियों को प्रत्येक छोटी से छोटी घटना को गंभीरता से लेना चाहिए और उनकी गहन जांच भी करनी चाहिए। दिल्ली पुलिस के हाथ आए संदिग्ध आतंकियों के पास से फर्जी आधार कार्ड बरामद हुए हैं और वे उन्हीं के जरिये तमिलनाडु एवं कोलकाता में काम कर रहे थे। इसका अर्थ है कि लोगों को इसके लिए आगाह किया जाए कि वे किसी को काम पर रखने के पहले उनके पहचान पत्रों की जांच सावधानी से करें।

सतर्कता जरूरी

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा लश्कर-ए-तैयबा के अंतरराज्यीय माड्यूल का भंडाफोड़ करना सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी को दर्शाता है, लेकिन पूरे प्रकरण में सबसे चिंताजनक पहलू लश्कर-ए-तैयबा का बदलता स्वरूप है। बांग्लादेश में बैठकर पाकिस्तानी आतंकी जिस तरह से हमारे देश में इस माड्यूल को संचालित कर रहा था, वह क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती है। दिल्ली जैसे महानगर के मेट्रो स्टेशनों के बाहर देश-विरोधी पोस्टर लगाना महज एक शरारत नहीं, बल्कि गहरी मनोवैज्ञानिक साजिश का हिस्सा था। बेशक पुलिस की भाषा में इसके 'ड्राई रन' कहा जा रहा है, लेकिन जिसका उद्देश्य सुरक्षा व्यवस्था की सतर्कता को मापना और समाज में भय का माहौल पैदा करना था।

भले ही आठ आतंकी पकड़ लिए गए हों, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों और आम जनता को अधिक सतर्क रहना होगा

गिरफ्तार आतंकियों के पास से भीड़भाड़ वाले स्थानों की रेकी के वीडियो मिलना इस बात का संकेत है कि वे बड़ी त्रासदी को अंजाम देने के बेहद करीब थे। यदि समय रहते यह कार्रवाई न होती, तो देश को एक और गहरा जख्म मिल सकता था। अब विचारणीय पहलू यह भी है कि यह समय आत्ममुग्ध होने का नहीं, बल्कि और अधिक सतर्क होने का है। पकड़े गए आतंकियों से पूछताछ में कई और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है, जो इस नेटवर्क के अन्य मोहरों तक पहुंचने में मदद करेंगे। सुरक्षा एजेंसियों के साथ आम नागरिक को भी अलर्ट रहना होगा।

कह के रहेंगे — माधव जोशी

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रंप के टैरिफ को अवैध घोषित करने से उन्हें मध्यावधि चुनाव में नुकसान होगा?

आज का सवाल
क्या समय-समय पर आतंकियों की धरपकड़ यही संकेत करती है कि उनके लिए स्थानीय सहायता जारी है?

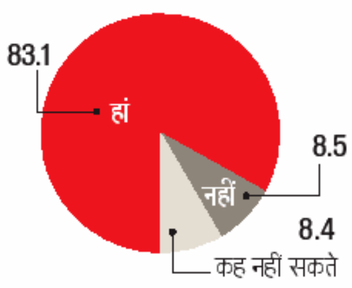

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

ट्रंप के लिए आपदा और दूसरों को अवसर

डा. मनिष दभाडे

चूंकि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप टैरिफ को अवैध करार दिया है, इसलिए उनकी आड़ में जिन देशों पर दबाव बनाया जा रहा था, वे अब कड़ी सौदेबाजी कर सकते हैं

टैरिफ को अपना नीतिगत हथियार मानने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी के एक फैसले में अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां कानून यानी आइईपीए के जरिये लगाए गए टैरिफ को असंवैधानिक ठहरा दिया। शीर्ष अदालत के इस निर्णय को हाल के दौर में व्हाइट हाउस की आर्थिक शक्तियों पर सबसे बड़े संस्थागत अंकुश के रूप में देखा जा रहा है। यह सिर्फ कुछ आयात शुल्कों को रद करने का मामला नहीं, बल्कि उस वैचारिक ढांचे पर चोट है, जिसके जरिये अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह मान लिया था कि वे अपनी मनमानी से वैश्विक व्यापार व्यवस्था को नए सिरे से तय कर सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि टैरिफ लगाना 'टैक्स' लगाने के दायरे में आता है और अमेरिकी संविधान यह शक्ति कांग्रेस को देता है, न कि राष्ट्रपति को। अदालत ने यह दलील भी खारिज कर दी कि व्यापार घाटा या फेंटानिल की तस्करी जैसे मुद्दे इतनी व्यापक और स्थायी आपात स्थिति हैं कि आइईपीए के तहत दुनिया के लगभग हर देश पर 10 से 50 प्रतिशत तक आयात शुल्क लगा दिया जाए। फैसले का सीधा प्रभाव यह है कि आइईपीए के तहत लगाए गए टैरिफ हटने से अमेरिका का औसत लागू टैरिफ स्तर अचानक घट गया और अब उन अरबों डालर की वसूली पर कानूनी सवाल उठ गया है जो पिछले साल इन शुल्कों के रूप में जमा किए गए थे।

ध्यान रहे कि यही आइईपीए टैरिफ ट्रंप के तथाकथित लिबरेशन डे अभियान की धुरी थे, जिसकी आड़ में उन्होंने चीन से लेकर कनाडा, यूरोप, जापान और भारत तक लगभग हर साझेदार पर दबाव बनाया। विभिन्न आर्थिक आकलनों के अनुसार इन टैरिफों की वापसी से 150-175 अरब डालर तक के रिफंड दावों की प्रक्रिया शुरू हो सकती है, जो पहले से बढ़ते राजकोषीय घाटे के बीच ट्रंप प्रशासन के लिए राजनीतिक और आर्थिक सिरदर्द बन सकती है। इस तरह अदालत ने सिर्फ एक कानूनी व्याख्या नहीं दी, बल्कि व्हाइट हाउस की टैरिफ से आर्थिक उगाही और उसे एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने वाली नीति के स्तंभ को हिला दिया है।

फैसले के तुरंत बाद ट्रंप ने जवाबी पहल करते हुए ट्रेड एक्ट, 1974 की धारा 122 के तहत नया दांव चला और सभी देशों से आने वाले आयात पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त वैश्विक सरचार्ज की घोषणा कर दी, जिसे अगले ही दिन बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 'हास्यास्पद, बेहद खराब तरीके से लिखा गया और असाधारण रूप से अमेरिका-विरोधी' कहकर न सिर्फ न्यायालय की वैधता पर हमला बोला, बल्कि यह संकेत भी दिया कि वे किसी भी संस्थागत अंकुश को राजनीतिक संघर्ष में बदल देंगे। हालांकि धारा 122 आइईपीए की तरह असीमित गुंजाइश प्रदान नहीं करती। इसके तहत अधिकतम 15 प्रतिशत तक ही शुल्क लगाया जा सकता है और इसकी अवधि भी 150 दिन तक सीमित है। उसे बढ़ाने के लिए कांग्रेस की स्वीकृति भी आवश्यक है। यह समयसीमा अमेरिकी मध्यावधि चुनाव अभियान के बीच पड़ाव से गुजरती है। इस दौर में मामूली बहुमत और कड़े मुकाबले वाले राज्यों में रिपब्लिकन नेताओं के लिए ऊंचे टैरिफ का बचाव करना आसान नहीं होगा।

टैरिफ पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दबाव में राष्ट्रपति ट्रंप ● फाइल

नई परिस्थितियों में ट्रंप प्रशासन धारा 232 (राष्ट्रीय सुरक्षा) और धारा 301 (भेदभावपूर्ण या अनुचित व्यापार व्यवहार) जैसे प्रविधानों के सहारे नए टैरिफ ढांचे की बात कर रहा है। हालांकि इस राह में विस्तृत जांच, तकनीकी रिपोर्ट और न्यायिक समीक्षा जैसी बाधाएं भी हैं। इसका यही अर्थ है कि अब एकाएक किसी इंटरनेट मीडिया पोस्ट के माध्यम से सौ प्रतिशत तक का टैरिफ लगाने का दौर गया-बीता हो गया है। इस फैसले का सबसे दूरगामी असर उन द्विपक्षीय और मिनी-डील्स जैसे समझौतों पर पड़ेगा जो ट्रंप प्रशासन ने टैरिफ की धमकी देकर कराई थीं। इस क्रम में ब्रिटेन, जापान, भारत, थाईलैंड, वियतनाम जैसे देशों ने ऊंचे टैरिफ से छूट पाने के लिए कृषि, ऊर्जा, डिजिटल व्यापार और नियमन में महत्वपूर्ण रियायतें दीं। अब जब टैरिफ को ही गैरकानूनी बता दिया गया है तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि ऐसे समझौते कितने वैध और टिकाऊ हैं। इस स्थिति में अमेरिकी पक्ष की ताकत कम होते ही साझेदार देशों के लिए सौदों की पुनर्समीक्षा का अवसर खुल गया है।

भारत के लिए तात्कालिक गणित सकारात्मक दिखता है। फरवरी की शुरुआत में जो अंतरिम व्यवस्था बनी थी, उसके तहत भारत पर लगने वाला प्रभावी टैरिफ स्तर 18 प्रतिशत माना जा रहा था। अब 15 प्रतिशत का वैश्विक टैरिफ लागू होने का अर्थ यह है कि भारत पर भी यही दर लागू होगी और कई उत्पादों पर पूर्व की तुलना में कुछ राहत मिलेगी। इससे भारतीय निर्यातकों के लिए अमेरिकी बाजार में आकर्षण और अधिक बढ़ सकता है।

इसमें भारत के लिए कुछ नीतिगत संदेश भी स्पष्ट हैं। पहला, वाशिंगटन के साथ चल रही व्यापार वार्ता का खाका नए सिरे से तय करना होगा। भारत को कुछ कड़ी सौदेबाजी से भी संकोच नहीं करना चाहिए। दूसरा, भारत को यह मानकर चलना होगा कि अनिश्चितता अब अमेरिकी व्यापार नीति का स्थायी गुण बन चला है। अदालत ने भले ही कार्यपालिका की एक सीमा तय कर दी हो, लेकिन ट्रंप की राजनीतिक शैली खुद अनिश्चितता को ही रणनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करती है। तीसरा, यह क्षण भारत के लिए अवसर भी है। अमेरिकी अदालत ने दर्शाया है कि संस्थागत व्यवस्था अभी भी कारगर हो सकती है। इसने वैश्विक साझेदारों को यह भी याद दिलाया है कि किसी एक नेता की मर्जी से ही अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का पुनर्लेखन संभव नहीं। ऐसे में, यदि भारत इस गुंजाइश का उपयोग अपने निर्यातकों के लिए बेहतर पहुंच, नियामकीय स्पष्टता और बहुपक्षीय मंचों पर अधिक सक्रिय भूमिका के लिए करता है, तो यह निर्णय केवल अमेरिकी घरेलू राजनीति की घटना न रहकर, भारत की दीर्घकालिक आर्थिक कूटनीति के लिए भी अहम मोड़ साबित हो सकती है।

(लेखक जेएनयू में एसोसिएट प्रोफेसर और 'द इंडियन फ्यूचर्स' के संस्थापक हैं)

response@jagran.com

जाति विभाजन की गहरी होती दरारें

अमेश चतुर्वेदी

समय के साथ जाति विभाजन की जो रेखाएं धुंधली पड़ने लगी थीं, वे यूजीसी के कदम से फिर गहरी होती नजर आ रही हैं

यूजीसी के दिशानिर्देश से चर्चा में आई जाति ● फाइल

उच्च शिक्षा परिसरों में समता लाने के नाम पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा हाल में जारी दिशा-निर्देशों ने न केवल जाति विमर्श को चर्चा के केंद्र में ला दिया है, बल्कि हिंदू समाज एक बार फिर जातीय खांचों में बंटता नजर आ रहा है। आर्थिक और शैक्षिक विकास के कारण जाति विभाजन की जो रेखाएं समय के साथ धुंधली पड़ने लगी थीं, वे अब पुनः गहरी होती दिखाई दे रही हैं। वर्तमान परिस्थितियां मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होने के बाद उत्पन्न हुए उस दौर की याद दिला रही हैं, जब हिंदू समाज स्पष्ट रूप से विभाजित हो गया था। आज समाज फिर उसी राह पर अग्रसर दिख रहा है। जाति के आधार पर राजनीतिक रोटियां सेंकने वाले कुछ दल छात्रों के बीच इस विमर्श को हवा दे रहे हैं, ताकि चुनावी लाभ लिया जा सके। इसके विपरीत, सवर्ण समाज भी अपने हितों की रक्षा के लिए छात्रों को लामबंद करने में पूरी शक्ति से जुटा हुआ है। यदि यूजीसी के इन दिशा-निर्देशों का कोई सर्वसमावेशी और सर्वमान्य हल नहीं खोजा गया, तो इसका सीधा असर भविष्य की राजनीति पर पड़ेगा। इससे न केवल सामाजिक समरसता प्रभावित होगी, बल्कि व्यापक हिंदू एकता का लक्ष्य भी संकट में पड़ सकता है।

जहां सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक विकास ने जातिगत विभाजन की दीवारों को कमजोर किया, वहीं राजनीति इसे पुनः उभारने में सफल रही है। पिछड़ी जातियों के उत्थान के नाम पर जाति विमर्श को सत्ता के केंद्र में लाने का मुख्य श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को जाता है। उन्होंने 1990 में चौधरी देवीलाल के राजनीतिक रसूख को काबू में करने के लिए मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू कर दिया। उस निर्णय ने हिंदू समाज को वैचारिक और सामाजिक स्तर पर बुरी तरह विभाजित कर दिया। तब मंडल आयोग के विरोध में लगभग समूचा उत्तर भारत सुलग उठा था और सवर्ण समुदाय के युवाओं को अपना भविष्य अंधकारमय प्रतीत होने लगा था। मंडल आयोग द्वारा पैदा की गई इस सामाजिक खाई को बाद की राजनीति ने पाटने के बजाय और अधिक गहरा ही किया है। जब समाज ने सरकारी नौकरियों में पिछड़ों के आरक्षण को धीरे-धीरे स्वीकार करना शुरू किया, तभी वर्ष 2006 में मनमोहन सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थानों के दाखिले में भी पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रविधान कर दिया। इस निर्णय के विरोध में छात्र एक बार फिर सड़कों पर उतर आए, जिससे सामाजिक विभाजन की दरारें और चौड़ी हो गईं। आज जब देश इन पुराने संघर्षों की स्मृतियों से उबर ही रहा था, तभी यूजीसी के नए दिशा-निर्देशों ने भारतीय समाज को पुनः एक गहरे अंतर्द्वंद्व और सामाजिक संघर्ष के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। यद्यपि यह संघर्ष अभी सार्वजनिक रूप से सड़कों पर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन विश्वविद्यालयों के परिसर इस वैचारिक उबाल की चपेट में हैं। वर्तमान में शैक्षणिक परिसर दो स्पष्ट गुटों में बंटे नजर आ रहे हैं-एक तरफ इस गाइडलाइन के प्रबल समर्थक हैं, तो दूसरी तरफ इसके तीखे विरोधी।

देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 27 जून, 1961 को सभी मुख्यमंत्रियों के नाम एक विस्तृत पत्र लिखा था। उस पत्र में नेहरू जी ने वर्तमान जाति-आधारित आरक्षण की व्यवस्था को एक प्रकार से नकार दिया था। वे आरक्षण-आधारित विकास के स्थान पर एक ज्ञान-केंद्रित समाज का निर्माण करना चाहते थे। नेहरू जी ने स्पष्ट शब्दों में लिखा था, "मुझे किसी भी रूप में आरक्षण पसंद नहीं है, विशेषकर नौकरियों में आरक्षण। मैं ऐसे किसी भी कदम के विरुद्ध हूं जो अक्षमता को बढ़ावा देता है और हमें औसत दर्जे की ओर ले जाता है।" नेहरू का मानना था कि यदि हमें देश को आधुनिक और प्रतिस्पर्धी बनाना है, तो योग्यता को प्राथमिकता देनी होगी। विडंबना यह है कि यदि यूजीसी की वर्तमान गाइडलाइन का विरोध करने वाले लोग आज पंडित नेहरू के इन शब्दों को दोहराएं, तो उन्हें तुरंत सामाजिक न्याय का विरोधी करार दे दिया जाएगा। यह तथ्य दर्शाता है कि पिछले छह दशकों में भारतीय राजनीति और सामाजिक विमर्श की दिशा कितनी बदल चुकी है।

मंडल आयोग के लागू होने के बाद देश में जो राजनीतिक विमर्श स्थापित हुआ, उसमें सवर्ण समाज प्रगति विरोधी कहलाने के भय से एक लंबे समय तक चुप्पी साधे रखी। किंतु बाद के वर्षों में विशेषकर एससी-एसटी कानून के दुरुपयोग और आरक्षण के निरंतर विस्तार ने इस वर्ग के भीतर एक दबाव पैदा किया। राम मंदिर आंदोलन के पश्चात सवर्ण समाज ने जिस तरह एकतरफा भाजपा का दामन थामा था, वह अब इस नई गाइडलाइन से चकित रह गया है। यही विस्मय अब गुस्से में परिवर्तित हो रहा है। सत्ता की बाट जोह रहे विपक्षी दल पर्दे के पीछे से इस असंतोष को हवा तो दे रहे हैं, किंतु वे खुलकर बोलने से बच रहे हैं। उन्हें भय है कि सवर्णों का पक्ष लेने पर कहीं उनका 'पिछड़ा वोट बैंक' न बिदक जाए। भाजपा सरकार और संगठन के शीर्ष नेता इस जातीय विमर्श को ठंडा करने के प्रयासों में जुटे हैं, लेकिन इस समस्या का समाधान खोजने में जितनी विलंब होगा, जाति विमर्श उतना ही प्रखर होता जाएगा। यदि समय रहते सवर्ण समुदाय का यह गुस्सा शांत नहीं हुआ, तो आने वाले चुनावों में भाजपा के लिए नई और कठिन चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

आत्मबल

यदि आत्मबल सुदृढ़ हो, तो किसी भी प्रकार का संकट विचलित नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मबल के सहारे ही समस्त समस्याओं का समाधान संभव है। वस्तुतः आत्मबल स्वतः प्राप्त नहीं होता। इसके लिए सात्विक जीवन और उच्च आचरण की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत झूठ, फरेब और छल-कपट से मनुष्य की बुद्धि कुंठित हो जाती है। परिणामतः विपरीत परिस्थितियां आने पर वह किंकर्तव्यविमूढ़ हो जाता है और उसे उचित मार्ग नहीं सूझता। मनुष्य की वास्तविक शक्ति बाह्य संसाधनों में नहीं, बल्कि उसके भीतर निहित है। यदि कोई व्यक्ति चोरी करके आ रहा हो और अचानक सामने पुलिस आ जाए, तो भले ही पुलिस कुछ न पूछे, किंतु उसका अंतर्मन कांपने लगता है।

आत्मबल को पुष्ट करने का अनुपम उदाहरण गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में 'रावनु रथी बिरथ रघुबीरा, देखि बिभीषन भयउ अधीरा' के प्रसंग में दिया है। श्री राम ने विभीषण को आंतरिक शक्तियों के 'धर्म-रथ' के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा, "इस शरीर रूपी रथ के पहिये शौर्य और धैर्य हैं। सत्य और शील इसकी ध्वजा (पताका) हैं। बल, विवेक, इंद्रिय-निग्रह और परोपकार इस रथ के घोड़े हैं, जो क्षमा, दया और समता रूपी डोरी से जुड़े हुए हैं। ईश्वर का भजन ही इसका सारथि है, वैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है। दान इस युद्ध का फरसा है।" श्री राम ने सर्वाधिक बल 'बुद्धि' पर दिया है, जो एक प्रचंड शक्ति है। वास्तव में जो व्यक्ति बुद्धि और विवेक के सहारे निर्णय लेता है, वह कभी संकट में नहीं पड़ता। विवेक नीर-क्षीर की भांति उचित और अनुचित का अंतर स्पष्ट करता है। हमारा अंतर्मन सदैव हमें सही और गलत का संकेत देता रहता है। अतः जहां मन कहे कि कार्य अनुचित है, उससे तत्काल विरक्त हो जाना चाहिए। ऐसा आचरण करने से मन सदैव प्रसन्न और आत्मबल से परिपूर्ण रहेगा।

सलिल पांडेय

पाठकनामा

pathaknama@nda .jagran.com

ट्रंप भरोसे के काबिल नहीं

'ट्रंप की मनमानी पर रोक' शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के अस्थिर व्यक्तित्व की चर्चा की गई है। यद्यपि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न देशों पर मनमाने टैरिफ लगाने संबंधी उनके फैसलों को पलट दिया है, किंतु यह आशंका बलवती है कि वे पुनः किसी न किसी बहाने अपने 'टैरिफ प्रेम' को उजागर करेंगे। जैसा कि देखा भी गया, अदालती फैसले के कुछ ही घंटों के भीतर सभी देशों पर पहले 10 प्रतिशत टैरिफ लगाया, फिर उसे बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया। यदि भविष्य में भी अनैतिक व्यापार और अमेरिकी सुरक्षा को होने वाले नुकसान का हवाला देकर उनके द्वारा टैरिफ लगाने का यह क्रम जारी रहता है, तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अतः विकासशील देशों को अपने वे कदम और रणनीतियां नहीं रोकनी चाहिए, जिन्हें उन्होंने विकल्प के तौर पर अपनाना शुरू किया है। राष्ट्रपति ट्रंप के अस्थिर निर्णय जिस प्रकार उजागर हुए हैं, उससे वैश्विक समुदाय का उन पर भरोसा करना सहज नहीं है। बहरहाल अगले महीने भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर हस्ताक्षर होने वाले हैं, जो एक अप्रैल से प्रभावी होगी, लेकिन 'अमेरिका को महान बनाने' की ओट में ट्रंप द्वारा उठाए जाने वाले विध्वंसकारी कदम वैश्विक अस्थिरता के दौर को जारी रखेंगे। संपादकीय में ईरान और क्यूबा को लेकर व्यक्त की गई आशंकाएं भी यथोचित प्रतीत होती हैं। अंततः अमेरिकी सर्वोच्चता के इस हठपूर्ण सिद्धांत से वैश्विक बाजार के साथ-साथ स्वयं अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी बड़े नुकसान की आशंका है।

mananmk8155@gmail.com

मातृभाषा की महत्ता

'सींचना होगा मातृभाषाओं का स्वाभिमान ' शीर्षक से आलेख में कुमुद शर्मा जी ने विश्व में तेजी से लुप्त होती भाषाओं के विषय में ध्यान आकर्षित किया है उनका यह कथन की प्रत्येक दो सप्ताह में दुनिया से एक भाषा गायब हो जाती है विषय की गंभीरता को प्रदर्शित करता है। वास्तव में मातृभाषा केवल साधारण संचार का माध्यम ही नही यह एक समाज की संपूर्ण सभ्यता होती है, संपूर्ण संस्कृति होती है, उस राष्ट्र की समृद्धि का इतिहास होती है, विश्व में सर्वाधिक आक्रमण भाषाओं पर ही हुए हैं। यदि किसी राष्ट्र या समाज को समाप्त करना है तो उसकी अपनी भाषा को समाप्त कर दो उसकी अपनी पहचान, इतिहास , संस्कृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी। क्योंकि उसके पास जो कुछ संस्कारों की, परंपराओं की विकास की पुरानी विरासत होगी वह उसकी अपनी भाषा में ही होगी। यह भी निर्विवादित सत्य ही है की बच्चा अपनी भातृभाषा में सबसे जल्दी सीखता है। इतिहास और वर्तमान दोनों साक्षी हैं की जिन देशों ने अपनी शिक्षा पद्धति अपनी मातृभाषा में रखी वही आज के विकसित देश है। भारत में प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाएं एवं संस्थान अंग्रेजी को महत्व देते हैं जबकि भारत में केवल पांच प्रतिशत बच्चे ही अंग्रेजी में शिक्षा पाते है, 95 प्रतिशत बालक बाहर हो जाते है जिनमें प्रतिभा तो होते है परंतु मुख्य विकास धारा का भाग नहीं होते है।

विपिन गोयल, हापुड़

नकारात्मक राजनीति

वैश्विक स्तर पर द्रुतगति से दौड़ती भारतीय अर्थव्यवस्था, बढ़ता विदेशी निवेश, फ्रांस से 114 अत्याधुनिक लड़ाकू विमान राफेल की डील हुआ है। जिसमें 94 राफेल विमानों का भारत में ही निर्माण होना है। तकनीक हस्तांतरण, भारतीय हथियारों की फ्रांस द्वारा खरीद-फरोख्त, न्यूजीलैंड, यूके आदि दूसरे देशों समेत मदर आफ आल डील से ख्याति प्राप्त यूरोपियन यूनियन से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का होना यही दर्शाता है कि वैश्विक स्तर पर व्यापार समझौतों के लिए भारतीय बाजार पहली पसंद बन चुका है। भारत मंडपम में भारत द्वारा निर्मित सर्वम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर शिखर सम्मेलन चल रहा है, जिसमें 125 देशों के प्रतिनिधि मंडल समेत 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष व विश्व की बड़ी-बड़ी टेक कंपनियां के सीईओ आदि भाग ले रहे हैं। निस्संदेह यह विशाल स्तर पर भव्यता लिए एक तकनीकी आयोजन है जिसमें स्वदेशी तकनीकी क्षेत्र में भारत की गूंज सुनाई देती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की युवा विंग ने चलते शिखर सम्मेलन में नकारात्मक राजनीति से प्रेरित होकर 10-12 युवा कांग्रेसी नेताओं ने बेशर्मी की सभी हदें लांघते हुए प्रधानमंत्री की छवि धुमिल करने के लिए जो किया है उससे बीजेपी नहीं वर्ना सारा देश गुस्से में हैं और शर्मिंदगी महसूस कर क्षुब्ध व स्तब्ध हैं। कांग्रेस के मीडिया प्रवक्ता पवन खेड़ा का ये कहना कि यह प्रदर्शन लाखों बेरोजगार युवाओं की आवाज थी निहायत ही अपरिपक्व, स्तरहीन, ओछी राजनीति से लबरेज बयान है।

दीपक गौतम, सोनीपत

पोस्ट

पैदल सिपाहियों की गलत रणनीति कई बार हाथी सवार बादशाह की हार का कारण बनती है।

उमाशंकर सिंह @umashankarsingh

भारत चांद पर पहुंच जाए, मंगल पर पहुंच जाए, वैश्विक एआइ समिट आयोजित कर ले, मगर पश्चिमी मीडिया अपनी जलन नहीं छुपा पाता।

अंकित कुमार अवस्थी @kaankit

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 725 अरब डालर हो गया। अमेरिकी टैरिफ के शोरशराबे के बावजूद इसमें बढ़ोतरी होती गई। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए यही सब भरोसेमंद खाद-पानी है। जो लोग भारत की अर्थव्यवस्था को निगेटिव मानते हैं, उन्हें इस सच को स्वीकार करना चाहिए।

संजय निरुपम @sanjaynirupam

दूसरे देशों से रिश्ते कैसे हों, अधिकांश मामलों में यह इस बात से तय होता है वहां कुर्सी पर कौन है। कनाडा में ट्रूडो ने अपनी निकृष्ट राजनीति के लिए भारत से रिश्ते बिगाड़े तो बांग्लादेश से मोहम्मद यूनुस दो कदम आगे निकल गए। अब दोनों देशों से संबंध पहले की तरह होने में देर नहीं। अखिलेश शर्मा @akhileshsharma1

जनपथ

कोशिश पूरी हो रही बंटे सनातन धर्म,
अगर 'बंटे तो कटेंगे' समझो इसका मर्म।
समझो इसका मर्म कर्म यदि होगा दागी,
होगा उसका न्याय चहे हो वह बैरागी।
हम सब रहें सतर्क बात यह बहुत जरूरी,
हमें बांटने हेतु हो रही कोशिश पूरी!

– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन.नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा जागरण प्रकाशन लि. के लिए डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा -201309 से मुद्रित एवं 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित
संपादक (दिल्ली एनसीआर)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No 50755/90 समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त। वर्ष 36 अंक 220

हां 82%
नहीं 18%

क्या देशों में एआइ सुपरपावर बनने की होड़ इसमें निहित शक्ति को दिखाती है?

हां 72%
नहीं 28%

क्या एआइ अगले पांच वर्ष में हमारे जीवन में बड़े क्रांतिकारी बदलाव लाएगा?

मुद्दा से संबंधित अपनी राय, सुझाव और प्रतिक्रिया mudda@jagran.com पर भेज सकते हैं।

एआइ कितनी चुनौती कितने अवसर

देश की राजधानी दिल्ली में अब तक के सबसे बड़े एआइ इम्पैक्ट समिट के अभूतपूर्व आयोजन के बाद चहुंओर इसकी चर्चा है। मशीनी दक्षता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे नामों से कही-सुनी जाने वाली इस अत्याधुनिक तकनीक एआइ को अब तक का सबसे बड़ा आविष्कार माना जा रहा है। हर क्षेत्र में इसके अनुप्रयोग की असीम संभावनाएं जताई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि यह इन्सान के दिमाग को और धार व रफ्तार देने वाली क्रांति लाएगी। सभी देश इस तकनीक पर अधिकार जमाने को आतुर हैं, भारत भी पीछे नहीं है। चूंकि यह तकनीक अपेक्षाकृत बहुत महंगी और ज्यादा संसाधन की दरकार करती है, लिहाजा भारत के सामने भी बड़ी चुनौती है। हालांकि इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि भारत जिस मानव संसाधन से लैस है और वह बहुत तेजी से इस श्रम शक्ति को कुशल भी बना रहा है, ऐसे में अगर इस तकनीक में भी वह अपना सिक्का जमा लेता है तो केवल कल्पना ही की जा सकती है कि इसके मानव संसाधनों की धार और रफ्तार क्या होगी। उम्मीद है, तमाम चुनौतियों के बावजूद यह वैश्विक आयोजन देश में न सिर्फ एआइ को स्थापित करने का बड़ा अवसर बनेगा बल्कि लोगों को इसके इस्तेमाल के प्रति प्रेरित करने में मददगार भी होगा...

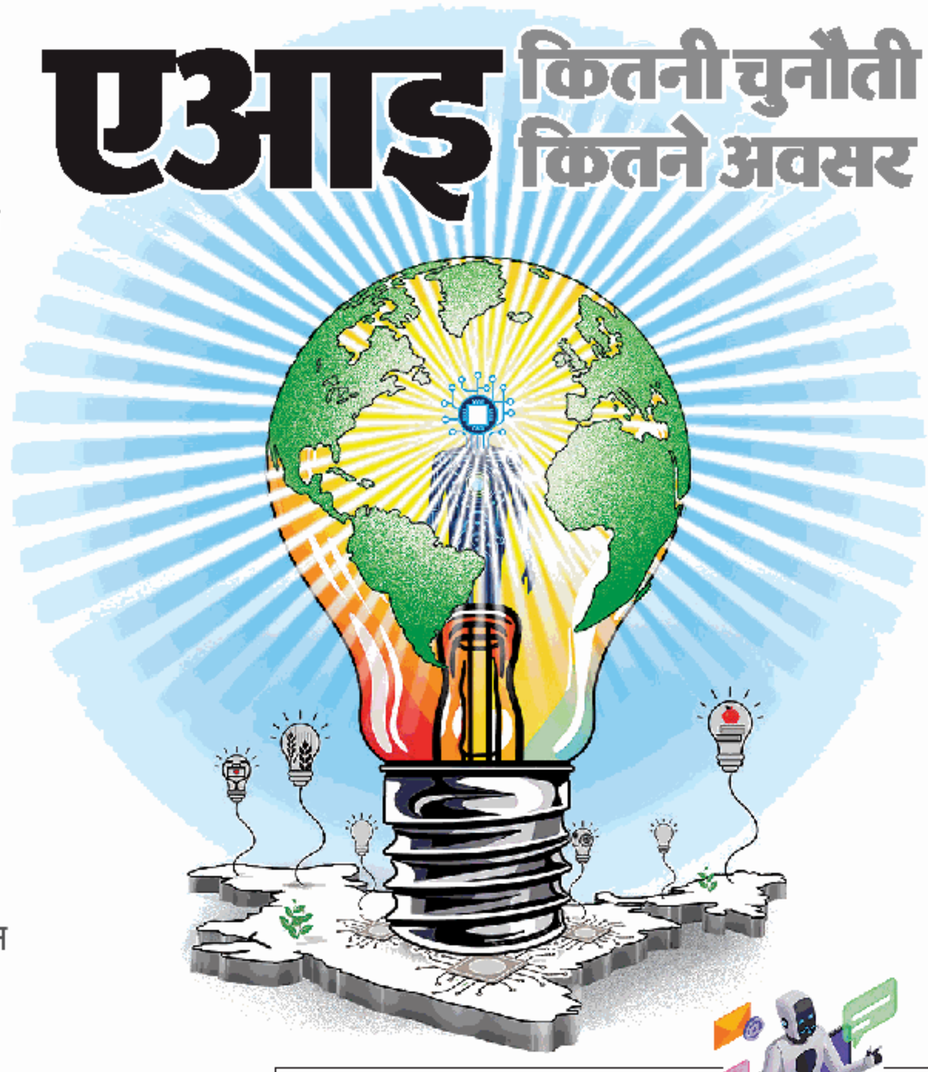

ऐसे बनता है मजबूत एआइ इकोसिस्टम

दुनिया तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) की दिशा में आगे बढ़ रही है और भारत भी इस क्षेत्र में मजबूत उपस्थिति दर्ज कराना चाहता है। लेकिन एक सशक्त एआइ इकोसिस्टम केवल साफ्टवेयर या एप बनाने से तैयार नहीं होता। इसके लिए ठोस डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर, गुणवत्तापूर्ण डाटा, प्रशिक्षित मानव संसाधन, दीर्घकालिक निवेश और स्पष्ट पालिसी फ्रेमवर्क की आवश्यकता होती है।

डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर

सबसे पहले बात डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर की करें तो एआइ के विकास के लिए उच्च क्षमता वाले कंप्यूटर, जीपीयू क्लस्टर और बड़े डाटा सेंटर जरूरी हैं। बड़े एआइ माडल को तैयार करने और उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए कंप्यूटिंग पावर की जरूरत होती है।

डाटासेट

एआइ का दूसरा महत्वपूर्ण आधार है डाटा। भारत जैसे बहुभाषी देश में विभिन्न भारतीय भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाले और स्वच्छ डाटासेट तैयार करना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही डाटा सिक्योरिटी और गोपनीयता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।

प्रशिक्षित मानव संसाधन

एआइ के क्षेत्र में मानव संसाधन की भूमिका भी बेहद अहम है। तकनीक तभी सफल होगी जब उसे विकसित और संचालित करने वाले लोग कुशल होंगे। भारत में आइआइटी, आइआइएससी और कई विश्वविद्यालयों में एआइ और मशीन लर्निंग से जुड़े कोर्स शुरू किए गए हैं। नीति आयोग ने 'नेशनल स्ट्रैटेजी फार एआइ' में शिक्षा और कौशल विकास को प्राथमिकता देने पर जोर दिया है। आगे की नीति में स्कूल स्तर से एआइ शिक्षा, उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग तथा कार्यरत कर्मचारियों के लिए री-स्किलिंग कार्यक्रमों को बढ़ावा देना आवश्यक होगा।

स्वदेशी समाधान

भारत को केवल एआइ तकनीक का यूजर नहीं, बल्कि उसका निर्माता बनने की दिशा में काम करना होगा। भारतीय भाषाओं के लिए बड़े लैंग्वेज माडल विकसित करना, कृषि, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे क्षेत्रों में स्वदेशी एआइ समाधान तैयार करना और अनुसंधान को दीर्घकालिक वित्तीय सहयोग देना बेहद जरूरी है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की साझेदारी स्वदेशी समाधान विकसित करने में अहम भूमिका निभा सकती है।

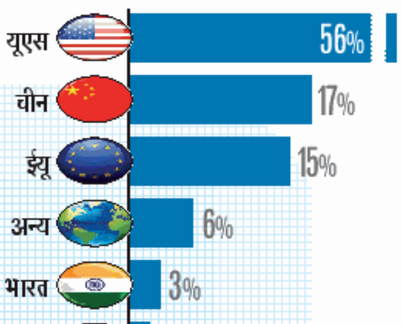

संतुलित रेग्युलेटरी फ्रेमवर्क

एआइ के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग के लिए स्पष्ट और संतुलित रेग्युलेटरी फ्रेमवर्क की आवश्यकता है। डीपफेक, साइबर अपराध और एल्गोरिदमिक पक्षपात जैसे जोखिमों को देखते हुए नियमों का होना अनिवार्य है, लेकिन ये नियम नवाचार में बाधा न बनें, इसका भी ध्यान रखना होगा।

एआइ की रेस में भारत

पिछले सप्ताह भारत में एआइ समिट का आयोजन किया गया। यह अपनी तरह की चौथी समिट थी और पहली बार इसका आयोजन भारत में हुआ है। इसमें बड़ी संख्या में वर्ल्ड लीडर एक मंच पर आए। फोकस इस बात पर था कि देश इनोवेशन को रेग्युलेशन के साथ कैसे संतुलित करें। यह आयोजन भारत के लिए अवसर के साथ आत्मनिरीक्षण का भी है कि एआइ की रेस में हम कहां खड़े हैं। आंकड़े भारत के एआइ इकोसिस्टम में ताकत और संरचनात्मक कमियों की मिली जुली तस्वीर दिखाते हैं?

प्रतिभा से समृद्ध, इन्फ्रास्ट्रक्चर कमजोर

भारत **टारट्वायज ग्लोबल एआइ इंडेक्स, 2024** में 10वें स्थान पर है। हमारी सबसे बड़ी ताकत प्रतिभा है। इस मोर्चे पर भारत की वैश्विक रैंकिंग दूसरी है। इसके अलावा परिचालन माहौल में भी हमारा प्रदर्शन शानदार है और इसमें भारत तीसरे स्थान पर है। इन्फ्रास्ट्रक्चर हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है और इसमें हम 68वें स्थान पर हैं। इसकी वजह से अमेरिका और चीन से प्रतिस्पर्धा करने की हमारी क्षमता सीमित हो जाती है।

कंप्यूटिंग सिस्टम की क्षमता

दुनिया के शीर्ष 500 हाई परफार्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम (एचपीसी) और क्षमता में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ एक प्रतिशत है। वहीं, अमेरिका के पास विश्व का 35 प्रतिशत कंप्यूटिंग सिस्टम और 48 प्रतिशत क्षमता है।

एआइ क्षमता के आधार पर शीर्ष 10 देशों की रैंकिंग

	प्रतिभा	इन्फ्रा	परिचालन माहौल	रिसर्च	डेवलपमेंट	कुल मिलाकर
अमेरिका	1	1	2	1	1	1
चीन	9	2	21	2	2	2
सिंगापुर	6	3	48	3	5	3
ब्रिटेन	4	17	4	4	16	4
फ्रांस	10	14	19	6	4	5
दक्षिण कोरिया	13	6	35	13	3	6
जर्मनी	3	13	8	8	11	7
कनाडा	8	18	16	9	10	8
इजरायल	7	26	65	7	6	9
इंडिया	2	68	3	14	13	10

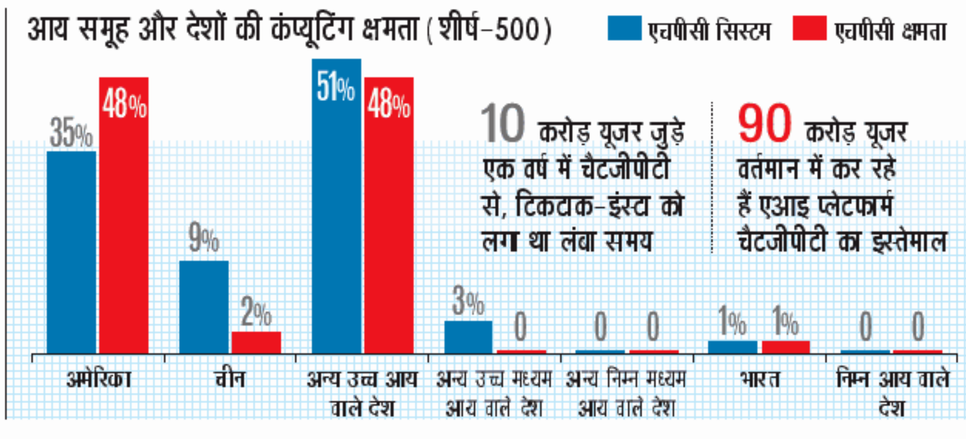

आय समूह और देशों की कंप्यूटिंग क्षमता (शीर्ष-500)

10 करोड़ यूजर जुड़े एक वर्ष में चैटजीपीटी से, टिकटाक-इंस्टा को लगा था लंबा समय

90 करोड़ यूजर वर्तमान में कर रहे हैं एआइ प्लेटफार्म चैटजीपीटी का इस्तेमाल

निवेश प्रवाह में सीमित हिस्सेदारी

भारत ने एआइ ट्रेनिंग डाटा में वैश्विक वेंचर कैपिटल निवेश का सिर्फ 3 प्रतिशत आकर्षित किया है। अमेरिका 56 प्रतिशत के साथ सबसे आगे है। चीन 17 प्रतिशत के साथ दूसरे नंबर पर और यूरोपीय संघ 15 प्रतिशत के साथ तीसरे स्थान पर है।

वैश्विक निवेश में हिस्सेदारी

कीमतों में कमी से बढ़ेगी आय

विकास सिंह
विशेषज्ञ, समग्र विकास

> एआइ कर्मचारियों की संख्या बढ़ाए बिना उत्पादन बढ़ाने में मदद कर रहा है। इसका मतलब है कि रोजगार सृजन के मोर्चे पर इसका असर नकारात्मक है। कई क्षेत्रों में एआइ लोगों के लिए कीमतें कम कर रहा है। इससे परिवारों की प्रभावी बढ़ रही है।

भारत की जनसंख्या तो बढ़ रही है लेकिन रोजगार का इंजन तेजी से नहीं चल पा रहा है। बेंगलुरु के टेक्नोलाजी कारिडोर में गतिविधियां सुस्त हो रही हैं। दो दशकों तक भारत के सेवा क्षेत्र में तेजी एक आसान फार्मूले पर चली। फार्मूला था ज्यादा कांट्रैक्ट के लिए ज्यादा इंजीनियरों की जरूरत। पेरोल और रेवेन्यू को बढ़ाया गया। अब यह हिसाब लड़खड़ा रहा है। बड़ी आइटी कंपनियों में राजस्व में स्थिरता के बावजूद कर्मचारियों की संख्या कम हो रही है। मैन्यूफैक्चरिंग सेगमेंट में भी यही पैटर्न दिख रहा है। हाल के निवेश चक्र पहले के मुकाबले कर्मचारियों की संख्या में कमी दिखा रहे हैं। आटोमेशन, रोबोटिक्स और डिजिटाइजेशन कर्मचारियों की संख्या में उसी अनुपात में बढ़ोतरी किए बिना उत्पादन बढ़ा रहे हैं। कई नई फैक्ट्रियां बड़ी संख्या में कर्मचारियों की नियुक्ति करने के बजाय कैपिटल-डीपनिंग ज्यादा कर रही हैं। कैपिटल डीपनिंग का मतलब है कि अर्थव्यवस्था में प्रति कामगार पूंजी बढ़ रही है। यह ऐसे समय में हो रहा है जब औद्योगिक नीति विस्तार के जरिये नौकरियों के सृजन पर जोर दे रही है। भारत में हर साल लगभग 70 से 80 लाख वर्कर वर्कफोर्स में जुड़ रहे हैं। इसके बावजूद ग्रोथ और नई नियुक्तियों के बीच असंतुलन बढ़ रहा है। हाल के रिपोर्टिंग साइकिल में प्रति कामगार राजस्व बढ़ा है और मार्जिन भी मजबूत हुआ है। एआइ सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है। यह ग्रोथ में कर्मचारियों की भूमिका को नया आकार दे रहा है। भारत की बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए यह एक संरचनात्मक बदलाव है। आइटी सेक्टर जीडीपी में लगभग 8 प्रतिशत और निर्यात में इससे ज्यादा योगदान देती है। मैन्यूफैक्चरिंग से लंबे समय से उम्मीद की जा रही है कि वह कृषि से निकल कर आने वाले श्रमिकों को समायोजित करेगी। अगर सेवा क्षेत्र और इंडस्ट्री दोनों कम कामगारों के साथ ज्यादा उत्पादन करते हैं, तो साफ है कि कामगारों की जरूरत कम हो रही है। एआइ उत्पादन की हर यूनिट के लिए जरूरी लेबर को कम करके इस बदलाव को गति दे रहा है। पहले के तकनीकी बदलावों ने आखिरकार काम की नई कटेगरी बनाई। एआइ गति के लिहाज से अलग है। यह नियमों के अनुपालन, डायग्नोस्टिक, अकाउंटिंग, लाजिस्टिक्स कोआर्डिनेशन और स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रक्शन जैसे सूचना आधारित सेक्टर में कर्मचारियों की भूमिका को कम करता है। पेरोल में उसी अनुपात में वृद्धि के बिना भी उत्पादन बढ़ सकता है। फिर भी यह सिर्फ विस्थापन की कहानी नहीं है। यह लागत में कमी की भी कहानी है। पिछले दशक में भारत का सबसे अहम डिजिटल इनोवेशन डिजिटल पेमेंट का इन्फ्रास्ट्रक्चर था। इससे लेनदेन की लागत को शून्य कर दिया और भागीदारी को बढ़ाया। एआइ भी ऐसी ही संभावनाएं दे रहा है। सेवाओं में सूचना की लागत कम करके यह आय बढ़ा सकता है। जब चिकित्सा सलाह, ट्यूशन, रेग्युलेटर कम्प्लायंस या लाजिस्टिक्स कोआर्डिनेशन की कीमत कम होती है, तो परिवारों को प्रभावी आय के मोर्चे पर फायदा होता है।

आपकी आवाज

एआइ का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, न्यायपालिका और प्रशासन सहित लगभग हर क्षेत्र में प्रारंभ हो चुका है। आने वाले पांच वर्षों में एआइ तकनीक मानव जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगी। इससे कार्यों की गति और सटीकता बढ़ेगी, समय और संसाधनों की बचत होगी तथा नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। परंतु हर तकनीक की तरह एआइ के भी दो पहलू हैं विकास और विनाश। जहां एक ओर यह जीवन को सरल बना सकती है, वहीं गलत उपयोग से रोजगार संकट, गोपनीयता का हनन और नैतिक चुनौतियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। **हिमांशु शेखर**

एआइ तकनीक हमारे जीवन में बहुत से बदलाव लाएगी, जैसे स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो सकती हैं। इस तकनीक से साइबर सुरक्षा मजबूत होगी, सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता लाने के लिए इस तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है, जिससे फर्जीवाड़े रुक सकते हैं। हालांकि मात्र पांच वर्षों में ही हमारे सारे देश में बहुत बदलाव ला देगा यह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हमारा देश गांवों का देश है और यहां के लोग नई तकनीक से बहुत जल्दी परिचित नहीं होते हैं। **राजेश कुमार चौहान**

लोग एआइ का उपयोग करना सीखेंगे, वे उन लोगों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करेंगे जो इसका विरोध करेंगे। एआई-आधारित स्वायत्त कारें और सार्वजनिक परिवहन अधिक सामान्य हो जाएंगे। शहर के बुनियादी ढांचे को मैनेज करने जैसे कचरा प्रबंधन और ट्रैफिक को सुचारू करने में एआई प्रमुख भूमिका निभाएगा। यह डाक्टरों को स्तन कैंसर जैसी बीमारियों का पता लगाने में मदद करेगा। **गौरी शंकर अंतज**

नवाचार से आसान हुआ है पेशेवर जीवन

जसप्रीत बिंद्रा
सह संस्थापक, एआइएंडबियांड

> एआइ न सिर्फ जटिल योजनाएं बनाने और वैज्ञानिक निष्कर्ष समझने में मदद कर रहा है बल्कि रियल टाइम में निर्णय लेने में भी सक्षम है। इससे न सिर्फ उच्च स्तर के मानसिक कार्यों में उत्पादकता बढ़ाई है बल्कि यह भी दिखाया है कि यह कामकाजी जीवन को कितना आसान बना सकता है।

एआइ अब केवल एक उभरता हुआ क्षेत्र नहीं रहा; यह एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुका है, जहां नए माडल आर्किटेक्चर, मल्टी-माडल रीजनिंग और फाउंडेशनल माडल जैसी क्रांतिकारी प्रौद्योगिकियां सामने आ रही हैं। हम देख रहे हैं कि कैसे दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं, उद्योगों और संस्थानों में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ की परिभाषा बदल रही है। पिछले 18 महीनों में बड़े भाषा माडल (एलएलएम) और मल्टी-माडल सिस्टम ने केवल पैटर्न पहचानने से आगे बढ़कर जटिल योजनाओं, वैज्ञानिक निष्कर्षों, और रियल टाइम में निर्णय लेने में मदद जैसी क्षमताएं हासिल की हैं। जीपीटी-4, पीएएलएम-2, क्लाउड-3 और एलएलएमए जैसे माडल अब केवल भाषा के दायरे में नहीं, बल्कि कोड सिंथेसिस, जटिल योजना और निर्णय लेने में भी सक्षम हो गए हैं। इसी तरह, कंप्यूटर विजन और रिइन्फोर्समेंट लर्निंग जैसे क्षेत्रों में भी विकास हो रहा है जो भाषा, नजरिये और एक्शन को जोड़ने वाली प्रणालियां बना रहे हैं, जो पहले केवल अनुसंधान प्रयोगों तक सीमित थीं।

यह बदलाव इस बात का प्रतीक है कि कैसे संगठनों के लिए डाटा से मूल्य निकालने का तरीका बदल रहा है। पारंपरिक माडल डाटा संग्रहण, फीचर इंजीनियरिंग, और विश्लेषणात्मक माडलिंग अब स्व-निर्देशित शिक्षण, ट्रांसफर लर्निंग और अनुकूलित फाइन-ट्यूनिंग से बदल रहे हैं। उच्च-स्तरीय मानसिक कार्यों का आटोमेशन केवल उत्पादकता को बढ़ा नहीं रहा, बल्कि यह यह भी परिभाषित कर रहा है कि मशीनें अब किस हद तक हमारे कामकाजी जीवन में सहायक बन सकती हैं। ये सभी बदलाव वैश्विक स्तर पर हो रहे हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत ही स्थानीय होगा। भारत के लिए अवसर सिर्फ सिर्फ एआइ को अपनाने में नहीं बल्कि एआइ की स्वदेशी क्षमता विकसित करने और रणनीतिक एकीकरण में है। इंजीनियरिंग प्रतिभा, डिजिटल ढांचा, और डाटा नेटवर्क देश को वैश्विक एआइ पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना सकती हैं। हालांकि, इसके लिए भारत को केवल उपभोक्ता बनने के बजाय निर्माता बनने की दिशा में बढ़ना होगा। स्वदेशी फाउंडेशनल माडल, क्षेत्र-विशेष एआइ स्टैक और डाटा सुरक्षा नीति के साथ एआइ इन्फ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है। स्वास्थ्य और जीवन विज्ञान के क्षेत्रों में मल्टी-मोडल एआइ की परिपक्वता पहले ही डायग्नोस्टिक्स, ड्रग डिजाइन और व्यक्तिगत देखभाल में बदलाव ला चुकी है। जेनरेटिव माडल जो क्लिनिकल इमेजिंग, जीनोमिक्स, और स्वास्थ्य रिकार्ड को जोड़ते हैं, अब पूर्वानुमान और प्रारंभिक निदान जैसी नई दिशा में काम कर रहे हैं। इसी तरह जलवायु और स्थिरता के क्षेत्रों में पहले की तुलना में बहुत बड़े पैमाने पर माडलिंग संभव हो रही है, जो कुछ साल पहले असंभव था। वैश्विक वित्तीय प्रणाली भी इस बदलाव से गुजर रही है। एआइ-आधारित रिस्क माडलिंग और रियल टाइम में धोखाधड़ी का पता लगाना अब सामान्य अपेक्षाएं बन गई हैं। इन प्रणालियों को अब खुद सीखने वाले आर्किटेक्चर की आवश्यकता है जो बाजार की स्थितियों के साथ लगातार खुद को अनुकूलित कर सकें। भारत के वित्तीय क्षेत्र में इसका उपयोग करने के लिए न केवल एआइ को अपनाना होगा बल्कि एक सुरक्षित, पारदर्शी, और स्पष्ट एआइ ढांचा विकसित करना भी जरूरी होगा ताकि सिस्टम की स्थिरता सुनिश्चित हो सके।

इस समय एआइ केवल प्रदर्शन के बारे में नहीं है, बल्कि यह विश्वसनीयता के बारे में भी है। जैसे-जैसे एआइ माडल उच्च-जोखिम वाले क्षेत्रों स्वास्थ्य, शासन और कानूनी प्रणाली में उपयोग होने लगे हैं, वैसे-वैसे इनकी निष्पक्षता, समझने योग्य परिणाम, और आडिट क्षमता की आवश्यकता बहुत बढ़ गई है। भारत के पास एथिकल एआइ गवर्नेंस में नेतृत्व करने का अवसर है, जो संवैधानिक मूल्यों और सार्वजनिक हित के सिद्धांतों पर आधारित हो। इसके लिए तकनीकी मानक, माडल जोखिम ढांचे और गवर्नेंस प्रोटोकाल को भी लगातार विकसित करना होगा। भारत के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण स्पष्ट है। अगली तकनीकी क्रांति के मार्ग को प्रभावित करने के लिए भारत को एक सेवा-आधारित भागीदार से एआइ-स्वदेशी नवप्रवर्तक के रूप में बदलना होगा। इसके लिए नीति, उद्योग, अकादमी, और नागरिक समाज के बीच समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है। स्वदेशी एआइ शोध प्रयोगशालाएं, डाटा ट्रस्ट और हाई परफार्मेंस कम्प्यूटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को राष्ट्रीय प्राथमिकताएं बनाना होगा।

छात्रावास में मिलती थीं बच्चों को सिर्फ दो रोटियां, तहसीलदार पहुंचे तो रो पड़े बच्चे

छात्रावास में भोजन के लिए थाली लेकर बैठा छात्र ● नईदुनिया

छात्रावास में बच्चों को ऐसे दी जाती हैं जली हुई रोटियां ● नईदुनिया

नईदुनिया प्रतिनिधि, राजगढ़ : मध्य प्रदेश में छात्रावास संचालकों की मनमानी कमजोर वर्ग के बच्चों पर भारी पड़ रही है। उन्हें भरपेट भोजन तक नसीब नहीं होता। रविवार को राजगढ़ के एक शासकीय बालक प्री-मैट्रिक विमुक्त जाति छात्रावास में निरीक्षण करने पहुंचे तहसीलदार विनीत गोयल को भूखे पेट रहने की व्यथा बताते हुए बच्चे रो पड़े। कहा कि उन्हें हर रोज खाने में केवल दो रोटी दी जाती हैं। आज भी वह भूखे हैं, इस पर तहसीलदार ने होटल से भोजन मंगाकर बच्चों को खिलाया।

दरअसल, पिछले दिनों शिकायत मिलने पर 20 फरवरी को अधिकारी निरीक्षण करने पहुंचे थे, जरूरी दिशा निर्देश भी दिए, लेकिन बच्चों से बात नहीं की। रविवार को एसडीएम अंकिता जैन ने तहसीलदार को छात्रावास भेजकर वास्तविकता पता करने को निर्देश दिया था। तहसीलदार पहुंचे तो छठवीं के छात्र ने बताया कि सुबह उन्हें केवल दो रोटियां दी हैं। और मांगने पर मना कर दिया। वहीं, एक अन्य छात्र ने कहा कि कई बार उन्हें भूखे ही सोना पड़ता है। शिकायत करने पर डराया-धमकाया जाता है। घर भेज देने की चेतावनी दी जाती है। बच्चों की मानें तो नाश्ते में रोज उन्हें पोहा, दोपहर में दाल-रोटी और रात में आलू-टमाटर या आलू-मटर की सब्जी मिलती है। विनीत गोयल ने बताया कि बच्चों के अनुसार उन्हें सही खाना नहीं दिया जा रहा, जली रोटी दी जाती है। पंचनामा बनाया है, जिसे डीएम को भेजा जाएगा।

बीएचयू में फायरिंग मामले में तीन हमलावरों समेत पांच नामजद

- बिड़ला 'अ' छात्रावास के गेट पर छात्र पर चलाई थीं गोलियां
- साजिश, जानलेवा हमले व प्रदर्शन को लेकर दो मुकदमे

जागरण संवाददाता, वाराणसी : बीएचयू के बिड़ला 'अ' छात्रावास के मुख्य द्वार पर शनिवार रात बीए तृतीय वर्ष के छात्र रौशन मिश्रा और उसके साथी विशाल कुमार पर हुई फायरिंग के मामले में लंका थाने में दो अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने हमले का षड्यंत्र रचने के मामले में दो लोगों और फायरिंग करने वाले तीन आरोपितों समेत पांच को नामजद किया है। घटना के बाद हुए प्रदर्शन व धक्का-मुक्की के मामले में मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने 35-40 अज्ञात छात्रों के खिलाफ केस दर्ज कराया है।

पीड़ित रौशन मिश्रा की तहरीर पर लंका पुलिस ने जिला बदर रहे क्षितिज उपाध्याय व अभिषेक उपाध्याय को हमले का षड्यंत्र रचने का आरोपित बनाया है। वहीं, पीयूष कुमार तिवारी, ऋषभ व तपस (तीनों का पूरा पता अज्ञात) के खिलाफ जानलेवा हमला करने का मुकदमा दर्ज किया गया है। तहरीर के अनुसार, रौशन मिश्रा अपने साथी विशाल के साथ छात्रावास के गेट पर खड़े थे, तभी बाइक सवार तीन हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। पुलिस को मौके से पिस्टल से चली चार गोलियों के खोखे बरामद हुए हैं। घटना के बाद छात्रों ने बिड़ला चौराहे पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। बीएचयू के मुख्य सुरक्षा अधिकारी परमानंद सिंह की तहरीर पर दर्ज दूसरे मुकदमे में आरोप है कि छात्रों ने मार्ग जाम किया, बिड़ला-रुईया चौराहा जाम किया व सुरक्षाकर्मियों से धक्का-मुक्की की।

भारतीय डाक के पास 38 करोड़ बचत खातों में 22 लाख करोड़ : ज्योतिरादित्य

गुंटूर, प्रेट्र : केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भारतीय डाक के पास लगभग 38 करोड़ बचत खाते हैं, जिनमें 22 लाख करोड़ रुपये की धनराशि जमा है। उन्होंने कहा कि भारतीय डाक में सुकन्या समृद्धि योजना के 3.8 करोड़ खाते हैं, जिनमें 2.27 लाख करोड़ रुपये जमा हैं। सुकन्या समृद्धि योजना एक सरकारी बचत योजना है, जो लड़कियों के माता-पिता के लिए बनाई गई है। इसके जरिये वे अपनी बेटी की पढ़ाई और भविष्य के लिए पैसे बचा सकते हैं। ग्रामीण डाक सेवक सम्मेलन में सिंधिया ने बताया कि भारतीय डाक के मेल नेटवर्क को तेजी से आधुनिक बनाया जा रहा है। इसके लिए डाक को आसानी से और जल्दी छांटने के लिए मशीनों का उपयोग हो रहा है। रेडियो आवृत्ति पहचान, बारकोड व क्यूआर कोड जैसी प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जा रहा है।

बीएसएनएल ने देश में बंद की ई-सिम स्वैपिंग सेवा

जागरण संवाददाता, बाराबंकी: वीआइपी फोन नंबरों के ई-सिम स्वैपिंग में हो रहा फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने इस सेवा पर रोक लगा दी है। बीएसएनएल के साफ्टवेयर में सेंध लगाकर ओडिशा, राजस्थान व अन्य प्रांतों में यह धोखाधड़ी की जाती रही है। जिला दूर संचार प्रबंधक डीके सिंह ने इसकी पुष्टि कर बताया कि स्वैपिंग में फर्जीवाड़े की उच्च स्तर पर जांच की जा रही है।

बीएसएनएल बाराबंकी में चार साल पूर्व तैनात रहे अधिकारी मृगेंद्र कुमार वर्मा की लागिन आइडी से 101 वीआइपी फोन नंबरों की अवैध रूप से ई-सिम स्वैपिंग कर दी गई। वर्तमान में मृगेंद्र कुमार सीतापुर जिले में तैनात हैं। इस फर्जीवाड़े का राजफाश तब हुआ, जब दूरसंचार जिला प्रबंधक आजमगढ़ का मोबाइल नंबर भी ई-सिम स्वैपिंग होने से उनका नंबर बंद हो गया। उनकी शिकायत पर जब बाराबंकी बीएसएनएल में खंगाला गया तो जनवरी से शुरू हुआ यह फर्जीवाड़ा सामने आया। जनवरी 2026 में 39 और फरवरी में 62 वीआइपी नंबरों को ई-सिम में बदल दिया गया।

सर्विस प्रोवाइडर पर संदेह

अधिकारियों का कहना है कि दिसंबर 2025 तक संचार आधार एप, जिससे यह प्रक्रिया होती है, उसको बाहरी कंपनी आपरेट करती थी। जनवरी 2026 से बीएसएनएल अपने साफ्टवेयर पर यह काम कर रहा है। आशंका है कि पूर्व सर्विस प्रोवाइडर के कर्मचारी या अधिकारी तो कहीं इसमें न्हीं शामिल हैं।

नई दिल्ली घोषणापत्र

एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स) को लेकर दुनिया का सबसे बड़ा सम्मेलन 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट' अब जब संपन्न हो चुका है, तब संतोष के साथ कहा जा सकता है कि यह आयोजन अपने उद्देश्य में पूरी तरह सफल रहा। 'नई दिल्ली एआई इम्पैक्ट समिट घोषणापत्र' इसकी तस्दीक करता है। इसे विश्व के 88 देशों व अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने अपना समर्थन दिया है। इन देशों में अमेरिका और चीन भी शामिल हैं, जिनका फिलहाल एआई के क्षेत्र में दबदबा है। इन दोनों के अलावा रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा और यूरोपीय संघ आदि ने भी इस घोषणापत्र का समर्थन किया है। कुल मिलाकर, इन देशों व संगठनों ने भारत के 'सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय' दर्शन को स्वीकार किया है। हालांकि, इस घोषणापत्र में दर्ज प्रतिबद्धताएं बाध्यकारी नहीं हैं और ये देश अपनी स्वेच्छा से तय करेंगे कि इनके मुताबिक वे किस हद तक काम कर सकते हैं। फिर भी, एआई के बुनियादी संसाधनों तक सस्ती और आसान पहुंच व स्थानीय जरूरतों के हिसाब से नवाचार के पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने की जो प्रतिबद्धता जताई गई है, वह इसके लोकतंत्रीकरण की अहमियत रेखांकित करती है, क्योंकि एआई के विकास के लिए बड़े निवेश की दरकार होती है और दुनिया के बहुत सारे मुल्क अभी अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए ही जूझ रहे हैं।

निस्संदेह, इस सम्मेलन से दुनिया में भारत का कद बढ़ा है। लगभग 20 देशों के शासनाध्यक्षों और संसार की शीर्ष टेक कंपनियों के सीईओ की इसमें सक्रिय भागीदारी इस बात की पुष्टि करती है। अब यह सर्वज्ञात है कि एआई बड़े पैमाने पर दुनिया को प्रभावित करने लगी है, लिहाजा इसमें किसी किस्म का एकाधिकार समूची मानवता के लिए नुकसानदेह होगा, इसलिए भारत ने सम्मेलन के सूक्त वाक्य 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' में ही अपना नजरिया स्पष्ट कर दिया था। शनिवार को जारी घोषणापत्र इसी का विस्तार है। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उचित ही कहा है कि भारतीय दृष्टि को स्वीकारते हुए एआई के विकास में सहयोग के लिए इतने बड़े पैमाने पर देशों का सहमत होना मामूली बात नहीं है। तमाम देश न सिर्फ इससे संबंधित ज्ञान साझा करने को तैयार हुए हैं, बल्कि वे एआई में दक्ष कार्यबल के विकास में एक-दूसरे का सहयोग करेंगे। वे देशों को एआई पर आधारित अपनी अर्थव्यवस्था के विकास में भी मदद करेंगे।

यदि नई दिल्ली एआई इम्पैक्ट समिट घोषणापत्र के मुताबिक देशों ने कदम उठाए, तो वह दिन दूर नहीं, जब 'ग्लोबल विलेज' की अवधारणा सचमुच साकार हो जाएगी।

एआई को लेकर जो सबसे बड़ा सवाल इस वक्त लोगों को परेशान कर रहा है, वह यह कि क्या यह तकनीक वाकई बड़े पैमाने पर लोगों को बेरोजगार करने जा रही है? हालांकि, ऐसी आशंकाएं हर बदलाव के साथ उठती हैं और वक्त उनका हल भी निकालता है, मगर इस सम्मेलन में कई विदेशी व भारतीय एआई कंपनियों ने अपने तईं यह वादा किया है कि वे डाटा के आधार पर इस बात की पड़ताल करेंगी कि एआई का रोजगार और अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ने जा रहा है। लब्बोलुआब यही है कि एआई का सकारात्मक उपयोग बहुत जरूरी है। अगर नई दिल्ली एआई इम्पैक्ट समिट घोषणापत्र के मुताबिक देशों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने कदम उठाए, तो वह दिन दूर नहीं, जब भाषा की तमाम बाधाएं दूर हो जाएंगी और यह दुनिया 'ग्लोबल विलेज' की अवधारणा को सचमुच साकार कर सकेगी। इसलिए आवश्यक यह है कि घोषणापत्र में जो प्रतिबद्धताएं जताई गई हैं, उस दिशा में तेजी से कदम उठाए जाएं और एआई के नकारात्मक पहलुओं का मिल-जुलकर सर्वमान्य हल निकाला जाए।

ट्रंप के अमेरिका में टैरिफ पर टकराव

यहां स्कैन करें

शशांक | पूर्व विदेश सचिव

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने पासा ही पलट दिया है। टैरिफ बढ़ाने से खजाने में पैसा तो आया, पर महंगाई भी खूब बढ़ी है, जिससे अमेरिकियों में गुस्सा है। वहां मध्यावधि चुनाव भी करीब हैं।

अमेरिका का यह नया घटनाक्रम कार्यपालिका बनाम न्यायपालिका का टकराव शुरू कर सकता है। वहां की सर्वोच्च अदालत ने जैसे ही पिछले साल लगाए गए पारस्परिक सीमा-शुल्कों (टैरिफ) को अवैध करार दिया, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने महज कुछ घंटों में 1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 122 का उपयोग कर लिया। यह प्रावधान अमेरिकी राष्ट्रपति को 150 दिनों तक अधिकतम 15 फीसदी शुल्क लगाने का अधिकार देता है। हालांकि, इसे समय-पूर्व वापस लिया जा सकता है या कांग्रेस (संसद) की सहमति के बाद आगे भी बढ़ाया जा सकता है।

शीर्ष अदालत ने 6-3 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए कहा कि राष्ट्रपति अमेरिका में आयात होने वाली वस्तुओं पर टैरिफ के मामले में 1977 के कानून (इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स ऐक्ट) का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। यह एक तरह से राष्ट्रपति की कार्यशैली पर परोक्ष टिप्पणी थी, क्योंकि अदालत ने माना कि जिस बुनियाद पर यह कानून लागू किया गया था, वह सही नहीं है। इस घटनाचक्र से तीन अहम सवाल खड़े होते हैं। पहला, राष्ट्रपति ट्रंप अब 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' की अपनी योजना किस रूप में आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि सीमा शुल्क में बढ़ोतरी उनकी इसी सोच से जुड़ी थी? दूसरा, दुनिया की आर्थिक व्यवस्था इससे किस कदर प्रभावित होगी? और तीसरा, अमेरिका के साथ हुए व्यापार समझौतों पर यह फैसला कितना असरंदाज होगा?

यह बात तो तय है कि राष्ट्रपति ट्रंप 'अमेरिका को फिर से महान बनाने' को लेकर उत्सुक रहे हैं और इस 'टैरिफ-वार' से अमेरिकी खजाने को करीब 130 अरब डॉलर का फायदा हुआ है। लिहाजा, किसी न किसी तरह से वह बढ़े हुए शुल्क को कायम रखने की कवायद करेंगे ही। सन् 1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 122 का उपयोग इसी का नतीजा है, लेकिन अमेरिका में इस साल के अंत में मध्यावधि चुनाव भी हो सकते हैं और इसमें ट्रंप के लिए स्थिति बहुत अनुकूल नहीं दिख रही।

अब तक यही लग रहा था कि रिपब्लिकन पार्टी पूरी तरह से ट्रंप के नियंत्रण में है, पर हाल-फिलहाल में तस्वीर बदली है। टैरिफ बढ़ाने से सरकार के खजाने में बेशक पैसा आया है, पर देश में महंगाई भी खूब बढ़ी है, जिसके कारण लोगों में सत्तारूढ़ दल के खिलाफ गुस्सा पनप रहा है। रही-सही कसर एच-1बी वीजा नीति ने पूरी कर दी है, क्योंकि इसकी फीस बढ़ाने से भारतीयों में नाराजगी है। कई राज्यों में वे सियासी रूप से मजबूत हैं। 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' नीति से भी उनकी परेशानी बढ़ी है।

इसका अर्थ है कि घरेलू राजनीति को देखते हुए ट्रंप फिलहाल कोई आक्रामक रवैया शायद ही अख्तियार करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति को कई मामलों में विशेष अधिकार जरूर हासिल है, मगर अमेरिका में ऐसा संसद के माध्यम से ही किया जाता रहा है और दूसरे संस्थानों से सीधे-सीधे टकराने से बचने का प्रयास होता है। जाहिर है, चुनावी दबाव, घरेलू राजनीति और कांग्रेस में रिपब्लिकन की स्थिति को देखते हुए ट्रंप फूंक-फूंककर अपना कदम बढ़ाएंगे।

जहां तक वैश्विक आर्थिक स्थिति की बात है, तो अमेरिकी अदालत का फैसला उसे भी प्रभावित करेगी। ट्रंप की 'टैरिफ जंग' कई देशों के आर्थिक हितों को चोट पहुंचा रही थी। यहां तक कि जब उन्होंने इसके खिलाफ इकट्ठे खड़े होने का प्रयास किया, तब राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ी सफाई से तमाम देशों से अलग-अलग समझौते करने शुरू कर दिए। नतीजतन, कई देशों ने चुपचाप अमेरिकी व्यवस्था मान ली और कई 'निगोशिएशन' कर टैरिफ देने को तैयार हो गए। अब जब, यह व्यवस्था खारिज कर दी गई है, तब माना यही जा रहा है कि हर देश फिर से वार्ता शुरू करने का दबाव बनाएगा और टैरिफ का फिर से निर्धारण हो सकता है। जिन देशों से व्यापार समझौता लागू हो चुका है, वे भी अब नए सिरे से बातचीत कर सकते हैं।

इस फैसले का एक पहलू, जो आर्थिक समझौतों से जुड़ा है, वह हमारे लिए काफी अहमियत रखता है। पिछली सदी के अस्सी के दशक के दौर को कई कूटनीतिज्ञ शायद ही भूले होंगे, जब 'सुपर 301' चर्चा में थी। बेशक, तब अमेरिका के निशाने पर जापान था, क्योंकि वह दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत था और दोनों देशों के बीच व्यापार असंतुलन टोक्यो के पक्ष में झुका हुआ था, लेकिन जब अमेरिका ने अपनी 'सुपर 301' सूची जाहिर की, तब उसमें उसने भारत का भी नाम शुमार किया था और 'अनुचित व्यापार प्रथा वाला देश' बताया था। ट्रंप ने टैरिफ लगाने के लिए जैसी कवायदें कीं, उनसे साफ हो गया कि अमेरिका उस ग्रंथि से आज तक उबर नहीं सका है। इसी पृष्ठभूमि में पिछले दिनों दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते पर सैद्धांतिक सहमति बनी थी।

सुखद है, इस समझौते की शर्तें अंतिम रूप से तय होने से पहले ही अदालत ने टैरिफ रद्द करने का आदेश दे दिया। यदि वाशिंगटन 'निर्णायक साझेदारी' का पक्षधर है, तो उसे उन रुकावटों को खत्म करना पड़ेगा, जो द्विपक्षीय व्यापार के बढ़ते कदमों को रोकते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप भले ही हमें 'टैरिफ किंग' कहें, लेकिन हमारे द्वारा टैरिफ लगाए जाने के वाजिब तर्क हैं। एक तो हम उभरती आर्थिक ताकत हैं, और फिर लंबे समय तक साम्राज्यवादी ताकतों के अधीन रहे हैं। लिहाजा, सीमा शुल्क या अन्य तरह के शुल्कों का इस्तेमाल हमारी मजबूरी रही है।

ट्रंप यह भी चाहते हैं कि हम रूस से तेल खरीदना कम कर दें, लेकिन जहां से हमें सस्ता तेल मिलेगा, हमें वहीं से इसे खरीदना चाहिए। इसकी दो अन्य वजहें भी हैं। पहली, अमेरिका-ईरान में तनाव बढ़ गया है और कभी भी युद्ध की शुरुआत हो सकती है। अगर ऐसा हुआ, तो क्षेत्र के साथ-साथ तेल का समीकरण भी बिगड़ सकता है। दूसरी, अमेरिका खुद रूस से बातचीत कर रहा है, ताकि यूक्रेन युद्ध का अंत हो सके। ऐसे में, यदि यूक्रेन मोर्चा शांत हो जाता है, जिसकी पैरोकारी भारत भी कर रहा है, तब रूस से दूरी बढ़ाने की नीति हमारे खिलाफ जा सकती है।

ऐसे में, व्यापार समझौते पर नए सिरे से विमर्श की जरूरत है। हमारे पास पर्याप्त समय है कि हम अपने हितों को मजबूती से रख सकें। अमेरिका के घटनाक्रमों से तस्वीर बदल गई है, लेकिन अनिश्चितताएं भी कम नहीं हैं। हमें सोच-विचारकर ही कदम बढ़ाना होगा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मणिपुर में शांति बहाली के लिए सुरक्षा बलों का अनूठा प्रयास

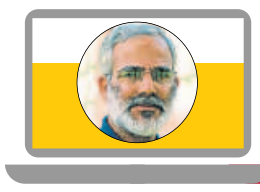

यहां स्कैन करें

शशिधर खान | वरिष्ठ पत्रकार

जातीय हिंसा और तनावग्रस्त मणिपुर में सामाजिक सद्भाव का एक नायाब प्रयास तारीफ के लायक है। असम राइफल्स ने यह प्रयोग 9 से 12 फरवरी तक चार दिवसीय 'सद्भावना फुटबॉल मैच' के माध्यम से किया।

मणिपुर की पहाड़ियों में कुकी-जो और घाटी में मैतेई समुदायों की आबादी ज्यादा है। पहाड़ी में ही मणिपुर की सबसे बड़ी तान्खुन नगा जनजाति के लोग रहते हैं। वे आपस में मेलजोल और एक-दूसरे के घर के आसपास से गुजरने में भी परहेज करते हैं। 3 मई, 2023 से भड़की जातीय हिंसा के बाद से इन समुदायों के युवा घड़ी और टॉर्च लेकर रातभर पहरा देते हैं। हिंसा से सामाजिक जन-जीवन अधिक प्रभावित हुआ है। इस त्रासदी का स्कूली बच्चों के दिलो-दिमाग पर गहरा असर पड़ा है। मैच के दौरान मैदान से सटे राहत शिविर के अंदर कुछ तस्वीरें और पेंटिंग देखी गईं। किसी में एक आदमी पेड़ से लटका था और उसकी गर्दन मरोड़ी हुई थी। एक चित्र में घर जल रहा था, छत से आग की लपटें निकल रही थीं। कुछ पेंटिंग में एके-47 से गोलियां दागी जा रही थीं और चारों ओर खून के धब्बे पसरे थे, लोग जान बचाने को बेहताशा भाग रहे थे। बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए गठित मणिपुर बाल आयोग के अध्यक्ष प्रदीप कुमार के मुताबिक, 10 साल के मैतेई बच्चों ने पेंसिल और स्याही से ये तस्वीरें बनाई थीं, जो उनके मानसिक हालत को दर्शाती हैं।

'सद्भावना मैच' के बाद से हिंसा की कोई खबर नहीं है। आशा की जानी चाहिए कि खेल के जरिये शुरू हुई यह सद्भावना चिरस्थायी हो।

असम राइफल्स के अधिकारियों ने उन जातियों, समुदायों को फुटबॉल मैच के बहाने आपस में मिलवाया, जो एक-दूसरे से लड़ रहे हैं। इस मैच के लिए हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित पहाड़ी इलाके को चुना गया, जहां बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात हैं। कैथेलमन्बी नामक यह गांव इंफाल घाटी और पहाड़ियों के बीच स्थित है और बफरजोन कहलाता है। यह मैदान 'असम राइफल्स फुटहिल्स फुटबॉल टुर्नामेंट' का है और सुरक्षा बल का हथियार भंडार भी इसी में है। मई, 2023 के बाद पहली बार इस चार किलोमीटर के बफरजोन से कुकी खिलाड़ी और कोच असम राइफल्स की बसों में गुजरे। असम राइफल्स ने खिलाड़ियों की भावनाओं का ख्याल करके टीमों का नाम उनके गांवों पर ही रखा था। बफरजोन एक संकरी जमीन की टुकड़ी है, जो मैतेई और कुकी-जो को अलग करती है और हिंसा का केंद्र रही है।

मैच के लिए 13 टीमों में आठ नगा, तीन मैतेई और दो कुकी समुदायों से शामिल की गईं। खिलाड़ियों को उन्हीं बख्तरबंद गाड़ियों में मैदान तक ले जाया गया, जिनमें बिठाकार हिंसा में शामिल संदिग्धों को थाने और हिंसा प्रभावित लोगों को राहत शिविरों या सुरक्षित स्थानों तक ले जाया जाता है।

इस मैच में नगा, मैतेई और कुकी समुदायों के फुटबॉल खिलाड़ी अच्छे माहौल में खेले, मिले, जो गत तीन वर्षों से हिंसा की त्रासदी झेल रहे हैं। *इंफाल प्रेस जर्नल* ने पहले ही असम राइफल्स के अधिकारी की हिंदी में की गई अपील ज्यों-की-त्यों छापी- 'प्रिय खिलाड़ी बंधुओ, खेल की सद्भावना बनाए रखें, रेफरी के निर्णय का पालन करें, खेल का जोश, उत्साह निभाएं।'

असम राइफल्स के वरिष्ठ अधिकारियों ने पहले इन समुदायों की टीमों से संपर्क करके उन्हें अपनी मेजबानी में खेलने के लिए आने को तैयार किया। इसमें टीम के खिलाड़ियों को प्रेम से चेतावनी भी दी गई कि खेल के दौरान या उसके बाद अपने प्रतिद्वंद्वी को किसी भी तरह चोट न पहुंचाएं। ऐसा करने पर तुरंत रेडकार्ड जारी कर दिया जाएगा और पूरी टीम को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। रेफरी का निर्णय अंतिम होगा। रेफरी के लिए सैनिकों को उत्तर-पूर्व के बाहर से बुलाया गया।

सबसे अधिक गौर करने लायक बात रही कुकी गांव लिटान सारेकखोंग से नगा समुदाय के खिलाड़ियों को टीम में लिया जाना। फुटबॉल मैच के समय ही लिटान गांव में तान्खुन नगाओं पर पथराव किया गया और कथित कुकी उग्रवादियों ने उनके कई मकानों में आधी रात को आग लगा दी। उसके जवाब में कुकियों के कुछ मकानों में भी आग लगाने की खबर फैली। 'सद्भावना मैच' के बाद से हिंसा की कोई बड़ी खबर नहीं मिली है। उम्मीद की जानी चाहिए कि खेल के माध्यम से शुरू हुई यह सद्भावना चिरस्थायी होगी।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

मन में उतरना सीखें

बाजार में सब कुछ मिलता है, लेकिन मन की शांति नहीं मिल सकती। कोई अमेजन इसे ऑनलाइन बेच नहीं सकता। आखिर शांति की मांग अचानक क्यों बढ़ गई है? क्योंकि यह विकास का युग है, हर चीज विकसित हो रही है; अच्छा, बुरा, सब कुछ। मजेदार बात यह है कि आदमी का जितना भौतिक और बौद्धिक विकास होता है, उसी मात्रा में मन भी विकसित हो रहा है, मन यानी अशांति।

विकसित मस्तिष्क बहुत ज्यादा सोच-विचार में उलझा रहता है, इसलिए मनोविश्लेषण और तरह-तरह की मानसिक चिकित्साएं खोजी गई हैं। आधुनिक आदमी पुराने आदमी की तरह सीधा सरल नहीं रहा। वह बड़ी जटिलताओं और ग्रंथियों से भरा हुआ है। बीमार है। इधर मनोवैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं मन द्वारा आदमी को शांत करने की। वे कभी भी सफल नहीं हो सकेंगे, क्योंकि शांति मानसिक घटना है ही नहीं।

मन के तल पर ज्यादा से ज्यादा सामंजस्य बिठाया जा सकता है, समायोजन किया जा सकता है। शांति कभी नहीं मिलती। शांति आध्यात्मिक घटना है। इसलिए मन की चाहे कितनी ही व्यवस्था की जाए, ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है कि आदमी अशांति को सहने योग्य बन जाए, लेकिन शांत कभी नहीं बन सकता। मन बना ही है हलचल से, लहरों से, निरंतर उथल-पुथल से। तभी वह जिंदा रहता है। मन का विकास, यानी अशांति का विकास। शांत तो मनुष्य बनता है, आत्मा के तल पर।

मन का स्वभाव समझिए। मन एक क्षण से ज्यादा किसी सुख को अनुभव नहीं कर पाता। वह एक क्षण बीता और सुख दुख में तब्दील हो जाता है। मन के तल पर जो सुख होते हैं, बिल्कुल क्षणिक होते हैं, फौरन डूब जाते हैं और समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए जिस चीज को पाने के लिए हम बिल्कुल पागल होते हैं, अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं और आतुरता से इंतजार करते हैं, वह मुट्ठी में आते ही हम एकदम उदास हो जाएंगे। जैसे, आप एक बहुत बढ़िया मकान खरीदना चाहते हैं। उस आप खरीद लें, तो अचानक यह पाएंगे कि वह पुलक, वह दौड़, वह खुशी, जो पाने की खोज में थी, वह उसके मिलते ही चली गई। जो भी आप पाना चाहते हैं, उसे पाते ही निराश हो जाएंगे, क्योंकि पाने में एक क्षण तो खुशी होगी, और एक क्षण के बाद सब पुराना पड़ जाएगा और और आप फिर उसी उदासी के साये में आ जाएंगे।

मन एक क्षण से ज्यादा किसी सुख को अनुभव नहीं कर पाता। वह क्षण बीता और सुख दुख में तब्दील हो जाता है। मन के तल पर जो सुख होते हैं, फौरन डूब जाते हैं और समाप्त हो जाते हैं।

आजकल हर आदमी शरीर और मन के बीच ही जी रहा है, इसलिए वह हमेशा अशांति में जिएगा। वस्तुतः हमारा अपने साथ संबंध टूट गया है। हम अपने से ही बिछुड़ गए हैं। असली समस्या यह है। थोड़े गहरे प्रवेश करें, खुद के ही भीतर, तो वहां कोई तरंग नहीं। जैसे, समुंदर की गहराई में लहरें नहीं उठतीं, वहां सब निस्तरंग, निस्तब्ध है, वैसे ही मन की गहराई में शांति का निवास होता है।

अमृत साधना

मलाला यूसुफजई | नोबेल विजेता

मैं ईरान की महिलाओं और मानवाधिकारों की अनथक सेनानी नरगिस मोहम्मदी के साथ खड़ी हूं। अब एक और झूठे मुकदमे में उन्हें 17 साल से ज्यादा की कैद की सजा सुनाई जा सकती है।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 23 फरवरी, 1951

रेलवे बजट

रेल मंत्री श्री गोपाल स्वामी आयंगर ने भारतीय संसद के सामने सन् 1951-52 का रेलवे बजट पेश कर दिया। बजट प्रस्तुत करते हुए रेलवे मंत्री श्री आयंगर ने जो भाषण दिया है, वह भारतीय रेलों की सुधरती अवस्था का द्योतक है।... रेल मंत्री ने भारतीय रेलों की मौजूदा स्थिति का जो चित्र प्रस्तुत किया है, उस पर संतोष ही प्रकट किया जा सकता है। सन् 1949-50 में भारतीय रेलों की कुल आय सबसे अधिक रही। रेलों पर यात्रा करने वालों की संख्या भी इतनी रही, जितनी पहले कभी नहीं रही।

सन् 1950-51 में रेलों ने और भी उन्नति की है और यह आशा की जाती है कि अगला वर्ष भी रेलों के लिए सतत प्रगति और समृद्धि का वर्ष साबित होगा।... मुसाफिरों की सुविधाओं में वृद्धि की जा रही है। रेलवे कर्मचारियों और रेलवे प्रबंध के संबंध सौहार्दपूर्ण हैं और दोनों एक-दूसरे की कठिनाइयों को समझने की कोशिश करते हैं। रेलवे प्रबंध की कार्यक्षमता धीरे-धीरे बढ़ रही है और व्यापार और उद्योग तथा यात्रा करने वाली जनता के प्रति रेलवे कर्मचारियों के व्यवहार में अनुकूल परिवर्तन हो रहा है।... भारतीय रेलों की आर्थिक स्थिति ठोस है। सन् 1949-50 में बचत 11 करोड़ 2 लाख होने का अनुमान किया गया था, किन्तु वास्तव में बचत 14 करोड 59 लाख रुपये हुई। सन् 1950-51 के संशोधित अनुमान के अनुसार, जहां बजट-अनुमान की अपेक्षा आय अधिक होगी, वहां खर्च भी बढ़ जायेगा। सन् 50-51 के बजट में 232 करोड़ 50 लाख की आय का अनुमान किया गया था, किन्तु ताजा अनुमानों के अनुसार, आय 263 करोड़ 40 लाख रुपये होगी। दूसरे शब्दों में आय में करीब 31 करोड़ की वृद्धि होगी। खर्च की ओर बजट के मूल अनुमान की तुलना में 13 करोड़ 72 लाख की वृद्धि होगी। चालू वर्ष में भारतीय रेलों का कुल व्यय 180 करोड़ 31 लाख तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है।

रेलवे मंत्री ने खर्च में वृद्धि होने के जो कारण दिये हैं, वे समझ में आने योग्य हैं और इस व्यय-वृद्धि के लिए रेलवे प्रबंध को कोई दोष नहीं दिया जा सकता। चालू वर्ष में रेलें 32 करोड़ 57 लाख रुपये सरकार के सामान्य कोष को देंगी और उन्हें 14 करोड़ 24 लाख की बचत होगी। इसमें से 10 करोड़ रुपये रेलों के विकास कोष में और शेष 4 करोड़ 24 लाख रेलवे रिजर्व फंड में जायेगा।

हर हाल में अमन कायम रहना चाहिए

शांति मन की ऐसी सकारात्मक स्थिति है, जिसमें चिंता, दुख या उद्वेग नहीं होता। यही शांति जब व्यापक राजनीतिक-सामाजिक संदर्भ में प्रयुक्त होती है, तो उसे सामाजिक या विश्व शांति कहा जाता है। इसमें युद्ध, हिंसा या संघर्ष की अनुपस्थिति और दुनिया भर में संवाद और सामंजस्य देखा जाता है। इसके लिए समाज या देशों के बीच हिंसा, युद्ध और डर का न होना तथा सुरक्षा का माहौल जरूरी है।

दुनिया में हर तरह से शांति कायम रहे और विवादों का निपटारा संवाद के जरिये हो, इसके लिए संयुक्त राष्ट्र का गठन किया गया है। अतीत में संयुक्त राष्ट्र से अपने इस मकसद में काफी कामयाबी भी हासिल की है। यह संयुक्त राष्ट्र ही है कि शीत-युद्ध व वैश्विक तनावों के बावजूद तीसरा विश्व युद्ध नहीं छिड़ सका। इस संस्था की कुछ कमजोरियां भी रही हैं, लेकिन कौन सी ऐसी संस्था है, जो कभी किसी मुद्दे पर नाकाम न रही हो। उसका आकलन समग्रता में किया जाना चाहिए और इस कसौटी पर संयुक्त राष्ट्र को उसके पूर्ववर्ती राष्ट्र संघ के मुकाबले काफी सफल और कामयाब ही कहा जाएगा।

विश्व शांति वैश्विक एकता, भाईचारे और आपसी सम्मान पर आधारित होती है। दलाई लामा के अनुसार, सार्वभौमिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करना ही असली शांति के सूत्र हैं। विश्व शांति का मुख्य उद्देश्य सभी प्रकार के तनावों और संघर्षों का अंत, मानवाधिकारों की सुरक्षा और सतत विकास को बढ़ावा देना होना चाहिए। बिहार के राजगीर में रत्नागिरी पर्वत पर स्थित 'विश्व शांति स्तूप' आज भी प्रेम, करुणा और अहिंसा का संदेश पूरी दुनिया को देता है।

विश्व शांति का मतलब केवल युद्ध या हिंसा का अभाव नहीं, बल्कि एक ऐसे समाज का निर्माण है, जहां सभी लोग, देश और संस्कृतियां *वसुधैव कुटुम्बकम्* की भावना से रहते हैं। यह ऐसी स्थिति है, जिसमें मानवाधिकार, सामाजिक-आर्थिक न्याय, शिक्षा और आपसी सहयोग को बढ़ावा देकर हर प्रकार के संघर्ष का अंत किया जाता है। शर्त यह है कि किसी भी परिस्थिति में इस तरह की शांति बनी रहनी चाहिए। विश्व शांति को बढ़ावा देने के लिए मानवाधिकारों की रक्षा, सामाजिक प्रगति और बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यह परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए काम करता है। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में प्रमुख योगदानकर्ता रहा है, जिसके 5,000 से अधिक शांति सैनिक वर्तमान में विभिन्न देशों में तैनात हैं। ऐसे में, उम्मीद यही की जानी चाहिए कि यह वैश्विक संगठन दुनिया में शांति को बनाए रखने में कामयाब होगा।

अमल कुमार, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम

शांति और संयुक्त राष्ट्र

न्याय के बिना इसकी कल्पना बेमानी

दुनिया में शांति बहुत आवश्यक है, लेकिन यह केवल बोलने से या कागजों पर लिख देने से नहीं कायम हो सकती। असल में, विश्व शांति के लिए गंभीर प्रयास की जरूरत है। इसके लिए दुनिया के सभी देशों को सक्रिय होना पड़ेगा और संयुक्त राष्ट्र जैसे वैश्विक संगठनों को शक्ति संपन्न बनाकर उन्हें खुली छूट देनी पड़ेगी।

संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी निभाने वाला संगठन है। इसका मुख्य ध्येय भावी पीढ़ियों को युद्ध की विभीषिका से बचाना और एक सुरक्षित, एकजुट विश्व का निर्माण करना है। आज स्थिति यह है कि विश्व शांति के लिए गठित यह संस्था कई मामलों में नख-दंत विहीन मिट्टी के बाघ जैसी बनी रहती है। वर्तमान में ही देखें, तो यूक्रेन युद्ध, गाजा का संकट, अमेरिका का वेनेजुएला के साथ शर्मनाक व्यवहार आदि अनेक ऐसे उदाहरण हैं, जो विश्व शांति की मर्यादा को तार-तार कर रहे हैं। दुनिया में स्थायी शांति का सबसे प्रामाणिक सूत्र हर समाज में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समानता स्थापित करना हो सकता है। आर्थिक और सामाजिक न्याय के बिना किसी भी प्रकार की शांति केवल तलवार के बल पर स्थापित की जा सकती है। हालांकि, ऐसी शांति कुछ दिन ही बरकरार रह पाएगी।

फिलहाल देखें, तो संयुक्त राष्ट्र विश्व शांति की स्थापना में विफल रहा है। उसकी विफलता का कारण सुरक्षा परिषद में वीटो शक्ति का दुरुपयोग है। इसके अलावा सदस्य देशों के बीच भू-राजनीतिक टकराव और रवांडा-स्रेब्रेनिका जैसे प्रमुख नरसंहारों को न रोक पाना उसकी बड़ी विफलता कही जाएगी। शक्ति संतुलन में बदलाव के बावजूद, 1945 की संरचना पर टिके रहना, कमजोर शांति मिशन और पश्चिमी देशों के प्रभुत्व ने इसकी विश्वसनीयता को गंभीर रूप से कम किया है। कांगो और सोमालिया में शांति सैनिकों पर गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन और यौन शोषण के कारण मिशनों के विफल होने के आरोप हैं। संयुक्त राष्ट्र की नाकामी के पीछे इसका आर्थिक रूप से स्वावलंबी न होना बड़ा कारण है। वह स्वतंत्र रूप से कार्रवाई नहीं कर सकता और सदस्य देशों द्वारा धन व सैनिकों के योगदान पर निर्भर है, जो हमेशा समय पर नहीं मिल पाते।

आज की बदलती दुनिया में भारत, जापान, जर्मनी जैसे देशों को स्थायी सदस्यता में शामिल न करके यह 1945 जैसी स्थिति में बने रहना चाहता है। इससे भी इसकी प्रासंगिकता कम हो रही है। ऐसे में, यह बहुत प्रभावशाली नहीं रह गया है और दुनिया में शांति को तोड़ने वाली शक्तियां अधिक सक्रिय हो रही हैं।

रीना कुमारी, ब्लॉगर

तन को न बनाएं तनाव का घर

हमारा शरीर कई अनकहे, अनसुलझे घावों का चलता-फिरता घर है, जो हमें खुलकर जीने से रोकते हैं। क्या कभी आपने अपनी बेचैनी, बेवजह के गुस्से, नियंत्रण की भावना या शरीर के किसी पुराने दर्द को समझने की कोशिश की है? यह लेख हमें उस यात्रा पर ले जाता है, जहां हम अपने तन से जुड़कर बरसों पुराने अदृश्य बोझ से हमेशा के लिए आजाद हो सकते हैं।

डायना बर्ड
न्यूरो इमोशनल कोच और लेखिका। हानि पहुंचाने वाले इमोशनल पैटर्न को समझने और उनकी हीलिंग पर जोर।

कुछ साल पहले मैं अपनी 'स्त्री शक्ति' को समझने के लिए एक ऑनलाइन कोर्स कर रही थी। बरसों तक बच्चों की परवरिश और कमर के पुराने दर्द की वजह से मैं अपने ही शरीर से कटी-कटी सी महसूस करती थी। उस दिन मैं उत्साहित थी और खुद से दोबारा जुड़ने के लिए तैयार थी।

दोपहर का वक्त था। मैंने एक मधुर पुर्तगाली संगीत लगाया और नाचना शुरू किया। मैं अपनी गरिमा को महसूस कर पा रही थी कि अचानक मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरा रोना रुक ही नहीं रहा था। मेरे भीतर एक गहरा और खौफनाक एहसास जागा- जैसे मैं कहीं भी सुरक्षित नहीं हूं। मैं बुरी तरह डर गई थी। मैंने नाचने की कोशिश की, लेकिन मेरा शरीर कांप रहा था। मेरा मन किया कि बस एक गेंद की तरह सिमट जाऊं और कहीं छिप जाऊं। मैं उलझन में थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्यों रो रही हूं? मेरे पास कोई ऐसी याद या घटना नहीं थी, जिसे मैं उस डर से जोड़ पाती।

तन से जुड़ी मन की सेहत

कुछ समय बाद जब मैंने 'न्यूरो इमोशनल कोचिंग' की ट्रेनिंग ली, तब मुझे समझ आया कि उस दिन क्या हुआ था। मेरी युवावस्था में एक ऐसी घटना घटी थी, जो बहुत दर्दनाक और उलझन भरी थी। मैंने कभी किसी को नहीं बताया। उस वक्त मैं बहुत अकेली थी और गहरे अपराध बोध से भरी थी। मैंने उन भावनाओं को दबा दिया था, लेकिन वह सब एक गहरे सदमे में बदल गया। ट्रॉमा हमारे शरीर में जमा हो जाता है और हमें पूरी तरह आजाद होकर जीने से रोकता है। जब आप इसे पहचानना सीख जाते हैं, तो यह कई रूपों में सामने आता है। ज्यादातर लोग, यहां तक कि दशकों तक मैं भी शरीर में छिपे पुराने जख्म नहीं देख पाती थी।

अक्सर हम ट्रॉमा या सदमे को बड़ी दुर्घटनाओं से ही जोड़कर देखते हैं, लेकिन यह रोजमर्रा की जिंदगी में इन रूपों में भी दिख सकता है :

- कुछ खास स्थितियों या लोगों से हद से ज्यादा बचना
- बिना किसी स्पष्ट कारण के घबराहट या बेचैनी रहना
- शरीर में पुराना दर्द या ऐसी बीमारियां, जिनका इलाज नहीं मिल रहा
- छोटी सी बात पर बहुत तेज गुस्सा या प्रतिक्रिया देना
- अपने ही शरीर में असहज महसूस करना

गहरे सदमों को समझिए

ट्रॉमा किसी ऐसे अनुभव को कहा जाता है, जिससे तीव्र भावनाएं और असहनीय दर्द शामिल होता है। दुख या तकलीफ के ऐसे क्षण, जिन्हें सहते समय आप बिल्कुल अकेले और बेसहारा थे। गैबर मोट कहते हैं, 'ट्रॉमा एक मानसिक घाव है, जो आपको मनोवैज्ञानिक रूप से सख्त बना देता है और फिर आपके विकास में बाधा डालता है। यह आपको दर्द देता है और आप उस दर्द के वश में होकर काम करते हैं। यह डर पैदा करता है और अब आप डर के साए में फैसले लेते हैं। मेरा शरीर उस पुराने दर्द को तिजोरी में बंद किए बैठा था। वह उसे भूला नहीं था, उसे सब याद था।

जब भी मैं अपने शरीर से गहरा जुड़ाव महसूस करती, वह दर्द बार-बार 'असुरक्षा' के एक गहरे एहसास के रूप में सामने आता था। हम अपने शरीर में कहां तनाव और दर्द महसूस करते हैं, यह अक्सर संकेत है कि हमारे अनसुलझे घाव कहां छिपे हैं। जब भी मैं नृत्य करती, गहरे श्वास का अभ्यास करती तो यह दर्द अचानक उभर जाता। पुराने घाव हमारे व्यवहार को कई तरह से प्रभावित कर सकते हैं, जैसे-

- वह व्यक्ति जिसकी मां बहुत बेचैन रहती थी, वह दुनिया में इतना असुरक्षित महसूस करता है कि सब कंट्रोल करना चाहता है।
- वह मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति, जिसका शरीर लगातार दर्द में रहता है, एक बीमारी ठीक होती है, तो दूसरी जगह दर्द शुरू हो जाता है। जिसे बचपन में हमेशा डांटा और कोसा गया है।
- वह महिला जो हमेशा अकेली रहती है, जिसके माता-पिता हमेशा उसे हीन महसूस कराते थे। बाहर से लगता है कि उसे कोई साथी नहीं मिल रहा, पर असल में वह आत्मीयता से बचती है।

मेरे बीते अनुभवों ने कई चीजों में असुरक्षा का अहसास पैदा कर दिया था- हवाई जहाज में उड़ना मुझे घबराहट देता था, कोई भी साहसिक गतिविधि मेरे लिए मना थी। कोई भी ऐसी स्थिति, जहां मुझे लगे, मेरा शरीर मेरे नियंत्रण से बाहर है और कमजोर है, वह मेरे नर्वस सिस्टम को हिला देती थी।

कुल मिलाकर, सदमा वह नहीं है, जो आपके साथ होता है, बल्कि वह है, जो उस घटना के कारण आपके भीतर घटित होता है।

diana-bird.com

शरीर ही है समाधान

हमारा शरीर बीते हुए दर्दनाक पलों की यादों और संवेदनाओं का एक चलता-फिरता बैंक हैं, लेकिन हमारा शरीर वह जगह भी है, जहां हम सबसे गहरी, सबसे तीव्र और मुक्त कर देने वाली आजादी पा सकते हैं।

मुक्ति की राह : जरूरी कदम

- **खुद के प्रति करुणा :** जब पुरानी भावनाएं उभरें, तो उनसे लड़ें नहीं। शांत बैठकर उन्हें महसूस करें और खुद को सांत्वना दें।
- **सोमैटिक हीलिंग :** कभी-कभी दर्द इतना गहरा होता है कि हम अकेले नहीं संभाल पाते। आप उपचार की किसी ऐसी पद्धति के साथ आगे बढ़ें, जो तन और मन के जुड़ाव से जुड़ी हो। किसी अनुभवी या ऐसे व्यक्ति की मदद लें, जो आपको संबल देना जानता हो और आपको भावनात्मक सुरक्षा दे सके, ताकि आप घाव भरने की दिशा में सहजता से आगे बढ़ें। एक सही विशेषज्ञ यह भी समझाएगा कि आपको क्या उम्मीद करनी चाहिए।
- **शरीर से जुड़ाव :** हमारा शरीर ही चाबी है और एक अद्भुत मार्गदर्शक है। शरीर के साथ अपने रिश्ते को दोबारा बेहतर बनाने की शुरुआत शरीर में दबे हुए उस पुराने बोझ को उतारने से होगी, जिसे ढोते-ढोते हम थक चुके हैं। योग, नृत्य, मसाज या गहरी सांस लेने की प्रक्रियाएं दबे हुए भावनात्मक बोझ को बाहर निकालने में मदद करती हैं।

काम की बात

दिमागी बाधाओं को पहचानें

हमारी योजनाओं और फैसलों की हमारी सफलता में बड़ी भूमिका होती है। अक्सर हमारा दिमाग दूर भविष्य की योजनाएं ढंग से नहीं बना पाता। हमारे कुछ पूर्वाग्रह हमें सही फैसले लेने से रोक देते हैं।

छोटे लालच में फंसना

हमारा दिमाग भावी तरक्की की तुलना में वर्तमान के छोटे सुख (जैसे- सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, मोबाइल गेम खेलना, बेकार की बातें करते रहना) को ज्यादा महत्व देता है। भावी लाभ जितना दूर होता है, दिमाग उसे उतनी कम तवज्जो देता है। नतीजा, हम जरूरी कौशल सीखने की बजाय छोटे-छोटे कामों में अपनी ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं।

समय और मेहनत का गलत आकलन

अक्सर हम सोचते हैं कि अमुक विषय को हम तुरंत कर लेंगे, पर उसे समझने में लंबा समय लग जाता है। कई बार हमारा दिमाग जटिल कामों को सरल मान लेता है। इससे शुरुआत में आत्मविश्वास बढ़ जाता है, लेकिन जब काम समय पर पूरा नहीं होता, तो मानसिक तनाव और हार का डर हावी हो जाता है।

एक हार-जीत को सब कुछ मान लेना

जो सोचा है, वो मिल गया, तो हम सातवें आसमान पर होंगे और अगर नहीं मिला, तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हमारा दिमाग किसी एक घटना के भावनात्मक असर को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाता है। इसे 'फोकसिंग इल्यूजन' कहते हैं। हार और जीत के बीच में, जीवन और काम का संतुलन, काम का अच्छा माहौल, मजबूत रिश्ते जैसे असली खुशी देने वाले कारकों को भूल जाते हैं।

दिमाग को ऐसे करें तैयार

- **छोटे लक्ष्य बनाएं :** दिमाग बड़े लक्ष्य नहीं बना पाता, तो उस दिशा में ले जाने वाले छोटे लक्ष्य बनाएं। एक साथ पांच साल की योजना बनाने की बजाय एक महीने की योजना बनाएं। लक्ष्य जितना करीब, दिमाग उतना ही सक्रिय रहेगा।
- **व्यावहारिक लक्ष्य बनाएं :** हवा-हवाई आकलन करने की बजाय यह देखें कि दूसरों को इस तरह का काम करने में कितना समय लगता है या फिर आप आमतौर पर कितना समय लेते हैं। उस हिसाब से उसमें 20 से 30 प्रतिशत अतिरिक्त समय जोड़ें।
- **अपनी खुशी भी देखें :** केवल पद न देखें, बल्कि उस नौकरी में अपनी रोजाना की दिनचर्या को लिखें। क्या आप रोज वही काम करके खुश रहेंगे? वही सफलता लंबे समय तक बनी रहती है, जिसे आपका दिमाग और भावनाएं लंबे समय तक अपना पाती हैं।

पूछें खुद से सवाल

- क्या आपके पास अगले 1 साल के लिए कोई ऐसा लक्ष्य है, जो आज थोड़ा डराता है, पर रोमांचित भी करता है?
- क्या आप अपने दिन का कम से कम 10% समय ऐसे कामों पर लगाते हैं, जो आपको भविष्य में एक बेहतर इंसान या पेशेवर बनाएंगे?
- क्या आपने पिछले 3 महीनों में कोई ऐसी नई बात सीखी है, जो आपके मौजूदा काम या पढ़ाई से बिल्कुल अलग है?
- क्या आपके लक्ष्यों में सेहत, परिवार और मानसिक शांति के लिए जगह है?
- क्या आप किसी नए काम को करने से डरते हैं?

कहीं आप अंदर और बाहर अलग तो नहीं?

कई बार लोगों से मिलने पर यह समझ नहीं आता कि जो वे बाहर से नजर आ रहे हैं, क्या वो भीतर से भी वैसे ही हैं? दूसरों को ईमानदारी का पाठ पढ़ाने वाला व्यक्ति खुद ईमानदारी से कोसों दूर दिखता है। क्या इस बात से हमें फर्क पड़ना चाहिए?

विविध

प्रसिद्ध लेखक सेब हंटर की किताब 'हाउ टु बी अ बेटर पर्सन' में बेहतर इंसान बनने की कई परिभाषाएं हैं। इनमें सबसे ऊपर है, व्यक्ति का एक होना, यानी व्यक्ति बाहर और भीतर से एक हो, उसके अंदर कोई छद्म न हो, वो इतना ईमानदार हो कि जो वो सोचता है, वो कह सके और उस पर अमल भी करे।

सेब अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं, 'आदमी को दुख और निराशा उसकी अपनी वजह से होती है। वह सोचता कुछ और है, करता कुछ और। उसके भीतर स्पष्टता नहीं होती। वह अपने आपको कई खानों में बांट कर जीता है। इससे कई बार वो असंवेदनशील भी हो जाता है। आपके भीतर का गुस्सा सिर्फ आपको नष्ट करता है, दूसरों को नहीं। जिस दिन व्यक्ति अपनी कथनी और करनी में एक हो जाता है, उसे निश्चिंतता मिल जाती है और वो दूसरों की फिक्र करना छोड़ देता है।' सेब अपनी बात समझाने के लिए चींटियों का उदाहरण देते हैं। चींटियों को बस पता होता है कि कहां जाना है और किसके पीछे जाना है। वो अपने काम में माहिर होती हैं। प्रकृति के बनाए जीव-जंतु भी अपने अस्तित्व को ले कर शंका में नहीं रहते। मनुष्य ही है, जो अक्सर अपनी बातों को खुद नकारता है। यह बहुत बड़ी वजह है, दुखी होने और असंतुष्ट रहने की।

अपने अंदर के बच्चे से मिलिए

जन्म के समय बच्चा बिल्कुल निर्मल और निष्पाप होता है। सद्गुरू के अनुसार आत्मा स्वभाव से शुद्ध, निर्गुण और चैतन्य स्वरूप है। आत्मा कभी दूषित नहीं होती, बल्कि हमारे विचार और कर्म उसे अशुद्ध महसूस कराते हैं।

सेब हंटर अपने ब्लॉग में पाठकों से यह सवाल करते हैं कि जब आप मुझे पढ़ रहे हैं, तो क्या आप यह महसूस कर रहे हैं कि आप भीतर से विचलित हैं? चलिए, इस बात पर विचार करते हैं कि यह विचलन क्यों हैं? आप यह सवाल इस क्षण अपने आपसे कीजिए। एक कागज उठाइए और लिखना शुरू कीजिए कि वो कौन-सी वजहें हैं, जो आप अपने भीतर का सच बाहर नहीं ला पा रहे? डर रहे हैं किसी बात पर? असमंजस में हैं? अपने आप से सच नहीं बोलना चाहते या किसी दूसरे की जिंदगी जीना चाहते हैं? आप इन सवालों के जवाब लिखिए, आप खुद हर नए वाक्य के साथ अपने विचारों में स्पष्टता पाएंगे। एक बार तय कर लीजिए कि आप भीतर से जो हैं, जो आपकी अंदर की आवाज है, वो सुनेंगे। इसके बाद आप धीरे-धीरे हर तरफ से वही होते चले जाएंगे, जैसा आप चाहते हैं। अगर आप भीतर से लालची, कपटी और कठोर नहीं हैं, तो बाहर से यह आवरण हटाने में आपको देर नहीं लगेगी।

हाल ही में सद्गुरू ने अपने एक पॉडकास्ट में कहा था कि इंसान इस धरती पर सबसे कठिन प्राणी है, क्योंकि उसके पास दिमाग है, लेकिन 60 प्रतिशत लोग अपने दिमाग का सही इस्तेमाल नहीं करते। मन की सीमाओं के पार जाना, ध्यान, योग और आत्म-शुद्धि से आप आसानी से वो बन सकते हैं, जो आप भीतर से हैं- निर्मल, सकारात्मक और संतुष्ट।

जयंती रंगनाथन

स्पष्टता होनी जरूरी

बिना स्पष्टता के आत्मविश्वास का होना घातक है। आप जैसा सोचते हैं, वैसा ही बन जाते हैं और कार्य करते हैं, क्योंकि विचार ही कर्म में परिणीत हो कर चरित्र और भाग्य का निर्माण करते हैं। आपके मन के निरंतर विचार आपके शब्द, शारीरिक व्यवहार और समग्र व्यक्तित्व को आकार देते हैं, इसलिए सोच अगर स्पष्ट न हो, तो वहां आत्मविश्वास भी किसी काम का नहीं होता।

ओशो कहते हैं, 'आदमी की मुश्किलें तब बढ़ती हैं, जब वो होता कुछ और है और दिखना कुछ और चाहता है। जिस दिन आप यह जान जाओगे कि आप भीतर से क्या हैं, अपने लिए क्या चाहते हैं, इस दुनिया से क्या चाहते हैं, तो आपको बाहर से नकाब ओढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी।'

एकदा

प्रेम की डायरी

विवाह की वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर एक पति-पत्नी ने एक अनूठा निर्णय लिया। संबंधों पर जमती शिकायतों की धूल साफ करने के लिए पत्नी ने प्रस्ताव दिया, 'हम साल भर एक-दूसरे की कमियां दो अलग डायरियों में लिखेंगे और अगली वर्षगांठ पर उन्हें पढ़ेंगे, ताकि हम खुद को सुधार सकें।' पति सहमत हो गया।

साल बीत गया। अगली वर्षगांठ पर दोनों डायरियां लेकर बैठे। पति ने पत्नी की डायरी पढ़नी शुरू की। उसमें शिकायतों की लंबी फेहरिस्त थी- 'आज आपने पसंदीदा फिल्म नहीं दिखाई', 'आज मायके वालों से ठीक से बात नहीं की', 'बाहर ले जाने का वादा करके भी नहीं ले गए।', 'आज उपहार अच्छा नहीं था' ऐसी ही कई बातें उसमें लिखी थी।

पति की आंखें भर आईं। उसने वादा किया कि वह इन गलतियों को नहीं दोहराएगा। अब पत्नी ने पति की डायरी खोली। वह हैरान रह गई। पहला पन्ना कोरा, दूसरा कोरा... पूरी डायरी कोरी थी! पत्नी ने उलाहना दिया, 'क्या तुम मेरी इतनी इच्छा भी पूरी नहीं कर सके? इतनी भी मेहनत नहीं कर सके?'

पति ने मुस्कराते हुए कहा, 'अंतिम पन्ना पढ़ो।' उस पर लिखा था, 'मुझे तुम्हारे असीमित प्रेम और त्याग के सामने तुम्हारी कोई कमी लिखने लायक नहीं लगी। ऐसा नहीं कि तुममें कोई त्रुटि नहीं है, पर तुम्हारा समर्पण उन सबसे कहीं ऊपर है। तुम मेरी छाया हो और अपनी ही छाया में भला कोई दोष कैसे ढूंढ़ सकता है?'

पत्नी की आंखें नम हो गईं। उसने दोनों डायरियां और सारे गिले-शिकवे स्वाहा कर दिए। उनका जीवन फिर से एक नव-विवाहित जोड़े की तरह प्रेम से महक उठा।

रोजनामचा

पं. राघवेन्द्र शर्मा
ज्योतिषाचार्य

स्कैन करें
भविष्यफल और व्रत-त्योहार जानने के लिए

मेष : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। मन प्रसन्न रहेगा। कारोबार के लिए विदेश यात्रा पर जा सकते हैं। किसी मित्र का सहयोग भी मिल सकता है। आय में वृद्धि होगी।

वृष : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। किसी मित्र के सहयोग से नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। कार्यक्षेत्र में वृद्धि होगी। आय बढ़ेगी। सेहत का ध्यान रखें।

मिथुन : मन प्रसन्न रहेगा। आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। सेहत के प्रति सचेत रहें। बातचीत में संतुलित रहें। परिवार का साथ मिलेगा। कारोबार में बढ़ोतरी होगी।

कर्क : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। मन परेशान हो सकता है। संयत रहें। धैर्यशीलता बनाए रखें। नौकरी में कार्यक्षेत्र में वृद्धि के साथ स्थान परिवर्तन हो सकता है।

सिंह : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, पर मन परेशान हो सकता है। संयत रहें। परिवार की सेहत का ध्यान रखें। पिता का साथ मिलेगा। खर्चों में वृद्धि होगी।

कन्या : मन परेशान रहेगा। आत्मविश्वास में कमी रहेगी। धैर्यशीलता बनाए रखें। कारोबार में बाधा का सामना करना पड़ सकता है। खर्चों में वृद्धि होगी।

तुला : मन प्रसन्न रहेगा। आत्मविश्वास भी भरपूर रहेगा। माता की सेहत का ध्यान रखें। परिवार का साथ मिलेगा। मित्रों के सहयोग से कारोबार में वृद्धि हो सकती है।

वृश्चिक : मन परेशान हो सकता है। सेहत का ध्यान रखें। कारोबार में भागदौड़ अधिक रहेगी। लाभ के अवसर भी मिलेंगे। किसी मित्र का सहयोग मिल सकता है।

धनु : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, मन में उतार-चढ़ाव रहेंगे। नौकरी में बदलाव के साथ तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। कार्यक्षेत्र में बदलाव हो सकता है।

मकर : आत्मसंयत रहें। क्रोध के अतिरेक से बचें। जीवन साथी की सेहत में सुधार होगा। किसी मित्र के सहयोग से किसी नए कारोबार की शुरुआत हो सकती है।

कुंभ : मन परेशान हो सकता है। पिता की सेहत का ध्यान रखें। परिवार का साथ मिलेगा। शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी। बौद्धिक कार्यों से आय में वृद्धि हो सकती है।

मीन : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। धैर्यशीलता में कमी हो सकती है। किसी पैतृक संपत्ति से धन की प्राप्ति हो सकती है। नौकरी में स्थान परिवर्तन का योग है।

व्रत और त्योहार | पंचांग | पं. ऋभुकांत गोस्वामी

23 फरवरी, सोमवार, **शक संवत्:** 04 फाल्गुन (सौर) 1947, **पंजाब पंचांग:** 05 फाल्गुन मास प्रविष्टे 2082, **इस्लाम:** 05 रमजान, 1447, **विक्रमी संवत्:** फाल्गुन शुक्ल षष्ठी तिथि प्रात: 09.10 बजे तक पश्चात सप्तमी तिथि, भरणी नक्षत्र सायं 04.34 बजे तक, तैतिल करण। चंद्रमा मेष राशि में रात्रि 10.13 बजे तक उपरांत वृष राशि में।

सूर्य उत्तरायण। सूर्य दक्षिण गोल। शिशिर ऋतु। प्रात: 07.30 मिनट से प्रात: 09 बजे तक राहुकालम्।

वास्तु सलाह | आचार्य मुकुल रस्तोगी

मेरे बनते हुए काम बहुत बिगड़ते हैं। बहुत परेशान रहता हूं।

-विनय कुमार, धनबाद

- घर की पूर्व दिशा में रखा हुआ सरसों के तेल का डिब्बा हटा दें।
- थोड़ी देर के लिए नियमित रूप से घर के किसी अंधेरे कोने में बैठें।
- उत्तर पश्चिम दिशा में एक चांदी का घोड़ा रखें।
- दक्षिण दिशा में एक कोई भी मेटल का सामान रखें।
- पूर्व दिशा में एक कांच के कटोरे में हरी मूंग रखें। घर की दक्षिण दिशा में एक लाल कपड़े में नारियल बांधकर किसी ऊंचे स्थान पर चार दिनों तक रखें।

वर्ग पहेली : 8249

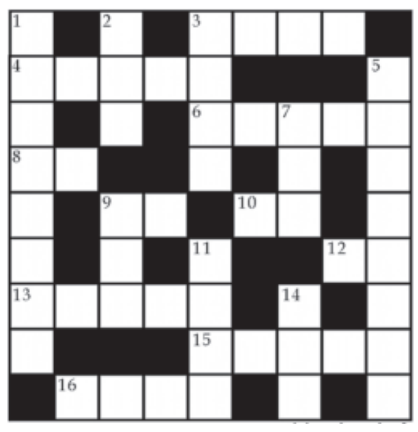

बाएं से दाएं
3. रेशेदार पौधा जिससे बोरियां बनती हैं (4)
4. जताने वाला; परिचय कराने वाला; सूचक (5)
6. वात के अनुकूल; वात नियंत्रण (5)
8. काया; शरीर; देह (2)
9. आंच; ऊष्णता; गरमी; जलन; ज्वर (2)
10. सलाद या सब्जी बना कर खाया जाने वाला सफेद कंद जिसके हरे पत्ते भी खाए जाते हैं; एक प्रकार का बांस; एक प्रकार की जड़ी-बूटी; मूलिका; ज्येष्ठी (2)
12. अन्न जिसे सब्जी की तरह पका कर रोटी या चावल खाया जाता है (2)
13. गंदा होना; गलना; बुरा होना; सड़ना (3,2)
15. पालने वाला; परमात्मा (5)
16. आकाशीय; आसमान का; आकाश के रंग का; हल्का नीला; ईश्वरीय; किसी प्रकार का नशा (4)

ऊपर से नीचे
1. किसी को न बताना; भेद न खोलना; रहस्य रखना (3,2,3)
2. अलग रखना, छिपाना; हटाना; खर्च न करना; जोड़ना (3)
3. रंधवाना; तैयार करवाना; परिपक्व कराना (4)
5. एक दल को छोड़ कर दूसरे दल में जाना (5,3)
7. तीखे कोने वाली; तेज चोंच वाली; नोक वाली (3)
9. जलाशय; सरोवर (3)
11. अन्न-जल; खाना-पीना (2,2)
14. मुंह; मुख (3)

हरीश चन्द्र सन्सी, विविधा विधा, दिल्ली
(उत्तर अगले अंक में)

वर्ग पहेली : 8248

सुडोकू : 8231

* मध्यम

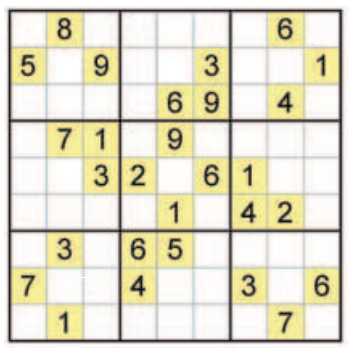

खेलने का तरीका : दिमागी खेल और नंबरों की पहेली है यह। ऊपर नौ-नौ खानों के नौ खाने दिए गए हैं। आपको 1 से 9 की संख्याएं इस तरह लिखनी हैं कि खड़ी और पड़ी लाइनों के हरेक खाने में 1 से 9 की सभी संख्याएं आएं। साथ ही 3×3 के हरेक बक्से में भी 1 से 9 तक की संख्याएं हों। पहेली का हल हम कल देंगे।

सुडोकू : 8230

5	4	6	1	8	3	7	2	9
3	7	9	5	6	2	8	1	4
1	8	2	4	7	9	5	3	6
4	3	8	9	2	6	1	7	5
7	2	5	8	4	1	9	6	3
9	6	1	3	5	7	4	8	2
8	1	3	6	9	5	2	4	7
6	5	7	2	1	4	3	9	8
2	9	4	7	3	8	6	5	1